हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

18 मार्च, 2016

खण्ड-1, अंक-6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 18 मार्च, 2016

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)1
गोस्वामी गणेश दत्त एस0डी0 कॉलेज सैक्टर–32, चण्डीगढ़ के अध्यापको एवं विद्यार्थियों/अति विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत	(6)8
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(6)8
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(6)18
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)27
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव– हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्ज सम्मिट के संबंध में	(6)35

मूल्य :

वक्तव्य–
उद्योग मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (6)36

सदन के कार्य में परिवर्तन करना (6)65

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (6)65

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा (6)77

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (6)77

पंजाब विधान सभा द्वारा पारित किए गए निंदा प्रस्ताव के संबंध में मामला उठाना (6)79

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (6)79

बैठक का समय बढ़ाना (6)89

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (6)89

बैठक का समय बढ़ाना (6)96

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ) (6)97

वर्ष 2015–16 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना (6)100

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना (6)100

वर्ष 2015–16 के अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (6)100

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 18 मार्च, 2016

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

To open a College

*** 1262. Shri Bhagwan Dass Kabir Panthi :**Will the Education Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the foundation stone of a college was laid down in Taraori Town during the financial year 1995-1996 by the then Chief Minister but the work has not been started thereon so far; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to open the abovesaid college in Taraori city in near future; if so, the present status of the construction work of the building of the college?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा)

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) नहीं, श्रीमान जी; इसलिए प्रश्न का यह अंश उत्पन्न ही नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूँ कि एक राजकीय महाविद्यालय करनाल में है, एक राजकीय महाविद्यालय घरौंडा में है, एक राजकीय महाविद्यालय मटक माजरी में है और एक राजकीय महाविद्यालय असंध में भी है और ये सभी तरावड़ी के नजदीक हैं। जहाँ तक शिलान्यास की बात है तो 1995-96 में तरावड़ी में किसी महाविद्यालय का शिलान्यास नहीं हुआ।

श्री भगवान दास कबीरपंथी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि 1995-96 नहीं तो इसके आसपास ही तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था और वह पत्थर आज भी वहाँ पर लगा हुआ है तथा उसके लिए 12 एकड़ जमीन छोड़ी हुई है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 3-4 कस्बे नीलोखेड़ी, तरावड़ी और निसिंग हैं जो करनाल से 25-30 किलोमीटर दूर पड़ते हैं तथा बड़ी संख्या में बहन-बेटियों को परेशान होना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि तरावड़ी में महाविद्यालय खोलने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इस महाविद्यालय को बनाया जाये।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री भगवान दास कबीरपंथी जी का अंदाजा सही है। कुछ सरकारें तो पत्थर लगाने वाली ही सरकारें थी और चुनाव से 3-4 महीने पहले तो अंधाधुंध पत्थर लगाये गये थे। अध्यक्ष महोदय, बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत महिला महाविद्यालय खोलना सरकार की प्राथमिकता है इसलिए अगर माननीय साथी विधायक जमीन उपलब्ध करवा दें या कोई भवन उपलब्ध करवा दें तो हम इसको इग्जामिन करवा लेंगे।

श्री भगवान दास कबीरपंथी : अध्यक्ष महोदय, 12 एकड़ जमीन पहले ही कॉलेज के नाम दी हुई है।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में लखनौर साहिब नाम का एक गांव है। उसका ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि वह श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी का ननिहाल है। वहाँ पर 30 साल पहले पूर्व मंत्री सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा द्वारा कॉलेज का शिलान्यास किया गया था और आधा एकड़ में उसकी नींव आज भी भरी हुई है। इसके लिए गांव की तरफ से 15 एकड़ जमीन शिक्षा विभाग के नाम कर दी गई थी। 30 साल बाद भी आज तक उस पर एक भी ईंट नहीं लगी है। वहाँ पर कोई काम न होता देख अब गांव वालों ने तंग आकर कोर्ट में केस डाल दिया कि अगर विभाग ने इस जमीन पर कुछ नहीं बनाना तो हमारी जमीन वापिस की जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे पूछना भी चाहता हूं कि आगे निकट भविष्य में क्या कोई प्रावधान है कि वहां पर कॉलेज खोला जा सके। गुरू गोबिन्द सिंह जी का सिख इतिहास में और भारत के इतिहास में बड़ा स्थान है। हमारी यह इच्छा है कि उस गांव को कोई पहचान दिलाने के लिए गुरू जी के नाम से वहां कोई यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च का इंस्टीट्यूट खोला जाए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री असीम गोयल जी का यह कहना बिल्कुल सही है कि लखनौर साहिब के नाम से इस गांव का बड़ा महत्व है हम इस गांव को तीर्थ के नाते मानते हैं। गुरू गोविन्द सिंह जी के प्रकट उत्सव पर हजारों की संख्या में लोग वहां आते हैं। पिछली सरकार के समय वहां पर पत्थर लगाने की जहां तक बात है उस समय इस गांव के लिए कोई आर्थिक सैंग्शन नहीं दिया गया इसलिए अब हम इसको बड़ी गम्भीरता से ले रहे हैं। आने वाले समय में गुरू गोविन्द सिंह जी की समृति में एक महाविद्यालय के लिए इस बजट के माध्यम से आने वाले वर्ष में इस पर कार्रवाई करेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री श्याम सिंह राणा) : अध्यक्ष महोदय, इसी सवाल से संबंधित मेरा भी एक सवाल है जिसके लिए मैं भी मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रादौर गांव में भी 11-12 एकड़ जमीन कॉलेज बनाने के लिए छोड़ी हुई है जो सरकार की तरफ से भी उस बारे में सैंग्शन हो चुकी है तो उस कॉलेज को इस वर्ष से चालू करने का क्या कोई प्रावधान है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्लियामैंट सैक्रेटरी श्री श्याम सिंह जी राणा तो खुद सरकार हैं उनकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे।

श्रीमती नैना चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लड़कियों की समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूं कि मेरे हल्के डबवाली में एक रामगढ़ गांव है और

चकजालू गांव हैं उन दोनों गांवों में केवल एक किलोमीटर की दूरी है और वहां पर आठवीं कक्षा तक का स्कूल है जिसके कारण उन दोनों गांवों की लड़कियों को उनके अभिभावक कहीं और पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं क्योंकि वहां पर परिवहन की सुविधा भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उन दोनों गांव के स्कूल्ज में से एक स्कूल को 10 वीं या 12 वीं कक्षा तक अपग्रेड किया जाए ताकि उन दोनों गांव की लड़कियां भी आगे पढ़ाई कर सकें क्योंकि "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" आपका बहुत बड़ा अभियान है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय बहन नैना चौटाला जी से यह कहना चाहता हूं कि यह इनके क्षेत्र का जो रामगढ़ गांव है उसमें ये स्कूल का दर्जा बढ़वाना चाहती हैं। आप हमें वहां के सारे नॉर्म्ज लिख कर दे दें उस पर हम जरूर विचार करेंगे।

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सबको पता है कि 21 फरवरी को मेरे हल्के के एक कैप्टन पवन कुमार जी की शहादत हुई थी तो कम से कम 20 गांवों के लोगों ने लिख कर दिया हुआ है कि उनके नाम पर कोई मेडीकल कॉलेज, एन.आई.टी., टैक्नीकल यूनिवर्सिटी खोली जाए जिसके लिए वहां के गांवों के लोग फ्री ऑफ कोस्ट अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाहती हूं कि कैप्टन पवन की शाहदत के लिए हमारे विधायक श्री सुभाष बराला जी, श्री ओम प्रकाश धनखड़, जी भी आए थे तो मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी इस पर गौर करें।

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, कैप्टन पवन खटकड़ अविवाहित थे और उसके माता-पिता दोनों नौकरी करते हैं मेरा निवेदन है कि उसके परिवार में से किसी को नौकरी भी दी जाए और उसके नाम को अमर रखने के लिए बहन प्रेमलता जी ने जो सुझाव दिया है मुझे लगता है कि इस बात के लिए पूरा सदन इनके साथ होगा। मैं भी चहाता हूँ कि उनके नाम पर कोई अच्छा इंस्टीच्युट जरूर बनाया जाए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी ने भी लिख कर दिया, कैप्टन अभिमन्यु ने भी लिख कर दिया है। पवन खटकड़ की माता जी हमारे विभाग में अध्यापिका हैं और उनके पिता जी भी शिक्षा विभाग में हैं और उनकी समृति को अमर रखने के लिए हम निश्चित रूप से पवन के नाम से कोई संस्था बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पवन जी ने जो अन्तिम एस.एम.एस. अपने भाई को किया वह बड़ा प्रेरणादायक है। उनको मालूम था क्योंकि पवन खटकड़ सुसाईडल सकैव्ड का मुखिया था। कश्मीर में तैनात हमारे जाबांज सैनिक आतंकवादियों की टोह के लिए दाड़ी बढ़ाकर व नाम बदलकर रखते हैं। पवन खटकड़ को खान बोस के नाम से जाना जाता था। पहले भी उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था उसमें वह शहादत से बच गये थे। इस बार भी बहुत खतरनाक काम उनके जिम्मे दिया गया था। पवन अविवाहित था। जिस प्रकार जब राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था तो उन्होंने बोला था कि:

मरते बिस्मिल, रोशन लहरी अस्फाक अत्याचार से,
पैदा होंगे हजारों - हमारे खून की धार से।

[श्री राम बिलास शर्मा]

उसी तरह से शेर दिल पवन खटकड़ के सामने जब मौत खड़ी थी तो अन्तिम सांस के वक्त उन्होंने अपने भाई को एस.एम.एस. किया कि:-

ना आजादी चाहिए, ना आरक्षण चाहिए,
यहां तो केवल- एक रजाई चाहिए।

यह उनके आखिरी शब्द थे और वह शहीद हो गये। ऐसे अमर शहीद को हम नमन करते हैं और उनकी स्मृति को अमर करने के लिए जिसके बारे में मैडम प्रेम लता जी ने तथा दूसरे अन्य सदस्यों ने बात कहीं है की उनकी स्मृति में एक संस्था का निर्माण किया जाये, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चय ही उनकी स्मृति में एक बहुत ही बढ़िया व अच्छी संस्था का निर्माण किया जायेगा। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री असीम गोयल जी के जवाब में शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी ने लखनौर साहिब में शायद गुरू गोबिन्द सिंह जी की स्मृति में महाविद्यालय बनाने की बात की है। गुरू गोबिन्द सिंह जी की कुर्बानी का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। लोग उन्हें सरबंशदानी के नाम से भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से केवल यही स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जो लखनौर साहिब में कॉलेज बनेगा क्या उसे गुरू गोबिन्द सिंह जी के नाम से बनाया जायेगा।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस कॉलेज को गुरू गोबिन्द सिंह जी की स्मृति में बनाया जायेगा।

To Metal the Unmetalled Passages

*** 1314. Dr. Pawan Saini :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether it is a fact that there are many unmetalled passages having the size of 4 and 5 karams in the state; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the abovesaid unmetalled passages; if so, the time by which these passages are likely to be metalled?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हाँ, श्रीमान जी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार मौके पर जहां रास्ते की चौड़ाई कम हो, वहां साथ लगती भूमि के मालिकों से अतिरिक्त भूमि मुफ्त में उपलब्ध कराई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, विधायक डॉ पवन सैनी जी ने चार तथा पांच करम के आकार के कच्चे रास्तों का जिक्र किया है और पूछा है कि क्या इन रास्तों को पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा पक्का किये जाने की कब तक सम्भावना है। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार यदि मौके पर रास्ते की चौड़ाई कम हो तो रास्ते के साथ लगती हुई भूमि मालिकों से अतिरिक्त भूमि मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा सकती है। जैसाकि विधायक जी ने अभी पूछा है कि क्या कोई पार्टिकुलर रास्ते ऐसे

हैं जो मंडी तक का जाने का रास्ता कम करेंगे तो उस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि सामान्यत: मार्किटिंग बोर्ड ऐसे रास्ते बनाता है जो मंडी तक पहुंचाते हों और इन रास्तों को बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मंडी पहुंचने का रास्ता छोटे से छोटा हो ताकि किसानों के समय व धन की बचत हो सके। सामान्यत: छह करम के रास्ते बनाये जाते हैं लेकिन अपवाद स्वरूप पहले कुछ ऐसे रास्ते पांच करम के भी बनाये हुए मिले है। रास्ता चौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमारी यही कोशिश होती है कि रास्ते के आस-पास की जमीन मिल जाए।

डॉ पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से डेरे हैं जहां लोग गांव से जाकर उन डेरों में बस गये हैं। गांव से डेरों तक जाने वाले रास्ते पांच करम के हैं इसके अतिरिक्त ऐसे भी बहुत से रास्ते हैं जो एक गांव को दूसरे गांव के साथ जोड़ते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे रास्तों को प्राथमिकता के आधार पर पक्का करवा दिया जाये तो आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी होगी।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि महेन्द्रगढ़ जिले में जितने भी इंटर विलेज रास्ते हैं उनकी चौड़ाई चार करम से ज्यादा कहीं पर भी नहीं है। मैं ढ़ाणियों की बात नहीं कर रहा हूँ काफी बड़े गांव ऐसे हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं और आठ-दस किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर लोगों को इन गांवों में पहुंचना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह यदि अपने महकमे के द्वारा इसकी जांच करवाकर कोई समाधान निकलवा दें तो इन गांवों के लोगों को बहुत फायदा होगा।

श्री बलवंत सिंह सढ़ौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पांच या छह करम का रास्ता तो कोई है ही नहीं। पिछली सरकार ने पता नहीं क्यों छह करम के रास्तों को पक्का करने का कानून बनाया है। हमारे किसी भी जिले में चार करम का रास्ता नहीं है। इसलिए इस कानून में अमेंडमेंट करके चार करम के रास्तें को पक्का बनाया जाये।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में गांव सोथा से खेड़ी जालब मण्डी, गांव सुंधोल से बालक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला की सुसराल के गांव कुलेरी से खारा खेड़ी तक रास्ता लगभग 5-6 करम का है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इन रास्तों को पक्का किया जाये।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जमीन कम है। होल्डिंग कम होने के कारण चकबन्दी में रास्ते कम छोड़े गए हैं। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी से पता चला है कि ये सड़कें हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड बनाता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि रेवाड़ी के पूर्व मंत्री ने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने खेतों तक 5 करम के रास्ते पक्के बना लिए और बाकी रास्ते छोड़ दिए थे। (विघ्न) क्या माननीय कृषि मंत्री जी बिना किसी निष्पक्षता से हमारे भी इन रास्तों को पक्का बनवायेंगे (विघ्न) ताकि सभी लोगों को इसका लाभ हो सके? (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री अनूप सिंह जी ने हाउस में बताया है कि एक गांव तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला की सुसराल कुलेरी गांव से संबंधित है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उस गांव का चाहे किसी भी करम का रास्ता हो उसे हम जरूर पक्का बनवायेंगे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, डॉ० पवन सैनी के विषय को बड़े ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि 186 रास्ते कुरूक्षेत्र में बने हुए हैं और 191 रास्ते यमुनानगर यानी आपके जिले में बने हुए हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो यमुनानगर के बाद कुरूक्षेत्र का नाम आता है। इनका निर्वाचन क्षेत्र सारे हरियाणा में सबसे आगे है। इनके क्षेत्र में ऐसे 63 मार्ग बने हुए हैं। पता नहीं किस कारण से इनके बुजुर्गों ने ये रास्ते कम चौड़े क्यों बनवाए हुए हैं। जिस रास्ते से दो ट्रेलियां एक-साथ न निकल सकें वहां पर जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये रास्ते अनाज को गांव से मंडियों तक पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। इन रास्तों से ट्रैक्टर-ट्रॉली की आवाजाही ज्यादा होती है। इनके लिए नियम तो 18 फुट का रास्ता बनाने का ही है। यदि हम कहीं पर इससे कम चौड़ाई का रास्ता बनाने के लिए अनुमति दे देते हैं तो तुरंत लोगों की शिकायतें आती हैं कि आप दूसरे रास्तों को भी चौड़ा करवा दीजिए। हमें रास्तों का निर्माण भविष्य को दृष्टि में रखते हुए ही करना पड़ता है। शुरू में जब चण्डीगढ़ का निर्माण हुआ था तो इसे बहुत योजनाबद्ध ढंग से बनाया गया था परंतु आज यहां भी काफी भीड़ देखने को मिलती है और यहां की गलियों में एक-साथ दो गाड़ियां निकलनी मुश्किल हो गई हैं। इस युग की मांग है कि हम रास्ते चौड़े ही बनवाए। इसलिए मेरे विचार से हमारी प्राथमिकता किसानों को जमीन देने के लिए कन्वींस कराकर रास्ते चौड़े ही बनाने चाहिएं। अगर कहीं कम चौड़े रास्तों की जरूरत होगी तो हम उन्हें अपवाद रूप में अवश्य बना देंगे। हमने इस तरह के 726 रास्ते अपवाद के रूप में पहले भी बनाए हैं। अगर हमें इन रास्तों को बनाने के लिए कहीं से जानकारी मिलेगी तो हमें ये संकरे रास्ते बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सदन से अनुरोध है कि इन संकरे रास्तों के निर्माण को अपवाद ही रहने दिया जाए। हमारी कोशिश समय को देखते हुए चौड़े रास्ते बनाने की ही होनी चाहिए। दूसरा, जो रास्ते डेरों और गांवों को आपस में जोड़ने वाले हैं उनको बनाने का काम मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत आता है। ये रास्ते गांव को मंडियों से जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत या पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा या अन्य किसी विभाग के द्वारा डेरों और गांवों को आपस में मिलाने के लिए जरूर इन रास्तों को बनाया जाना चाहिए। जिन माननीय सदस्यों ने हमसे रास्ते बनाने की मांग की है हमारा पूरा प्रयास इन रास्तों को बनाने के लिए रहेगा।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मैं भी प्रदेश का कृषि मंत्री रह चुका हूँ। मार्केटिंग बोर्ड कृषि विभाग के अंतर्गत ही आता है। हमने अपनी सरकार के समय 4,600 किलोमीटर लम्बे गांव से गांव को जोड़ने वाले मार्ग बनाए थे। मंत्री जी ने अभी 3 और 4 करम के रास्ते बनाने की मांग को स्वीकार किया है। मेरा अनुभव है कि जब व्यक्ति की किसी काम को करने की नीयत सही होती है तो वह काम हो ही जाता है। वर्ष 1955-56 में ज्यादातर रास्ते 3 या 4 करम या 16.5 फुट के ही काटे गए थे। हमने भी अपनी सरकार में किसानों की जमीन को मार्केटिंग बोर्ड के नाम नहीं करवाया था। हमने किसानों को कहा था कि आप एफिडेविट दे दो कि हम यह रास्ता बनाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। इस तरह से हमने एफिडेविट लेकर 3 और 4 करम के रास्ते बनाए थे। दूसरा रास्ता यह है कि आप एक बिल लाकर किसानों से जमीन एक्वॉयर करके रास्ते बना लो लेकिन यह रास्ता ठीक नहीं

है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि जिस जगह भी किसान यह एफिडेविट दे दें कि मुझे रास्ता बनाने के लिए जमीन देने में एतराज नहीं है आप वहां रास्ता जरूर बनवाएं। किसानों को अपना अनाज खेतों से मंडियों में पहुंचाने के लिए इन रास्तों की बहुत जरूरत है। बहुत-से किसान ढ़ाणियों और डेरों में रहते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए और बीमार होने पर अस्पताल तक पहुंचाने के लिए सड़कें होना जरूरी है। कच्चे रास्तों से उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंत में मेरा मंत्री जी को यही सुझाव है जहां भी किसान जमीन देने के लिए एफिडेविट दे दे आप वहां 3 और 4 करम के रास्ते जरूर बनवाएं।

Reconstruction of School Building

*** 1134. Shri Ved Narang :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is a fact that the building of Primary School situated in Ward No. 17 Vikas Nagar of Barwala city had been demolished for reconstruction; if so, the time by which the construction work of the building of said school is likely to be completed togetherwith the details thereof?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हाँ, श्री मान जी। अगले वित्तीय वर्ष में इसके निर्माण हेतु राशि का प्रावधान करने बारे विचार किया जाएगा।

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने इस बिल्डिंग के निर्माण करने के लिए सिर्फ विचार करने का आश्वासन दिया है। जब इस स्कूल की इमारत को नाकारा घोषित किया गया था तो उस समय इस स्कूल में 493 बच्चे पढ़ते थे। आज मजबूरन उन छात्र-छात्राओं को शहर से 3 किलोमीटर दूर गवर्नमैंट सीनियर सैंकेडरी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है और उस स्कूल में बच्चों की संख्या घटकर 260 रह गई है। यह रास्ता सूनसान पड़ता है जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग पर विचार न करके इसको बनाने बारे सुनिश्चित किया जाए।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी वेद नारंग जी का कहना सही है कि इस विद्यालय की जो इमारत थी उसको असुरक्षित समझते हुए यहां के बच्चों को अनाज मंडी में स्थित इमारत में शिफ्ट किया गया। अनाज मंडी के इस भवन की इमारत ठीक थी इसलिए यहां शिफ्ट किया जाए। उस समय बच्चों की संख्या 469 थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हम अब दोबारा से इस इमारत का निर्माण करके इस विद्यालय को यहां शिफ्ट करने बारे विचार करेंगे।

श्री रणधीर कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी में एक उच्च कन्या महाविद्यालय है जिसकी इमारत इतनी जीर्ण है कि वह कभी भी गिर सकती है। इस स्कूल में कन्याओं की संख्या 2600 है। हमने पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से निवेदन किया था कि आप भी मौके पर जाकर इस स्कूल को देखकर आओ। मेरे कहने का अभिप्राय है कि यह मसला प्रशासन की नोलेज में है। उन्होंने इस बारे लिखित कार्रवाई भी कर दी है। मैंने इस बारे में पहले भी कहा था और अब भी मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस स्कूल की इमारत का निर्माण करवाया जाए क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है और हादसा होने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी शहर का यह सबसे बड़ा विद्यालय है। माननीय साथी रणधीर कापड़ीवास जी के आग्रह पर हम वहां गए थे। मंत्री नरबीर सिंह जी और मैं एक बार वहां से गुजरते हुए इस विद्यालय को देखकर आए थे, मैंने स्वयं एक घंटा लगाकर इस स्कूल के एक-एक कमरे को देखा है इसलिए हम इसकी इमारत को बनाने पर विचार कर रहे हैं।

गोस्वामी गणेश दत्त एस.डी.कॉलेज, सैक्टर 32, चण्डीगढ़ के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत/अति विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि गोस्वामी गणेशदत्त एस.डी. कॉलेज, सैक्टर-32, चंडीगढ़ के छात्र और अध्यापकगण इस सदन की कार्यवाही को देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से और पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आज भारत सरकार के केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी भी हमारे सदन की कार्यवाही को देखने के लिए उपस्थित हैं , हम उनका भी स्वागत करते हैं। पिछली बार हमने चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी के जन्मदिवस पर बहन प्रेमलता जी को गांव अलेवा का कॉलेज बधाई में दिया था। आज कप्तान पवन खटकड़ जो शहीद हुए हैं और जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है , उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए एक बड़ा शिक्षण संस्थान हमने प्रेमलता जी को, सुभाष बराला जी को और कैप्टन अभिमन्यु जी के एरिया को दिया है।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To Start Government Girls College at Kalayat

*** 1124. Shri Jai Parkash :** Will the Education Minister be pleased to state whether Kapilmuni Education Society of Kalayat Distt Kaithal has offered any land to Department of Education or to the District Administration for starting a Girls College; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to start a Girls College on the abovesaid land togetherwith the details thereof?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी; इसलिए प्रश्न का यह अंश उत्पन्न ही नहीं होता।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सदन में भी इस कॉलेज के लिए आग्रह किया था। मंत्री जी, मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार कपिलमुनि शिक्षा समिति के साथियों ने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी और आपके कार्यालय में भी जमीन का और बिल्डिंग का रैजोल्यूशन भेजा था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दोबारा निवेदन करूंगा कि आपने पिछली बार कहा था कि आप इस काम को करवा देंगे तो फिर अब क्यों चक्कर कटवा रहे हो। आज तो हमें आश्वासन दे दिया जाए कि यह गर्ल्ज कॉलेज बना दिया जाएगा।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी जय प्रकाश जी ठीक दिशा में चलते-चलते ट्रैक छोड़ जाते हैं। मेरा जय प्रकाश जी से बहुत पुराना भाईचारा है। जय प्रकाश जी कई जगह से रिप्रजैंट कर चुके हैं और कलायत बाद में आये हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो संस्था कपिल मुनी के नाम से कलायत में है यदि यह संस्था जमीन और भवन उपलब्ध करवाती है तो हम वहां पर जरूर महाविद्यालय बनाने पर विचार करेंगे। इस बारे में ये प्रस्ताव करवाकर सरकार को भिजवा दें।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कनीना और निजामपुर में कालेज खोलने की घोषणा की थी और वहां पर कालेजिज की मंजूरी भी हो गई। यदि आने वाले सत्र में वहां पर कालेजिज की क्लासिज शुरू कर दी जायें तो मंत्री जी की बहुत-बहुत मेहरबानी होगी।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी डा. अभय सिंह यादव जी ने जो जिक्र किया है इन कालेजों की घोषणा मुख्यमंत्री जी जब नांगल चौधरी और नारनौल गए थे उस समय करके आये थे। जहां निजामपुर में माननीय साथी कालेज का काम शुरू करवाना चाहते हैं यह 9 गांव हैं जिन्हें नलवटी कहते हैं। इसमें झिलरो, निजामपुर, पैरा, नापला और तलोट आदि गांव आते हैं। मैं डा. अभय सिंह यादव जी को आश्वस्त करता हूं कि हम इसी सत्र में निजामपुर के कालेज का निर्माण प्रारंभ कर देंगे।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि रेवाड़ी में भी कालेज बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करके आये थे। इस वित्तीय वर्ष में तो वहां पर कार्य शुरू नहीं किया गया क्या अगले वित्त वर्ष में उस कालेज का कार्य शुरू करने का मंत्री जी आश्वासन देंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरूआत के दो महीने के दौरान अधिकतम विधान सभा क्षेत्रों के कार्यक्रमों में जो भी घोषणाएं की हैं उनमें शिक्षण संस्थाओं से जुड़ी हुई जो भी घोषणाएं हैं उन पर हम इसी सत्र में काम प्रारम्भ करने जा रहे हैं। (इस समय मेजें थप-थपाई गई।)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, जो विषय शिक्षा के संबंध में चल रहा है इस बारे में सदन में जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने विचार किया है कि हर 20 किलोमीटर पर लड़कियों का कालेज अवश्य बने ताकि किसी भी बहन या बेटी को 20 किलोमीटर से ज्यादा सफर करके न जाना पड़े। विभाग द्वारा इस तरह की हमने मैपिंग करवाई है। इस मैपिंग के अनुसार 23 लड़कियों के कालेज खोलने की बात सामने आई है। 6 कालेज पिछले सत्र में खोले हैं और 17 कालेज इस वर्ष खोल देंगे। यदि कोई 2-3 कालेज रह जायेंगे तो उनको अगले साल खोलने का काम करेंगे ताकि हमारे प्रदेश की बहन-बेटियां हायर शिक्षा अपने नजदीक ही ले सकें।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, जब पूरे प्रदेश में 20 किलोमीटर की दूरी पर लड़कियों के कालेज खुल जायेंगे तो हमारी बहनों को केवल 10 किलोमीटर का सफर ही तय करना होगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार नये कालेज जगह-जगह बना रही है, यह बहुत अच्छी बात है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों के सामने बड़ी समस्याएं हैं विशेषकर लड़कियां जो गांव से चलकर शहर में पढ़ने के लिए जाती हैं उनको ज्यादा दिक्कत आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कोई कालेज नहीं था। हमने हमारे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भागीराम जी के गांव में एक चौधरी से कालेज बनवाने के लिए जमीन सोसायटी को दान में दिलवाई और उसमें 15-16 कमरे भी बनवा दिए। पिछली सरकार के दौरान भी हमने वहां कालेज बनाने की बात कही थी लेकिन वे कहते रहे कि बिल्डिंग की दिक्कत है। अब तो वहां पर बिल्डिंग भी बना दी है। मेरी प्रार्थना है कि उस सोसायटी को सरकार टेकओवर करके वहां कालेज चलाने का काम करे। पिछले सैशन में भी इस बारे में मैंने यह रिक्वैस्ट शिक्षा मंत्री जी से की थी कि आप वहां पर पूरा स्टाफ लगाओ ताकि वहां पर बच्चों की पढ़ाई में कोई किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। आज भी वहां पर पूरा स्टाफ नहीं है। जो गवर्नमैंट कालेज, सिरसा की प्रिंसीपल हैं उसी के पास ही इस कालेज का भी एडीशनल चार्ज़ है। इसी प्रकार से सिरसा से ही कुछ प्रोफैसर वहां पर पढ़ाने के लिए जाते हैं। जिसकी वजह से वहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सामने बड़ी कठिनाई है। इसीलिए मेरी आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पुन: रिकवैस्ट है कि वहां पर परा स्टाफ लगाया जाये ताकि वहां के बच्चे पढ़ाई के मामले में पूरे प्रदेश में पिछड़ न जायें। यह भी बड़ी अजीब सी बात है कि वहां पर कालेज तो है लेकिन पढ़ाने वाला स्टाफ नहीं है। इसी प्रकार की समस्या कनीना में भी हालांकि वह मेरा विधान सभा क्षेत्र नहीं है लेकिन मैं वहां पर अक्सर जाता रहता हूं। वहां पर भी एक प्राईवेट कालेज के 28 कमरे बनकर तैयार हो गये हैं। वहां पर लगभग 2500 छात्रायें शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं। मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि इस कॉलेज को भी सरकार द्वारा ओवर-टेक किया जाये ताकि वहां के बच्चों को भी पढ़ाई के मामले में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं श्री अभय सिंह चौटाला जी के साथ-साथ पूरे सदन की जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगा कि कनीना का माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था और बहन संतोष यादव उस क्षेत्र को रिप्रैजैंट करती हैं। उस कालेज को हम बहुत जल्दी टेक-ओवर करेंगे। वहां पर एक संस्था दादा कान्हा महाविद्यालय के नाम से थी उसको भी हमने पिछले साल टेक-ओवर किया था। वहां पर पूरी सुविधायें उपलब्ध हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह जी ने जो बात ऐलनाबाद के बारे में कही है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम वहां पर जल्दी से जल्दी पूरा स्टाफ लगायेंगे। वहां पर हम प्रिंसिपल भी पूरे समय के लिए लगायेंगे। जिस महाविद्यालय को टेक-ओवर करने की बात श्री अभय सिंह जी ने कही है हम उसको भी जल्दी ही टेक-ओवर करेंगे।

प्रो. रविन्द्र बलियाला : स्पीकर सर, मेरा सवाल पे-बैंड से संबंधित है। इस सम्बंध में मेरा एक सवाल भी आज के लिए ही लिस्टिड है लेकिन पता नहीं उसका नम्बर आ पायेगा या नही। मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा ज़रूरी यह बात है कि जो वर्किंग कंडीशंज़ हैं वे ज्यादा से ज्यादा सही होनी चाहिएं और इसमें भी सबसे ज्यादा ज़रूरी यह है कि जो प्राध्यापक वहां पर पढ़ाते हैं वे पूरी तरह से तनावमुक्त हों। मैं इस बारे में यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में कुछ प्राध्यापकों को पे बैंड 4 दे दिया गया था जिनका सिलैक्शन

वर्ष 2001 में हुआ था। लगभग 150 प्राध्यापक ऐसे हैं जिनको अभी तक पे बैंड 4 नहीं दिया गया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह पे बैंड अब तक क्यों नहीं दिया गया और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने अभी तक इसको रोके रखा है।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, प्रोफैसर रविन्द्र बलियाला जी स्वयं भी एक अध्यापक रहे हैं। आज की सूची में उनका एक सवाल भी है। जिन प्राध्यापकों को पे बैंड 4 देने कि ये बात कर रहे हैं इस बारे में मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि हमारा डिपार्टमैंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमैंट है और इसमें हमने बहुत सी विसंगतियों को इन डेढ़ साल के समय में दूर किया है। रविन्द्र जी ने जो बात कही है इसके लिए हमने फाईल के ऊपर आवश्यक आदेश जारी कर दिये हैं।

श्रीमती विमला चौधरी : स्पीकर सर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक ही गुजारिश करना चाहती हूं कि मानेसर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी घोषणा करके आये थे कि मानेसर में एक सरकारी महाविद्यालय खोला जायेगा। वे मुझे इस बात की जानकारी दे दें कि मानेसर में यह कालेज कब तक बनेगा ?

श्रीमती लतिका शर्मा : स्पीकर सर, ऐसा ही मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र के रायपुररानी कस्बे का है। वहां पर भी माननीय मुख्यमंत्री एक महिला महाविद्यालय खोलने की घोषणा करके आये थे। यह शिक्षा के मामले में एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसलिए माननीय मंत्री जी मुझे भी यह बताने की कृपा करें कि रायपुररानी में इस महिला महाविद्यालय की कब तक स्थापना कर दी जायेगी। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या बहन विमला चौधरी जो पटौदी से विधायक हैं और श्रीमती लतिका शर्मा जी जो कालका से विधायक हैं उनको यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की घोषणा के मुताबिक हम मानेसर में सरकारी महाविद्यालय और रायपुररानी में महिला महाविद्यालय इसी फाईनैंशियल ईयर से प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, खानपुर कलां में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय चल रहा है। पहले यह खानपुर महिला महाविद्यालय था और उसकी कुछ जमीन जीन्द जिले के निडानी गांव में है। निडानी के आसपास कोई कॉलेज नहीं है मेरी माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उस जमीन का सदुपयोग करते हुये वहाँ पर एक महिला कॉलेज का निर्माण करवाने की कृपा करें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात ध्यान में आई है कि खानपुर महिला महाविद्यालय जो कि अब भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय बन चुका है और वह बहुत अच्छा चल रहा है। अब जीन्द में जो विश्वविद्यालय बनने जा रहा है उसके नाम का सुझाव भी यही आ रहा है कि उसका नाम भी भगत फूल सिंह के नाम पर ही रखा जाये। जहाँ तक माननीय साथी श्री परमिन्दर सिंह ने निडानी की जमीन पर महिला महाविद्यालय खोलने का सुझाव दिया है सरकार उस पर विचार करेगी।

Rajiv Gandhi Thermal Power Plant Khedar

*** 1241. Shri Abhay Singh Chautala :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the fine was imposed on M/S Reliance Energy Limited Company for not setting up the Rajiv Gandhi Thermal Power Plant Khedar (Hisar) in time and also for improper working of Machines and default in router etc.; if so, the details thereof?

(b) whether the fine has been recovered; if not, the reason thereof?

मुख्य मन्त्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) श्रीमान् जी, 377.54 करोड़ रुपये परियोजना के देरी से पूरा होने के लिए लिक्विडेटेड डैमेज के रूप से वसूले गये। मशीनों की अनुप्युक्त कार्यप्रणाली के लिए कोई भी जुर्माना नहीं लगाया गया। हालांकि, प्लांट के फाईनल टेकिंग ओवर से पहले मशीनों को समय-समय पर कॉन्ट्रेक्टर द्वारा उनकी लागत पर ठीक करवाया गया।

(ख) लिक्विडेटेड डैमेज पूरी तरह से वसूल लिया गया है।

Chemical Mixed Water

*** 1214. Shri Randhir Singh Kapriwas :** Will the Environment Minister be pleased to state whether it is fact that the chemical mixed Contaminated water of the factories of Industrial area Bhiwadi (Rajasthan) spreads in the area of Dharuhera (Rewari); if so, the steps being taken by the Government to check the flow of said chemical mixed water in Dharuhera area?

(वित्त मन्त्री) श्री कैप्टन अभिमन्यु : श्रीमान् जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हां श्रीमान जी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और जिला प्रशासन रेवाड़ी के अधिकारियों ने राजस्थान राज्य के अपने समकक्षों के साथ कई बैठकें की। परिणामस्वरूप राजस्थान राज्य ने भिवाडी संयुक्त बहि:स्राव उपचार सयंत्र (सी.ई.टी.पी.) की मौजूदा क्षमता 9 मिलियन प्रतिदिन (एम.एल.डी.) से 14 एम.एल.डी. तथा मलजल संशोधन सयंत्र की क्षमता 4 एम.एल.डी. से 11.5 एम.एल.डी. का आश्वासन दिया है।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के का बहुत बड़ा हिस्सा बावल और मानेसर के बीच में स्थित है। यहाँ पर हुडा ने एक सैक्टर भी काट रखा है। राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र का रसायन युक्त पानी यहाँ हर समय बहता रहता है और बरसात के दिनों में बाढ़ आती है क्योंकि यह सैक्टर लो-लाईंग एरिया में काटा गया है। यह पानी हाइवे को तोड़ता हुआ जाम लगा देता है। कई-कई दिन तक जाम लगते रहते हैं। इस बारे में राजस्थान सरकार से स्थानीय स्तर पर मीटिंग भी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने इस बारे में नैशनल ग्रीन

ट्रिब्यूनल में मुकदमा भी दायर किया हुआ है लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो यह रसायन युक्त पानी आता है इस बारे में राजस्थान सरकार से बात करके इसका कोई न कोई समाधान निकाला जाये।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है यह गम्भीर समस्या बहुत लम्बे समय से है। यह समस्या रेवाड़ी के क्षेत्र में हाईवे के आसपास बनी हुई है। रेवाड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर राजस्थान का भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र है और उसमें लगभग एक हजार ऑरेंज और रैड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज चल रही हैं। उन इंडस्ट्रीज का एफ्यूलैंट प्रोपरली ट्रीट न करके उसको ओपन में छोड़ा जाता है और नेचूरल फ्लो होने के कारण वह हरियाणा की तरफ आता है और रास्ते में जो भी गांव आया या जिसका भी खेत आया उसने सुरक्षा की दृष्टि से उस पानी के बहाव को डायवर्ट कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने इस संबंध में लगातार राजस्थान सरकार से भी बातचीत की है और केन्द्र सरकार के साथ भी बातचीत की है तथा सैंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ भी बातचीत की है। जैसे विधायक जी ने बताया कि यह मामला कुछ प्राईवेट लोगों के माध्यम से एन.जी.टी. में भी लगा है। हरियाणा सरकार का लगातार प्रयास है कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जा सके। उसी तरह भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ में उनका जो शहर है उसकी भी लगभग एक लाख की आबादी है उस शहर का जो सीवरेज डिस्पोजल है वह भी एस.टी.पी. के अभाव में अपने आप में एक समस्या बना हुआ है। पिछले दिनों मैंने जो सारी डिटेल प्राप्त करने के प्रयास किये हैं उनको बताने की बजाए मैं इस मैटर की जो सीरियसनैस है और जिसको माननीय विधायक ने भी उठाया है, मैं उसके बारे में हाउस को बताना चाहूंगा कि यह सामान्य एफ्लूअंट डिस्पोजल नहीं लगता है। जो बी.ओ.डी. हैं जिसको हम बायोलॉजीकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं उसका जो पैरामीटर है वह यह है कि जो कोई भी ट्रीटिड या अनट्रीटिड वाटर है उसका जो एक्सैप्टेबल पैरामीटर है कि इस क्वालिटी के वाटर को क्लीन माना जाएगा। उसकी तीन यूनिट्स तीन बी.ओ.डी. मानी जाती हैं। यह जो एफ्लूअंट आ रहे हैं वह 190 बी.ओ.डी. का है तो इससे आप समझ सकते हैं कि इतना जहरीला और इतना खतरनाक पानी हरियाणा की तरफ रेवाड़ी में आ रहा है। इसकी गम्भीरता को देखते हुए हमने पिछले दिनों राजस्थान सरकार और भारत सरकार की एक संयुक्त बैठक के माध्यम से इसी साल की 18 फरवरी को फिर मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने एक्शन प्लान सबमिट किया है। उनका प्रपोजल है कि अगले कुछ महीनों में जो इंडस्ट्रियल एरिया रिको चलाती है उसके अन्दर उनकी जो बाडी है जो भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण ट्रस्ट है उनका राजस्थान सरकार के साथ एक ट्राइपार्टइट अरेंजमैंट है। राजस्थान सरकार रिको और बी.जे.पी.एन.टी. वहां पर सी.टी.पी. और एस.टी.पी. चलाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने वायदा किया है कि अगले दो महीनों में इनका जो 9 एम.एल.डी. का सी.टी.पी. चल रहा है उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमैंट के अलावा बाकि जो इसका पारशियल ट्रीटमैंट है उसको दो महीने में करने की शुरूआत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जल्द ही वहां का जो 9 एम.एल.डी डिस्चार्ज है वैसे तो वहां का टोटल डिस्चार्ज 21 एम.एल.डी. है लेकिन सीवरेज का और इंडिस्ट्रियल एफ्लूअंट का मिलाकर 21 एम.एल.डी. बन जाता है उसको टरचरी लेवल तक ट्रीट करने का प्रिसक्राईब्ड स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने वायदा किया है और राजस्थान स्टेट जो

[कैप्टन अभिमन्यु]

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने उसको अपग्रेड करके 14 एम.एल.डी. तक ले जाने के लिए और उसकी कैपेसीटी बढ़ाने के लिए भी दो महीने का समय मांगा है। इसके अलावा वहां पर रिको जो एस.टी.पी. चला रही है वह 4 एम.एल.डी. का है जैसा कि मैंने बताया कि यदि यह 9 एम.एल.डी. से 14 एम.एल.डी. हो जाए तो सही रहेगा। इसके अलावा उन्होंने 4 एम.एल.डी. का अलग-अलग एस.टी.पी लगाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने एक गांव संतकलां में 3 एम.एल.डी. का, एक भिवाड़ी के पास 3 एम.एल.डी. का एडिसनल, एक डेढ़ एम.एल.डी. का भगत सिंह कॉलोनी में और एक गांव खानपुर में 2 एम.एल.डी. का तथा एक गांव मुंडानामेव में 2 एम.एल.डी. का एस.टी.पी लगाने का प्रस्ताव दिया है। अध्यक्ष महोदय इसके अलावा जो अमरूद्र योजना है पानी अटल मिशन ऑफ रज्यूगनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफर्मेशन उसमें उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। जिसमें 4 एम.एल.डी. की कैपेसिटी को साढ़े 11 एम.एल.डी. प्रस्तावित है और यह अप्रैल, 2018 तक पूरा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय इसके अतिरिक्त वहां पर एक साहिबी नदी बहती है उसमें भी पानी इस प्रकार से छोड़ा जा रहा है जो हरियाणा में घूम कर जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कहीं-कहीं पर पाईप लगाई गई थी लेकिन किसानों ने उसको रोक लिया था तो वह पानी भी उसमें जुड़ रहा है उसको लेकर भी हरियाणा सरकार राजस्थान व केन्द्र सरकार से लगातार सम्पर्क में हैं और मैं माननीय विधायक जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एन.जी.टी. में जो भी प्राईवेट पार्टी गई हैं उनके साथ भी हम सहयोग कर रहे हैं अगर और भी आवश्यक हुआ तो इसमें हम और प्रोएक्टीवली और अग्रेसिवली परस्यू करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित तौर पर एक गम्भीर समस्या है इसलिए इसका निदान होना चाहिए।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह जरूर पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से यह ट्रीटमैंट हो रहा है बहुत अच्छी बात है यह हो जाएगा। इसके अलावा भी पिछली सरकारों ने 15-20 साल पहले किसी एक सरकार ने वहां समझौते में राजस्थान सरकार से मात्र 20-30 लाख रूपये ले लिये थे कि उनको जो पानी ट्रीट होकर आएगा वह कैसा ट्रीट होगा। अध्यक्ष महोदय, वह तो समय बताएगा जो पानी ट्रीट होकर आएगा उसको एक नाले के द्वारा आगे साहिबी नदी तक बढ़ाया जाएगा लेकिन उस समय तो यह पैसा ले लिया लेकिन वहां नाला अभी तक नहीं बना है। प्रदूषण का पानी फैल कर जा रहा है और जो साफ पानी आएगा उसके लिए नाला नहीं बना है जिसके लिए उस वक्त हमारी सरकार ने पैसे ले लिये थे और उस पर कोई काम नहीं हुआ है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह नाला कब तक बन जाएगा ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, अभी विधायक जी ने जो जानकारी दी है कि 15-20 साल पहले तत्कालिन शासनारूढ़ हरियाणा सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अंतर्राज्यीय समझौता हुआ था, अगर आप उसकी सही डिटेल हमें प्रोवाईड करवा सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे हमारे द्वारा विभाग से इस बारे में जानकारी ली जायेगी। अगर इस प्रकार का कोई अंतर्राज्यीय समझौता इतिहास में हुआ है और उसकी एवज में हरियाणा सरकार ने कोई राशि ली है और उसके फोलो अप में हरियाणा सरकार को जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, वह की गई है या नहीं की गई है, निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लेकर के जो उचित कार्यवाही बनती है

वह की जायेगी। जैसा कि आपने बताया कि जो ट्रीटिड वाटर है उसे साहिबी नदी में लेकर आया जाये तो इस संबंध में मिली एक जानकारी बताती है कि यहां पर पाईप लाईन तो लगी है लेकिन चूंकि इस पाईप लाईन से किसानों के खेत प्रभावित हो रहे थे तो उन्होंने उस पाईप लाईन को बीच में ब्लॉक कर दिया है जिसके कारण फलो आगे नहीं जा पा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात मैं माननीय सदस्य को जरूर बताना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार के पास पानी को ट्रीट करने के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, यदि जरूरत पड़ी तो हम भी अपनी तरफ से मदद करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जिम्मेदारियों को निश्चित तौर से जरूर पूरा करेंगे।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने अंतर्राज्यीय समझौते से संबंधित डिटेल को प्रोवाईड करने की बात कही है, उस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि यह डिटेल संबंधित उपायुक्त के पास भेज दी जायेगी।

Shortage of Teachers and Supporting Staff

*** 1265. Shri Aseem Goel :** Will the Education Minister be pleased to state whether it is fact that there is a shortage of teaching as well as of other supporting staff in the GSSS Naneola, GHS Pnjola, GHS Chourmastpur, GSSS Jansui, GSSS Balana, GMS Jandheri of Ambala City constituency; if so, the time by which the shortage of staff in the abovesaid schools is likely to be met-out?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हाँ श्रीमान् जी, रिक्त पदों को जल्द ही पदोन्नति/सुव्यवस्थिकरण/सीधी भर्ती द्वारा भर लिया जाएगा जिसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री असीम गोयल ने अपने विधान सभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नन्यौला जो इनका अपना गांव है, राजकीय उच्च विद्यालय पंजोला, राजकीय उच्च विद्यालय चौड़मस्तपुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जनसूई, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बलाना, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जन्धेड़ी में अध्यापकों की रिक्त स्थानों के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है और इनकी बात सही भी है। शिक्षा विभाग में बहुत विसंगतियां थी। अयोग्य लोगों को नौकरी पर लगाया गया था। हमने पी.जी.टी. तथा टी.जी.टी. के लिए 20000 अध्यापकों की भर्ती के लिए हरियाणा स्टॉफ सिलेक्शन कमीशन को रिक्विजिशन भेजी है। शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया बहुत तेज गति से की जा रही है। मैं माननीय असीम गोयल जी को बताना चाहूँगा कि अप्रैल महीने से शुरू होने वाले सत्र में इन सब रिक्त स्थानों को भर दिया जायेगा।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा लेकिन स्टाफ की कमी के साथ-साथ एक और मूलभूत समस्या मेरे क्षेत्र में स्थित इन स्कूलों में अनुभव की जा रही है। यह सारे स्कूल लगभग लो-लाईंग एरिया में स्थित है। इन स्कूलों में मिट्टी डलवाकर भरत भरवाने की बहुत आवश्यकता है। माननीय कृषि एवं पंचायत मंत्री जी भी यहां बैठे हुए है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में भी लाना चाहूँगा कि जो मनरेगा की स्कीम चली हुई है उसके तहत कह दिया जाता है कि मिट्टी भरवा लो लेकिन जिन गांवों के पास अपनी पंचायती जमीन नहीं है वह मिट्टी कहां से लायें। अध्यक्ष महोदय, माननीय

[श्री असीम गोयल]

कृषि मंत्री जी तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में मौजूद हैं। मेरा कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि बरसात के दिनों में कई स्कूलों में चार-चार फुट तक पानी भर जाता है और स्कूल तालाब बन जाते हैं। हम उच्च गुणवत्तापूर्वक वाली शिक्षा की बात करते हैं जब तक हम इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं करेंगे तब तक अच्छी शिक्षा का सपना, सपना ही रहेगा।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी से संबंधित कार्य के लिए तो माननीय असीम गोयल जी को अलग से प्रश्न लगाना होगा। जहां तक मेरे विभाग का प्रश्न है तो उस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि स्कूलों के लिए हमने एक फ्लैगशिप कार्यक्रम चलाया है कि स्वच्छ प्रांगण-शिक्षा की गुणवत्ता। मतलब साफ है कि यदि स्कूल प्रांगण साफ सुथरा है तो शिक्षा की गुणवत्ता मे सुधार जरूर आयेगा। इसी के मद्देनजर हमने ऐसे स्कूलों को रेखांकित किया है जो लो-लाईंग एरिया में स्थित हैं तथा जहां पर बरसात के दिनों में पानी खड़ा होने की वजह से कई-कई दिनों तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। यह समस्या न आने पाये इसकी पर्याप्त व्यवस्था भी की जा रही है।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न को केवल शिक्षा विभाग तक ही केन्द्रीत करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि आप पंचायत के माध्यम से मनरेगा के माध्यम से या विभाग के माध्यम से इन स्कूलों को रेखांकित करके कब तक लो-लाईंग स्कूलों में मिट्टी डलवाने का कार्य हो जायेगा ? अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान क्षेत्र में लगभग 157 के करीब राजकीय स्कूल हैं, उसमें चाहे मॉडल स्कूल हों, चाहे राजकीय हाई स्कूल हों, चाहे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल हों और चाहे राजकीय मिडल स्कूल हों उनमें से तकरीबन 110 राजकीय स्कलों का स्तर नीचे होने के कारण बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। अध्यक्ष महोदय, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समस्या कितनी गहरी है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि क्या नये शैक्षणिक सत्र से जिन स्कूलों में यह समस्या ज्यादा गहरी हैं उनको रेखांकित करके मिट्टी भरवाने का काम करेंगे?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि हम इसी नये शैक्षणिक सत्र से रेखांकित किए गए स्कूलों में मिट्टी भरवाई के साथ-साथ जिन स्कूलों के कमरे नीचे बैठ गए हैं, उन स्कूलों में भी युद्ध स्तर पर काम करेंगे।

Veterinary Doctor in Gaushala

*** 1192. Shri Balwan Singh Daultapuria :** Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to depute Veterinary Doctors in each Gaushala; if so, the time by which the above said doctors in each Gaushala; if so, the time by which the above said doctors are likely to be deputed?

(कृषि मन्त्री) श्री ओम प्रकाश धनखड़ : नहीं, श्रीमान जी।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी कहने को तो गौ भक्त सरकार कहलाती है लेकिन जब भी गायों की देखभाल और डिस्पैंसरी या पशु अस्पताल खोलने की बात आती है तो सरकार पैसों की कमी के कारण पीछे हट जाती है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया हुआ है कि हरेक गाय को प्रतिदिन 15 रूपये के हिसाब से डाईट मिलनी चाहिए। इस प्रकार की सुविधा दिल्ली और राजस्थान में भी है। अगर ऐसी सुविधा हरियाणा में भी उपलब्ध हो जाये तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। इस प्रकार से गऊ माता की सेवा हो सकेगी।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में 392 गऊशालाएं पंजीकृत हैं। जिनमें 3 लाख से ज्यादा पशु हैं। हर गऊशाला में पशुओं की संख्या अलग-अलग हैं। पशुओं की संख्या और वहां की जरूर के हिसाब से विभाग ने व्यवस्थाएं की हुई हैं। मेरे माननीय साथी का प्रश्न हर गऊशाला के लिए था, इसलिए मैंनें कहा था कि हर गऊशाला इतनी बड़ी संख्या की नहीं है कि हर गऊशाला में पशु अस्पताल खोला जाये क्योंकि सरकार ने जो नियम बनाए हुए हैं उनके अनुसार 2000 पशुओं के लिए डिस्पैंसरी और 3000 पशुओं के लिए पशु अस्पताल खोले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इन गऊशालाओं में फिलहाल 8 पशु अस्पताल और 9 गऊशालाओं में डिस्पैंसरी हैं। इस वर्ष हमने डिमाण्ड के अनुसार जहां पर पशुओं की संख्या ज्यादा है वहां पर 5 गऊशालाओं को चुना हुआ है, जहाँ पर इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी गौ भक्त सरकार है। सरकार ग्रामीण क्षेत्र में भी उसी भावना के अनुसार विभाग 2000 पशुओं के लिए डिस्पैंसरी और 3000 पशुओं के लिए पशु अस्पताल खोलती हैं।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक माननीय सदस्य को पता है कि गऊशालाओं की आर्थिक हालत बड़ी खराब है। अगर गायों को प्रतिदिन डाईट मिलेगी तो गऊशालाओं को बड़ा लाभ होगा। दानी सज्जन गऊ माताओं के लिए जनवरी से मार्च महीने तक भागवत कथा कराते हैं ताकि उनको अनुदान राशि दी जा सके। सरकार भी अपने तरफ से फाईंनेशियल मदद कर दें तो इन गऊशालाओं की स्थिति सुधर जायेगी।

श्री हरि चंद मिढ्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि गऊ माता, धरती माता, गंगा माता इस तरह पांच माताएं होती है, लेकिन गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। ब्लड प्रेशर के मरीज को चाहिए कि सुबह उठकर एक रोटी 11.00 बजे गाय को खिलाए, तांबे का लोटा लेकर गाय के चरणों में जल डालें और फिर दो चुटकी हल्दी का तिलक उसके माथे पर लगाए और फिर 21 बार उच्चारण करें - "हे गऊमाता हमारे कष्ट दूर करो"। अध्यक्ष जी, अगर अगली बार हमारी पार्टी की सरकार बनी तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि मैं ही स्पीकर पद के लिए चुना जाऊं। मैं जब सुबह उठकर तप-साधना करता हूँ तो ईश्वर से अंत में यही कहता हूं कि इंडियन नैशनल लोकदल की जय हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Survey of Unapproved Colonies

*** 1307. Shri Mahipal Dhanda :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the report of 79 unapproved colonies of Panipat Rural Assembly constitutency has been submitted to concerned Department after conducting the survey by Urban Local Bodies Department; and

(b) if so, the time by which the abovesaid unapproved colonies are likely to be approved?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) :

(क) हां, श्रीमान्

(ख) इन अनाधिकृत कालोनियों के अनुमोदन करने का कोई प्रावधान नहीं है।

Beti Bachao Beti Padhao Yojna

*** 1220. Shri Ranbir Gangwa :** Will the Women and Child Development Minister be pleased to state districtwise provision of amount made in the budget by the Government under the "Beti Bachao - Beti Padhao Yojna" togetherwith the details thereof?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वकतव्य

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के अन्तर्गत जिलावार बजट का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(रु० लाख में)

क्र०सं०	जिला	बजट प्रावधान (वर्ष 2015-16)
1	2	3
1.	अम्बाला	65.01
2.	भिवानी	65.01
3.	झज्जर	65.01

1	2	3
4.	कैथल	65.01
5.	करनाल	65.01
6.	कुरूक्षेत्र	65.01
7.	नारनौल	65.01
8.	पानीपत	65.01
9.	रिवाड़ी	65.01
10.	रोहतक	65.01
11.	सोनीपत	65.01
12.	यमुनानगर	65.01
	कुल	**780.12**

गतिविधि अनुसार जिलावार बजट प्रावधान निम्न है:-

(रु० लाख में)

क्र०सं०	**गतिविधिवार बजट प्रावधान वर्ष 2015-16**	**बजट**
1.	अर्न्तक्षेत्रीय परामर्श और बैठक	5
	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण/संवेदीकरण कार्यक्रम	6
	नवीनीकरण	10
	आगे बढ़ाने की गतिविधियाँ	22
	निगरानी एवं मूल्यांकन	3.1
	प्रलेखन	3
	मानव संसाधन विकास की क्षेत्री गतिविधियाँ	5
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की क्षेत्रीय गतिविधियाँ	5
	फलैक्सी फण्ड	5.91
	कुल	**65.01**

Number of Universities

*** 1227. Shri Naseem Ahmed :** Will the Education Minister be pleased ot state the districtwise details of the number of Universities established in Haryana?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियन्त्रण में 8 राजकीय तथा 19 निजी विश्वविद्यालय हैं और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। सभी विश्वविद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम तथा पता	विश्वविद्यालय का प्रकार	स्थापना की तिथि/वर्ष
1	2	3	4
	जिला सोनीपत		
1	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां, सोनीपत	राजकीय विश्वविद्यालय	18.8.2006
2	डॉ० बी० आर० अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, सोनीपत	राजकीय विश्वविद्यालय	दिनांक 26.4.2012 को अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अधिसूचित किया गया था तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के नाम 25 एकड़ भूमि स्थानान्तरित हो चुकी है। भवन अभी निर्माणाधीन है तथा अभी तक कोई कक्षा आरम्भ नहीं की गई है।
3	ओ० पी० जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय, गांव जगदीशपुर, सोनीपत	निजी विश्वविद्यालय	23.03.2009
4	एस०आर०एम० विश्वविद्यालय, राजीव गांधी ऐजुकेशन सिटी, सोनीपत	निजी विश्वविद्यालय	03.05.2013
5	अशोका विश्वविद्यालय, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, सोनीपत	निजी विश्वविद्यालय	02.05.2014
	जिला गुड़गांव		
1	नार्थकैप विश्वविद्यालय, सैक्टर-23-ए, गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	21.10.2009
2	एमिटि विश्वविद्यालय, गांव-ग्वालियर, पंचगांव (नजदीक मानेसर), जिला गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	26.04.2010
3	एपीजे सत्य विश्वविद्यालय, गांव-सिलानी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	26.04.2010

1	2	3	4
4	अंसल विश्वविद्यालय-सैक्टर-55, गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	10.2.2012
5	श्री गुरू गोबिन्द सिंह विश्वविद्यालय, गांव बुढेरा, जिला गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	3.5.2013
6	जी०डी० गयोन्का, विश्वविद्यालय, सोहना रोड़, गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	3.5.2013
7	के०आर० मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना रोड़, गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	3.5.2013
8	बी०एम०एल० मुंझाल विश्वविद्यालय गुड़गांव	निजी विश्वविद्यालय	2.5.2014
	जिला अम्बाला		
1	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, गांव सदोपुर, अम्बाला	निजी विश्वविद्यालय	29.10.2010
	जिला कैथल		
1	एन०आई०आई०एल०एम०, विश्वविद्यालय, 9 के०एम० माईलस्टोन, मेन एन०एच० 65, कैथल	निजी विश्वविद्यालय	27.9.2011
	जिला रोहतक		
1	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	राजकीय विश्वविद्यालय	21.8.1975
2	बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक	निजी विश्वविद्यालय	10.2.2012
	जिला पलवल		
1	एम०बी०एन० विश्वविद्यालय, गांव औरंगाबाद, पलवल	निजी विश्वविद्यालय	10.2.2012
	जिला झज्जर		
1	जगननाथ विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़, झज्जर	निजी विश्वविद्यालय	3.5.2013
2	पी०डी०एम० विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़, झज्जर	निजी विश्वविद्यालय	14.1.2016

[श्री राम बिलास शर्मा]

1	2	3	4
	जिला फरीदाबाद		
1	अल-फलाह विश्वविद्यालय, धौज, फरीदाबाद	निजी विश्वविद्यालय	02.05.2014
2	मानव रचना विश्वविद्यालय, फरीदाबाद	निजी विश्वविद्यालय	06.08.2014
	जिला कुरूक्षेत्र		
1	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	राजकीय विश्वविद्यालय	1956
	जिला सिरसा		
1	चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा	राजकीय विश्वविद्यालय	28.3.2003
	जिला रेवाड़ी		
1	इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर, रेवाड़ी	राजकीय विश्वविद्यालय	7.9.2013
	जिला जीन्द		
1	चौ० रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द	राजकीय विश्वविद्यालय	7.8.2014
	जिला भिवानी		
1	चौ० बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी	राजकीय विश्वविद्यालय	6.8.2014
	जिला महेन्द्रगढ़		
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांव जांट-पाली महेन्द्रगढ़।	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2009

VAT/Surcharge on Diesel

*** 1225. Shri Zakir Hussain :** Will the Finance Minister be pleased to state the rate of VAT/Surcharge imposed on Diesel by the Government from October, 2014 till to date together with details of revenue accrued to the state exchequer so far by imposing the aboversaid VAT/Surcharge on diesel?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान् जी, अक्तूबर, 2014 में डीजल पर कर की दर 8.8 प्रतिशत थी (प्रभावी दर देय कर पर 5% अधिशुल्क सहित 9.24% थी)।

दिनांक 26.11.2014 को डीजल पर कर की दर को संशोधित करते हुए 11.5% निर्धारित किया गया (प्रभावी दर अधिशुल्क सहित 12.075% थी)।

दिनांक 16.07.2015 को डीजल पर कर की दर को पुन: संशोधित करते हुए 11.5% से 16.4% किया गया (प्रभावी दर अधिशुल्क सहित 17.22% थी)।

सरकार द्वारा अक्तूबर, 2014 से फरवरी, 2016 तक डीजल की बिक्री पर 4922.74 करोड़ रुपये का राजस्व वैट/अधिशुल्क के रूप में एकत्रित किया गया।

To set up Industrial Unit in Charkhi Dadri

*** 1233. Shri Rajdeep Phogat :** Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any industrial unit in Charkhi Dadri, if so, the time by which it is likely to be set up?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं श्रीमान् जी, इस तरह का कोई प्रश्न नहीं उठता।

Up-gradation of School

*** 1288. Shri Makhan Lal Singla :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Middle School of village Dhigtania of Sirsa Constituency; if not, the reasons thereof togetherwith the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी। यह विद्यालय स्तरोन्नति के लिए छात्र संख्या व कक्षा कक्ष संख्या से सम्बन्धित निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करता।

Steps taken to Control Air Pollution

*** 1107. Smt. Naina Singh Chautala :** Will the Environment Minister be pleased to state whether the Air Pollution level in village namely Tigri, Narong, Chattha, Asir, Desu Malkana (Kalanwali Constiuency) Dabwali and Kalanwali constituency is at very alarming level due to refinery situated at Kanakwal villages of Batinda Distt. Punjab State; if so, the steps taken to control the air pollution in the steps area?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं श्रीमान् जी। इसलिए द्वितीय भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

Plots given to SC, BC(A) and BPL

*** 1243. Smt. Geeta Bhukal :** Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state the number of 11 Sq. Yard Plots given to SC, BC(A) and BPL families of state under Mahatama Gandhi Gramin Basti Yojana during 2014-15 and 2015-16 togetherwith year wise details thereof?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रख दिया गया है।

वक्तव्य

वर्ष 2014-15 व 2015-16 के दौरान 100 वर्ग गज के प्लाटों के आबंटन का विवरण निम्न प्रकार से है-:

क्र. सं.	जिले का नाम	उन परिवारों की संख्या जिन्हें वर्ष 2014-15 में प्लाट अलाट किए गए हैं				उन परिवारों की संख्या जिन्हें वर्ष 2015-16 में प्लाट अलाट किए गए हैं			
		एस०सी०	बी०सी०	बी०पी०एल०	कुल	एस०सी०	बी०सी०	बी०पी०एल०	कुल
1	अम्बाला	27	10	29	66	0	0	0	0
2	फरीदाबाद	4504	2364	1453	8321	0	0	0	0
3	गुड़गांवा	32	27	92	151	49	48	57	154
4	हिसार	237	693	37	967	0	122	0	122
5	झज्जर	176	28	18	222	0	0	0	0
6	पानीपत	0	72	0	72	0	0	0	0
7	रेवाड़ी	14	5	247	266	7	3	4	14
	कुल	**4990**	**3199**	**1876**	**10065**	**56**	**173**	**61**	**290**

नोट

अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के प्लाट आबंटन के लिए आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.03.2008 थी, जबकि पिछड़ा वर्ग-ए के परिवारों हेतु अन्तिम तिथि 16.09.2008 थी। उक्त तिथि समाप्ति के बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया है। शेष 14 जिलों में वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में कोई प्लाट अलॉट नहीं किया गया लेकिन कोर्ट केस होने के कारण या भूमि अतिक्रमण इत्यादि के कारण उक्त वर्णित 7 जिलों में प्लाट आबंटन का कार्य वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 में किया गया है।

———————

Shifting of Bus Stand

*** 1248. Shri Naresh Kaushik :** Will the Transport Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the land has been acquired near Sector 9 of Bahadurgarh for the shifting of the bus stand outside the city; and

(b) if so, the time by which the new bus stand is likely to be constructed togetherwith the details thereof?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : (क) श्रीमान् जी, हां

(ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला लम्बित होने के कारण बस स्टैण्ड के निर्माण की समय सीमा नहीं दी जा सकती।

Construction of PHC Building

*** 1272. Shri Sri Krishan Hooda :** Will the Health Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the PHC Building of village Baroda; and

(b) if so, the time by which the work is likely to be started thereon?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) श्रीमान् जी।

(ख) आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य आरम्भ करने की संभावना है।

Works under D-Plan

*** 1272. Shri Balkaur Singh :** Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state the details of grant given in District Sirsa under the D-Plan during the year 2014-15 and 2015-16 together with the details of works to be done alongwith time by which these works are likely to be completed?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, राज्य सरकार द्वारा जिला योजना स्कीम के अंतर्गत जिला सिरसा को वर्ष 2014-15 में 510.83 लाख रुपये तथा चालू वित्त वर्ष 2015-16 में 818.40 लाख रुपये जारी किए गए। नियमानुसार सभी अनुमोदित कार्य उसी वित्त वर्ष में पूर्ण किये जाने चाहिएं जिसके लिये राशि जारी की गई है।

वर्ष 2014-15 के दौरान जिला सिरसा में 104 कार्य अनुमोदित किए गए थे। इनमें से 90 कार्य पूर्ण कर लिए गए, 1 कार्य प्रगति पर तथा 13 कार्य छोड़ दिए गए क्योंकि यह कार्य संबंधित विभागों द्वारा अन्य स्कीमों से पूर्ण कर लिए गए। जहां तक वर्ष 2015-16 के कार्यों की स्थिति का सम्बन्ध है, 164 कार्य जिला सिरसा में अनुमोदित किए गए थे। इनमें से 117 कार्य पूर्ण कर लिए गए, 27 कार्य प्रगति पर तथा 20 कार्य छोड़ दिए गए, क्योंकि यह कार्य संबंधित विभागों द्वारा अन्य स्कीमों से पूर्ण कर लिए गए।

Vacant Posts of Head Masters/Principals

*** 1231. Shri Ravinder Baliala :** Will the Education Minister be pleased to state the districtwise details of the number of Primary Schools, Senior Secondary Schools functioning without the Headmasters/Principals together with the reasons thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : श्रीमान् जी। इस सम्बन्ध में एक विवरण पत्र सदन की मेज पर रखा है।

विवरण

हरियाणा राज्य में मुख्य शिक्षकों व प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों की जिलेवार सूची निम्नानुसार है:-

जिले का नाम	मुख्य शिक्षकों के बिना क्रियाशील कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	प्रधानाचार्यों के बिना क्रियाशील कुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या
अम्बाला	127	27
भिवानी	136	49
फरीदाबाद	173	9
फतेहाबाद	146	41
गुड़गांव	-7	17
हिसार	158	31
झज्जर	37	58
जीन्द	145	23
कैथल	56	58
करनाल	276	38
कुरूक्षेत्र	188	17
महेन्द्रगढ़	238	30
मेवात	110	32
पलवल	257	26
पंचकूला	-38	8
पानीपत	148	47
रेवाड़ी	-1	39
रोहतक	21	20
सिरसा	117	30
सोनीपत	-10	33
यमुनानगर	156	14
कुल (हरियाणा)	**2433**	**647**

ये पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं। स्नातकोत्तर शिक्षक/मुख्याध्यापक के पदों से प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र ही पूरी कर ली जायेगी। वरिष्ठता मामले पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के कारण इस कार्य में देरी हुई जो कि अब हट गई हैं। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मुख्य शिक्षकों के पदों के लिए वैज्ञानिकीकरण तीव्रता से विचाराधीन है और निकट भविष्य में पूरा कर लिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of New Stadiums

234. Shri Hari Chand Midha : Will the Sports and Youth Affairs Minister be pleased to state—

(a) whether any new sports policy has been formulated by the state Government; if so, the details thereof;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any new stadium under the new sports policy in the state; and

(c) if so, the district level and block level details thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हां, श्रीमान जी। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी, 2015 को रोहतक में हरियाणा खेल तथा शारीरिक उपयुक्तता नीति 2015 जारी की है।

कथन (विवरण) सदन के पटल पर रखे जाते हैं।

(ख) हां, श्रीमान् जी।

(ग) नई नीति के अधीन निर्मित किये जाने वाले जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय स्टेडियमों के बारे में ब्यौरे निकाले जा रहे हैं।

कथन

हरियाणा खेल तथा शारीरिक उपयुक्तता नीति 2015 के मुख्य प्रावधान

सामान्य बिन्दु

1. खेल नीति 2015 प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेल हेतु व्यापक अधिकार है। यह सभी के लिए शारीरिक उपयुक्तता की दिशा में एक कदम है।

2. खेल नीति में सामान्य व्यक्ति तथा खिलाड़ियों सहित सभी के लिए शारीरिक उपयुक्तता के लिए विशेष प्रावधान है।

3. नई नीति सभी के लिए सभी के सहयोग हेतु खेल की मूल धारणा पर आधारित है। इसके उद्देश्य अन्तर राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, ढील, उच्च कार्य प्रतियोगिता के लिए खेल मुहैया करवाने के लिए है।

4. खेल की परिस्थिति के अनुसार लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारित करना।

[श्री अनिल विज]

खेल अवसंरचना

1. नई नीति के अधीन मूल कार्यक्रम के निष्पादन का प्रावधान है। प्रत्येक गांव में दो एकड़ या अधिक भूमि पर मिनी स्टेडियम तथा खेल मैदान बनाने का लक्ष्य है। इन मिनी स्टेडियमों को व्यायामशाला के नाम से पुकारा जाएगा। इन व्यायामशालाओं में व्यायाम (अभ्यास) तथा योग के साथ-2 खेल के लिए व्यवस्था भी है। इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव में कम से कम पांच खेल खेलने की सुविधा मुहैया करवाई जाए।

2. ब्लॉक स्तर पर भी व्यायामशाला का प्रावधान 6-7 एकड़ भूमि तथा योग तथा व्यायाम (अभ्यास) के लिए कम से कम दस खेल खेलने की सुविधा को भी ध्यान में रखा गया है, प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक भीतर तथा बाहरी स्टेडियम का निर्माण करने का लक्ष्य है।

3. स्टेडियम की सुविधाओं में सुधार तथा रख-रखाव के लिए व्यापक कार्य योजना पर विचार किया गया है। जिला स्तरीय स्टेडियम में योग तथा व्यायाम (अभ्यास) के साथ-साथ कम से कम 15 खेल खलने की सुविधा का विकास करने का लक्ष्य है।

शहर क्षेत्र

नई खेल नीति में पहली बार व्यापक योजना शहरी क्षेत्र में खेल सुविधाओं के लिए भी तैयार की गई है।

नगरपालिका

मिनी खेल स्टेडियम के विकास के लिए कम से कम एक व्यायामशाला जिसमें कम से कम पांच खेल खेलने की सुविधाओं के साथ-साथ योग तथा व्यायाम (अभ्यास) नगरपालिका स्तर पर मुहैया करवाया जाएगा।

शहर परिषद

मूल मिनी खेल स्टेडियम के नगरपालिका परिषद विकास के स्तर पर कम से कम एक अभ्यास योग तथा व्यायाम (अभ्यास) के साथ-साथ कम से कम 10 खेल खेलने की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं।

नगरनिगम

नगरनिगम के स्तर पर योग तथा व्यायाम (अभ्यास) के साथ-साथ 15 खेल खेलने की सुविधाओं हेतु मिनी खेल स्टेडियम में कम से कम एक व्यायामशाला विकसित करने का लक्ष्य है। कमजोर वर्गों तथा गंदी बस्तियों में खेलों के विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे।

राष्ट्रीय बाक्सिंग एथलैटिक एकेडमी रोहतक तथा सोनीपत राष्ट्रीय कुश्ती एकेडमी राज्य में प्रारंभ की जानी संभावित है।

पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम

1. इस नीति में वर्ष 2016 में रियो ओलम्पिक खेलों को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के साहस को बढ़ाने के लिए ओलम्पिक पदक विजेताओं हेतु नकद इनाम में जबरदस्त बढ़ौतरी की

गई है। अब ओलम्पिक स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपये के स्थान पर 6 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। रजत पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये के बजाए 4 करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 2 करोड़ रुपये की बजाए 2.50 करोड़ रुपये तथा हरियाणा राज्य के ओलम्पिक में प्रतिभागी 11 लाख रुपये की बजाए 15 लाख रुपये प्राप्त करेगा।

2. इसी प्रकार विश्व चैम्पियनशिप, एशियन खेलें, कॉमनवैल्थ खेलें, विश्व विश्वविद्यालय खेलें, राष्ट्रीय खेलें, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप पदक विजेताओं के खिलाड़ियों के लिए इनाम में वृद्धि का प्रावधान भी किया गया है। उदाहरण के लिए एशियन खेल के खिलाड़ियों के स्वर्ण पदक विजेताओं को 2 करोड़ की बजाए 3 करोड़ रुपये दिए जाएंगे तथा कॉमनवैल्थ खेलों के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 1 करोड़ की बजाए 1.50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे तथा विश्व कप चैम्पियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को 10 लाख रुपये की बजाए 25 लाख रुपये दिए जाएंगे। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्र. सं.	**प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप**	**पदक**	**पूर्व इनाम राशि**	**संशोधित इनाम राशि**
1	2	3	4	5
1.	ओलम्पिक/पैरालम्पिक खेलें	स्वर्ण	5,00,00,000	6,00,00,000
		रजत	3,00,00,000	4,00,00,000
		कांस्य	2,00,00,000	2,50,00,000
		प्रतिभागिता	11,00,000	15,00,000
2.	एशियन/पैरा एशियन खेलें	स्वर्ण	2,00,00,000	3,00,00,000
		रजत	1,00,00,000	1,50,00,000
		कांस्य	50,00,000	75,00,000
		प्रतिभागिता	5,00,000	7,50,000
3	कॉमनवैल्थ/पैरा कॉमनवैल्थ	स्वर्ण	1,00,00,000	1,50,00,000
		रजत	50,00,000	75,00,000
		कांस्य	25,00,000	50,00,000
		प्रतिभागिता	5,00,000	7,50,000
4.	विश्वकप/चैम्पियनशिप (चार वर्ष में एक बार)	स्वर्ण	10,00,000	25,00,000
		रजत	8,00,000	20,00,000
		कांस्य	6,00,000	15,00,000
		प्रतिभागिता		7,50,000

[श्री अनिल विज]

1	2	3	4	5
5.	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/ पैरा विश्व खेलें/पैरा विश्व चैम्पियनशिप (वार्षिक)	स्वर्ण	10,00,000	20,00,000
		रजत	8,00,000	15,00,000
		कांस्य	6,00,000	10,00,000
		प्रतिभागिता		3,00,000
6.	विश्व विश्वविद्यालय खेलें/ चैम्पियनशिप	स्वर्ण	--	7,00,000
		रजत	--	5,00,000
		कांस्य	--	3,00,000
7.	युवा ओलम्पिक खेलें	स्वर्ण	10,00,000	10,00,000
		रजत	7,50,000	7,50,000
		कांस्य	5,00,000	5,00,000
8.	युवा एशियन खेलें	स्वर्ण	7,00,000	7,00,000
		रजत	5,00,000	5,00,000
		कांस्य	3,00,000	3,00,000
9.	एशियन/कॉमनवैल्थ चैम्पियनशिप/कप	स्वर्ण	4,00,000	5,00,000
		रजत	3,00,000	4,00,000
		कांस्य	2,00,000	3,00,000
10.	युवा कॉमनवैल्थ खेलें	स्वर्ण	5,00,000	5,00,000
		रजत	3,00,000	3,00,000
		कांस्य	2,00,000	2,00,000
11.	सैफ खेलें	स्वर्ण	3,00,000	5,00,000
		रजत	2,00,000	3,00,000
		कांस्य	1,00,000	2,00,000
12.	राष्ट्रीय खेलें/पैरा राष्ट्रीय खेलें	स्वर्ण	3,00,000	5,00,000
		रजत	2,00,000	3,00,000
		कांस्य	1,00,000	2,00,000
13.	राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/पैरा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप	स्वर्ण	2,00,000	3,00,000
		रजत	1,00,000	2,00,000
		कांस्य	50,000	1,00,000

1	2	3	4	5
14.	राष्ट्रीय स्कूल खेलें	स्वर्ण	30,000	50,000
		रजत	20,000	30,000
		कांस्य	14,000	20,000
15.	अखिल भारतीय अन्तर	स्वर्ण	30,000	50,000
	विश्वविद्यालय	रजत	20,000	30,000
	प्रतियोगिता/चैम्पियनशिप	कांस्य	14,000	20,000
16.	राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव	स्वर्ण	30,000	50,000
		रजत	20,000	30,000
		कांस्य	14,000	20,000
17.	अखिल भारतीय ग्रामीण खेल	स्वर्ण	30,000	50,000
	प्रतियोगिता	रजत	20,000	30,000
		कांस्य	14,000	20,000
18.	अन्तर्राष्ट्रीय वैटर्न (मास्टर)	स्वर्ण	70,000	1,00,000
	एथलैटिक्स चैम्पियनशिप (सभी	रजत	50,000	60,000
	आयु वर्ग में)	कांस्य	34,000	40,000
19.	राष्ट्रीय वैटर्न (मास्टर)	स्वर्ण	30,000	75,000
	एथलैटिक्स चैम्पियनशिप (सभी	रजत	20,000	50,000
	आयु वर्ग में)	कांस्य	14,000	30,000
20.	मानसिक रूप से विकलांग	स्वर्ण	15,00,000	15,00,000
	खिलाड़ियों के लिए विशेष	रजत	10,00,000	10,00,000
	ओलम्पिक-विश्व खेलें	कांस्य	5,00,000	5,00,000
	(अन्तर्राष्ट्रीय)	प्रतिभागिता	1,00,000	2,00,000
21.	मानसिक रूप से/शारीरिक रूप	स्वर्ण	1,00,000	3,00,000
	से विकलांग खिलाड़ियों के लिए	रजत	75,000	2,00,000
	विश्व मैराथन	कांस्य	50,000	1,00,000
		प्रतिभागिता	--	50,000
22.	मानसिक रूप से/शारीरिक	स्वर्ण	30,000	50,000
	रूप से विकलांग खिलाडियों	रजत	20,000	30,000
	के लिए विशेष ओलम्पिक	कांस्य	14,000	20,000
	(राष्ट्रीय)			

[श्री अनिल विज]

1	2	3	4	5

राज्य स्तरीय अखाडा कुश्ती प्रतियोगिता

स्थान	**वर्तमान नकद इनाम राशि**	**प्रस्तावित नकद इनाम राशि**
प्रथम	500/-	5100/-
द्वितीय	300/-	3100/-
तृतीय	200/-	2100/-

राज्य स्तरीय कुमार दंगल विजेताओं के लिए नकद इनाम

स्थान	**वर्तमान नकद इनाम राशि**	**प्रस्तावित नकद इनाम राशि**
प्रथम	21,000/-	51,000/-
द्वितीय	11,000/-	31,000/-
तृतीय	5,000/-	21,000/-

राज्य स्तरीय केसरी दंगल विजेताओं के लिए नकद इनाम

स्थान	**वर्तमान नकद इनाम राशि**	**प्रस्तावित नकद इनाम राशि**
प्रथम	31,000/-	1,51,000/-
द्वितीय	21,000/-	1,00,000/-
तृतीय	11,000/-	51,000/-

Pay Band IV to College Lecturers

283. Shri Ravinder Baliyala : Will the Education Minister be pleased to state a number of Lecturer of Govt. College of the State to whom the Pay Band-IV is due with the time by which the Pay Band likely to be provided to these lecturers?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, उपलब्ध रिकार्ड अनुसार राजकीय महाविद्यालयों के 25 सहायक प्रोफेसरों को पे बैंड-IV देय है। एक सहायक प्रोफेसर को पे बैंड-IV, उसके द्वारा सभी जरूरी आवश्यकताएं जैसे कि वर्षों की संख्या, शैक्षणिक कार्य दक्षता (ए0पी0आई0) आदि पूर्ण करने पर, अनुवीक्षण समिति, जो इस उद्देश्य हेतु गठित की जाती है द्वारा अनुमोदन उपरान्त प्रदान किया जाना है। अनुवीक्षण समिति की बैठक दिनांक 06.04.2016 को की जा रही है।

To give the Proprietorship to Gaushalas

329. Sh. Ramchand Kamboj : Will the Development and Panchayat Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the building of Gaushalas have been constructed on the land of Panchayat since long time in Raina Assembly Constituency, and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to give proprietorship to Gaushalas; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

(क) रानिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पंचायती भूमि पर पिछले 1 से 15 वर्षों से 17 गौशालाऐ निर्मित हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान जी,

To Install Water Cooler Equipped with R.O.

297. Sh. Rajdeep Phogat : Will the Education Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to install the water coolers equipped with RO system for the students in schools and colleges in the state; if so, the time by which these are likely to be installed ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान जी, राज्य के राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आर0ओ0 से सुसज्जित वाटर कूलर लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं हैं।

Total Number of Boy and Girl Students

336. Sh. Udai Bhan : Will the Education Minister be pleased to state the total number of Boy and Girl students in the Government Primary Schools, Government Middle Schools, Government High Schools and Government Senior Secondary Schools togetherwith the number of students belonging to scheduled castes, backward classes and General Category separately?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हाँ, श्रीमान जी। राजकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति व सामान्य वर्ग से सम्बन्धित छात्र तथा छात्राओं की संख्या निम्नानुसार है:-

[श्री राम बिलास शर्मा]

			लड़के			लड़कियां			
	विद्यार्थियों की कुल संख्या	कुल संख्या	सामान्य	एस०सी०	बी०सी०	कुल संख्या	सामान्य	एस०सी०	बी०सी०
राजकीय प्राथमिक विद्यालय	951254	467701	91077	192330	184294	483553	101513	189930	192110
राजकीय मिडल विद्यालय	661397	320971	60525	140328	120118	340426	74151	140032	126243
राजकीय उच्च विद्यालय	387173	187658	39368	81396	66894	199515	49566	83228	66721
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय	239565	120804	39569	36837	44398	118761	40071	36835	41855
कुल संख्या	2239389	1097134	230539	450891	415704	1142255	265301	450025	426929

To Open Women Degree college in Ladwa

331. Dr. Pawan Saini : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Women Degree College in Ladwa Assembly Constituency?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं श्रीमान जी।

Repair of Road

240. Sh. Om Parkash Barwa : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the road from Loharu upto the limit of Mahendergarh has been damaged; if so, the time by which it is likely to be repaired?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान जी। सड़क यातायात योग्य है तथा इसका रख-रखाव गढ़े भरकर / पैच कार्य द्वारा किया जा रहा है। इसकी मरम्मत प्रीमिक्स कारपेट द्वारा 09/2011 के दौरान की गई थी तथा मुख्य मरम्मत के लिए वर्ष 2016-2017 में प्रस्तावित किया जा रहा है।

Purchase of New Buses

271. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Transport Minister be pleased to state :-

(a) the Depotwise number of new buses purchased during the years 2013-14, 2014-15 and 2015-16; and

(b) the Depotwise number of new purchased buses which could not be put on routes due to non-availability of Drivers togetherwith the period of idleness of each bus?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान जी,

(क) परिवहन विभाग डिपोवार नई बसों की खरीद नहीं करता है।

(ख) उपरोक्त 'क' पर उत्तर के सन्दर्भ में, प्रश्न नहीं उठता है।

Up gradation of School

246. Sh. Lalit Nagar : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government High School in village Sehatpur of Tigaon Assembly constituency up to secondary school ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हाँ, श्रीमान जी। राजकीय उच्च विद्यालय, सेहतपुर को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का मामला विचारधीन है।

Baba Gaibi Sahib Pilgrimage

254. Sh. Pirthi Singh : Will the Tourism Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to hand over the charge of Baba Gaibi Sahib Pilgrimage in Narwana to the Kurukshetra Development Board together with the time by which its charge is likely to be handed over to the Kurukshetra Development Board?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्ज सम्मिट के संबंध में

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्य श्री रणबीर गंगवा, विधायक तथा चार अन्य विधायकों (सर्वश्री परमिन्द्र सिंह ढुल, जाकिर हुसैन, नगेन्द्र भड़ाना तथा केहर सिंह) द्वारा "हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्ज सम्मिट" के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-25 प्राप्त हुई है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

श्री उमेश अग्रवाल, विधायक द्वारा भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 "हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्ज सम्मिट" के बारे में दी गई है। समान विषय का होने के कारण ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री उमेश अग्रवाल, विधायक भी इस विषय पर सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

श्री रणबीर गंगवा, विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैं तथा श्री परमिन्द्र सिंह ढुल विधायक, श्री जाकिर हुसन विधायक, श्री नगेन्द्र भडाना विधायक तथा श्री केहर सिंह विधायक इस माननीय सदन का ध्यान एक आवश्यक एवं सार्वजनिक महत्व के मामले के प्रति आकर्षित करना चाहते हैं कि राज्य सरकार विख्यात राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय व्यावसायिक घरानों से हरियाणा में निवेश आमन्त्रित/आकर्षित करके हैपनिंग हरियाणा कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्धियों का प्रचार कर रही है। हाल ही में, सरकार ने गुड़गॉव में उद्योगपतियों/व्यापारियों का एक सेमीनार/सम्मेलन उनके हरियाणा में पूंजी निवेश करने के लिए विश्वास दिलाने के लिए आयोजित किया है। हरियाणा के लोगों में बहुत बेचैनी तथा पश्चाताप है कि हरियाणा का कार्यक्रम पूर्णतया असफल रहा है पहले भी राज्य सरकार निवेशकों को वास्तविक रूप में लाने में असफल रही। गुड़गांव का सम्मेलन असफल रहा है क्योंकि निवेशकों ने बहुत कम संख्या में वह भी बहुत कम पूंजी निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई तथा वे गुड़गांव क्षेत्र तक ही सीमित रहे। निवेशकों द्वारा हरियाणा के बाकी भागों में दिलचस्पी न दिखाना एक चिन्ताजनक बात है विशेषत: विकास के आन्दोलन में सरकार के असफलता के कारण।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन का ध्यान गुड़गांव में दिनांक 07 एवं 08 मार्च 2016 में आयोजित हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवैस्टर सम्मिट के सम्बन्ध में आवश्यक तथा बहुत सार्वजनिक महत्व के मुद्दे की ओर दिलाना चाहेगें, जिसमें 15 देशों से निवेशकों ने उपस्थिति दी तथा 12 देशों द्वारा सहभागी देश के रूप में हिस्सा लिया, जिसमें हरियाणा में उद्योग की स्थापना के लिए विचार-विमर्श हुआ लगभग 2300 निवेशकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। लगभग 357 समझौते 5.84 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए हस्ताक्षर किये गए थे। यह सम्मेलन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पूरी तरह सफल रहा था, जिसके लिए हरियाणा सरकार तथा विशेषतया माननीय मुख्यमंत्री प्रशंसा के पात्र हैं। इस सम्मेलन की सफलता हरियाणा में औद्योगिक विकास को उन्नत करेगी, जिससे राज्य के समग्र विकास में तेजी आयेगी तथा लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यह प्रयत्न वर्तमान सरकार द्वारा प्रथम बार किया गया है। पिछले 1 साल के दौरान कुछ राज्य जिसमें पंजाब, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक शामिल हैं जिन्होंने इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए हैं परन्तु, हरियाणा एक छोटा राज्य होने के बावजूद भी महत्वपूर्ण निवेशों को आकर्षित करने तथा बड़ी संख्या में समझौतों का क्रियान्वयन करने में सफल हुआ है, तथा महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त होने की सम्भावना है। सरकार से अनुरोध है कि इस माननीय सदन को बताऐं कि कितने समझौते हुए हैं तथा विभिन्न क्षेत्रों में कितना निवेश प्राप्त होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कौन सी सुविधाऐं प्रदान की जायेंगी। सरकार से यह भी अनुरोध है कि नई औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में सूचित किया जाये।

अत: उपरोक्त के दृष्टिगत सरकार सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय वित्त मंत्री उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देंगे।

वक्तव्य

वित्त मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय,

1. राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य में औद्योगिकरण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं तथा हरियाणा से अन्य राज्यों को उद्योगों के स्थानान्तरण के लिए कारणों सहित अध्ययन

करने के लिए तथा स्थिति से निपटने के लिए मार्ग सुझाने हेतु अधिकारियों की एक समिति का गठन किया था। समिति ने पाया है कि जबकि वर्ष 2007-2014 की अवधि के दौरान राज्य का औद्योगिक विकास 8 प्रतिशत से अधिक था, परन्तु 2009 से विकास की दर लगभग 4 प्रतिशत रही है। यह भी पाया गया था कि इस अवधि के दौरान निर्माण सैक्टर का शेयर जी.डी.पी. का 32 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत हो गया था। समिति ने यह भी बताया था कि यद्यपि राज्य की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय विकास स्तर से आगे बढ़ गई है, फिर भी यह कभी भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सकी थी।

2. यद्यपि औद्योगिक विकास में कमी मूल रूप से 2008 की मन्दी का कारण रही, राज्य में कम औद्योगिक विकास के लिए भिन्न-भिन्न कारण थे, जो एक विस्तृत तथा गहन अध्ययन करने पर सुनिश्चित हुए। आसानी से व्यापार करना, आर्थिक प्रोत्साहनों की अनुपलब्धता, एम.एस.एम.इज. पर ठोस केन्द्रित होने की आवश्यकता तथा पड़ोसी राज्यों की तुलना में उच्च कारक जैसे भूमि श्रम एवं विधुत की उच्च दर। यह भी पाया गया था कि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए अनेकों प्रयासों जैसे मेक इन इण्डिया, स्किल एण्ड डिजीटल इण्डिया तथा रक्षा, अन्तरिक्ष, रेलवे एवं इलक्ट्रोनिक्स निर्माण क्षेत्रों में उदार पूंजीनिवेश वातावरण के कारण राज्य के लिए औद्योगिक रणनीति में बड़े बदलाव की आवश्यकता पड़ी। इन सभी फैक्टरों ने राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने तथा वर्तमान नीति में अन्तरों को पूरा करने, मन्दी को रोकने तथा अपनी सच्ची क्षमता को अनुभव करने के लिए राज्य को विकास की राह पर लाने की काफी आवश्यकता पड़ी।

3. सभी उपरोक्त मुद्दों को सुलझाने तथा राज्य को अग्रणी विकास प्रक्षेपवक्र पर ले जाने के लिए राज्य में अगस्त 2015 में एक अग्रणी (उधम उन्नयन नीति-2015) (ई.पी.पी.) बनाई। इस पोलिसी में 8 प्रतिशत से अधिक जी.डी.पी. का विकास, 1.00 लाख करोड़ रूपये का पूंजी निवेश तथा 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार उत्पन्न करना तथा हरियाणा को एक पूर्वप्रतिष्ठित निवेश स्थान के रूप में कल्पना की गई है। इस नीति में निर्माण तथा सेवाऐं क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केन्द्रिय किया गया है क्योंकि वे राज्य जी.डी.पी. का योगदान करते हैं।

4. नई उद्यम उन्नयन नीति 2015 की घोषणा के तुरन्त पश्चात, हरियाणा को निवेश स्थान के रूप में पेश करने तथा सुविधाओं एवं प्रौत्साहनों का मुख्य आकर्षण प्रस्तुत करने के लिए अगस्त 2015 में यू.एस.ए. तथा कन्नाडा में दौरे किए गए थे। इन दौरों की बेहद अच्छी प्रतिक्रिया की तथा एक निवेशक सम्मेलन के आयोजन के बारे में एक विचार सामने आया।

5. आज के सहयोगी स्पर्धात्मक संघीय वातावरण में, सभी राज्य एक दूसरे के साथ अधिकतम निवेश प्रवाहित करने की स्पर्धा में है तथा निवेशक सम्मेलन आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य निवेश बढ़ाने की रणनीति का प्राथमिक मूलतन्त्र है। पिछले 6 महिनों में ऐसे कई सम्मेलन आयोजित किए जा रहे जैसे सितम्बर 2015 में तमिलनाडु द्वारा ग्लोबल इन्वैस्टर सम्मिट, अक्तुबर 2015 में प्रगतिशील पंजाब, नवम्बर 2015 में पुर्नउत्थानशील राजस्थान, जनवरी 2016 में सनराईज आन्ध्रा तथा फरवरी 2016 में ग्लोबल इन्वस्टर मीट कर्नाटका।

[कैप्टन अभिमन्यु]

6. आगे राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय दोनों निवेशकों के साथ वार्तालाप में एक अर्न्तराष्ट्रीय स्तर सम्मेलन का विचार बना तथा इस बारे में अन्तिम निर्णय नवम्बर/दिसम्बर 2015 में लिया गया था। जबकि अन्य राज्यों ने ऐसे सम्मेलन का आयोजन करने के लिए कम से कम एक वर्ष का समय लगाया है, हरियाणा राज्य ने 3 महिने की अवधि में इस सम्मेलन के आयोजन की चुनौती स्वीकार की।

7. अन्य राज्यों की तरह एक टीम बनाई गई जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी, राष्ट्रीय पार्टनर सी.आई.आई. ज्ञान पार्टनर के.पी.एम.जी. तथा मीडिया पार्टनर एडफैक्टर शामिल थे मार्च 2016 के लिए अनुसूचित मुख्य सम्मेलन के लिए घरेलू रोड शोज देहली, कलकता, चैनई, मुम्बई तथा बंगलुरू में हुए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने जनवरी 2016 में हरियाणा का व्यापार बढ़ाने तथा निवेशक सम्मेलन में भागीदारी आकर्षित करने के लिए जापान तथा चीन का दौरा किया। इस इवैन्ट का इलैक्ट्रोनिक्स, प्रिन्ट तथा सोशल मीडिया पर एक अभियान के माध्यम से प्रचार किया गया था व प्रमुख उद्योगपतियों, केन्द्रीय मन्त्रियों, राजदूतों/उच्चायुक्तों एवं अन्य निवेशकगणों के साथ इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सम्पर्क किया गया था।

8. जबकि इस आयोजन में एक आरम्भिक सत्र तथा एक विदाई सत्र शामिल थे, इन दोनों सत्रों के मध्य राज्य सरकार के विशेष क्षेत्रों पर आधारित कई समानान्तर क्षेत्रों वाले तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों के आयोजन के लिए सरकार के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई थी जो कि एक केन्द्रीय मन्त्री की अध्यक्षता में शुरू किया गया तथा राज्य केबिनेट मन्त्री द्वारा अध्यक्षता की गई।

9. राज्य सरकार ने हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टरस सम्मिट, 2016 का होटल लीला, गुड़गांव में 7 से 8 मार्च 2016 को सफलता पूर्वक आयोजन किया। इस बात का प्रमाण है कि सम्मेलन सफलता पूर्वक हुआ जिनमें निम्नलिखित विशेष है -

- इस आयोजन में माननीय वित मन्त्री श्री अरूण जेटली के नेतृत्व में 13 केन्द्रीय कैबिनेट मन्त्रियों ने प्रतिनिधित्व किया।
- हैपनिंग हरियाणा को केन्द्रीय केबिनेट मन्त्रियों का व्यक्तिगत रूप से हमारी सभी तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता का लाभ मिला था जिसमें श्री मनोहर परिकर, श्री पीयूष गोयल, श्री कलराज मिश्र तथा अन्य शामिल थे।
- 3000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया जिसमें 160 विदेशी प्रतिनिधि शामिल थे। फरवरी 2016 में हुए दंगों के बावजूद आयोजन में बड़ी संख्या में भागीदारी यह दर्शाती है कि निवेशकों ने राज्य सरकार पर भरोसा जताया।
- चीन, चैक रिपब्लिक, जापान, स्पेन, यू.के., मारिशस, मालावी, न्यूजीलैंड, पेरू, दक्षिण कोरिया, टयूनेषिया तथा कनाडा से 12 पार्टनर देशों के राजदूतों तथा उच्चायुक्तों ने भाग लिया। इसके साथ ही लगभग अन्य 15 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया।

- आरम्भिक एवं विदाई सत्रों के दौरान प्रमुख उद्योगपति भी उपस्थित थे जिसमें वाई.सी. देवेश्वर, गौतम अडाणी, आनन्द महिन्द्रा, वाण्डा के वंग जियनलिंन, गोदरेज आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न कम्पनियों से काफी संख्या में मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर के अधिकारियों ने भी भाग लिया जैसे मारूति सुजुकी, माईक्रोसॉफ्ट, पैनासोनिक, भारती, माइक्रोमैक्स, जे.एस.डब्लयू, वालमार्ट, अमूल, यस बैंक, जेड.टी.ई.,एन.आई.आई.टी. जैनपैक्ट, सोमानी, हनिवैल, प्रैंट एव विटनि, रोलस रोयस, साब, आई.टी.सी. लि0 ऐजूकम्प, वोडाफोन, केपीएमजी, जी, फोर्टिस हैल्थ केयर, लोटे असेट डवल्पमैंट, होण्डा, जूनिपर नैटवर्क, पंजाब नेशनल बैंक, गोदरेज, सन फार्मा, डीएलफ, हीरा, अदानी, वाण्डा ग्रुप, महिन्द्र, पेप्सिको, इनफाईसिस, सन्धार, एजवुड, सर्वजल, जे.आई.ओ., बुर्टमालट, स्नेप डील अवन्था, डासोल्ट, चाईना फयुचर लैण्ड डवलपमैंट कम्पनी लि0, जे.आई.सी.ए. मिनिस्टरी ऑफ इकनोमि ट्रेंड एण्ड इन्डस्ट्रीज जापान।
- राज्य सरकार ने 5 गुणा निवेश प्राप्त किया जो हरियाणा राज्य तथा दूसरे राज्यों की तुलना में उद्योग के भरोसे को दर्शाता है। भारत तथा विदेशों से 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिन्होने सम्मेलन को सफल बनाया। 1 लाख करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध 5.84 लाख करोड़ रुपये का पूंजिनिवेश 5 लाख रोजगार के साथ सम्मेलन के दौरान रूचि दिखाई। कुल 359 एम.ओ.यूस. पर हस्ताक्षर किए थे। कुल एम.ओ.यूस. में से लगभग 180 एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हुए जिनमें 4 लाख करोड़ (68%) के पूंजिनिवेश गुड़गांव-फरीदाबाद के अलावा अन्य जिलों के लिये किये गये थे। गुड़गांव में लगभग 25 एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हुए जिनमें लगभग 90 हजार करोड़ (15%) का निवेश व 1.4 लाख रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। फरीदाबाद क्षेत्र के लिए लगभग 37 एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हुए हैं। जिनमें लगभग 10 हजार करोड़ (1.7%) रुपये का पूंजिनिवेश व 60 लाख रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। एम.ओ.यूस. का लगभग 10 प्रतिशत एम.एन.सी. के साथ हस्ताक्षर किए गए थे जो इस तथ्य को उजागर करता है कि हरियाणा निवेश के लिए एक प्रथम अधिमान राज्य है, तथा राज्य में अतिरिक्त एफ.डी.आई. का प्रवाह सुनिश्चित हो गया है। एम.ओ.यूस. का 15 प्रतिशत 1000 करोड़ रुपये से अधिक वाली परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए गए थे तथा एम.ओ.यूस. के 33 प्रतिशत 100 करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले थे। यह अनुभव करते हुए कि एम.एस.एम.इज. औद्योगिक विकास की जीवन रेखा है तथा रोजगार अवसरों को बढ़ाने वाली है। एम.ओ.यूस. का लगभग 25 प्रतिशत (125) एम.एस.एम.इज सैक्टर में लगभग 20 प्रतिशत एम.एस.एमइज सैक्टर से संबन्धित थे। रियल एस्टेट सैक्टर में लगभग 20 प्रतिशत एम.ओ.यू. हस्ताक्षर हुए है जिसमें 1.1 लाख करोड़ रुपये का पूंजिनिवेश होगा। मैन्यूफैक्चरिंग/सर्विस सैक्टर में लगभग 80 प्रतिशत एम.ओ.यू हस्ताक्षर हुए हैं। जिनमें 4.7 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। जैसे ऑटो एंड ऑटो कम्पोनैंट, टैक्सटाईल व एप्रेल, फार्मास्यूटिकल व कैमिकल, शिक्षा व कोशल विकास, उर्जा/अक्षय उर्जा, एग्रो व फूड प्रोसैसिंग, फुटवियर व एसेसरीज, इलैक्ट्रोनिक्स, आईटी, आईटीस शामिल हैं। हरियाणा उतर भारत में इतनी मात्रा के निवेश को

[कैप्टन अभिमन्यु]

आकर्षित करने वाले प्रथम राज्य बन गया है तथा प्रथम अधिमान निवेश स्थान के रूप में उभर कर सामने आया है जबकि बहु क्षेत्रों वाले एम.ओ.यूस. राज्य के सभी भागों के विकास के लिए किए गए, 12 देशों की उपस्थिति तथा निवेशकों की भारी संख्या विशेषतया एम.एन.सी. की दो दिवसीय हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर सम्मिट-2016, राज्य सरकार की कार्य प्रणाली में उनके भरोसे को दर्शाती है।

10. **प्रमुख घोषणाऐं** :-

1. केन्द्रीय मन्त्री कपड़ा व उद्योग, माननीय संतोश कुमार गंगवार ने कपड़ा, परिधान, सहायक सामान, चमड़ा का हब के रूप में हरियाणा विषय पर एक विशेष सत्र के दौरान 180 करोड़ रूपये का टैक्सटाईल पार्क की घोषणा की। भारत सरकार इस परियोजना के लिए 40 करोड़ रुपये की सब्सिडी के अलावा राज्य में स्थापित किए जाने वाले इन्कूबेसन केन्द्र के लिए 14 करोड़ रुपये देगी।

2. केन्द्रीय रेलवे मन्त्री माननीय सुरेश प्रभु ने हरियाणा में एक रेल कोच फैक्ट्री की घोषणा की तथा सूचित किया कि भारत सरकार ने रेल कनैक्टिवीटी में विस्तार करने के लिए हरियाणा में वृहदनिवेश करने का निर्णय लिया है यह परियोजना में 120 एकड़ भूमि पर स्थापित की जानी नियोजित है।

3. केन्द्रीय सड़क एवं जहाज रानी मन्त्री माननीय नितिन गडकरी ने गुड़गांव में मर्टिनों परसोनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम की घोषणा की। इस परियोजना पर 980 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। उन्होने देहली में द्वारका से गुड़गांव में खेडकी डोला तक राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में एक सड़क के अतिरिक्त सोनीपत जिला में पल्ला से देहली में वजीराबाद तक प्रथम वाटर वे बनाने की भी घोषणा की।

4. माननीय वैंकया नायडू, केन्द्रीय शहरी विकास आवास, एवं शहरी गरीबी स्थानीय निकाय मन्त्री ने घोषणा की कि अमरूत योजना के अन्तर्गत हरियाणा के 18 शहरों को फंड दिया जायेगा।

5. श्री नरेश त्रेहान ने घोषणा की कि मेदान्ता एक मैडिकल स्कूल तथा 1000 बैड का हस्पताल स्थापित करेगा।

6. श्री सुभाष चन्द्र ने घोषणा की कि हरियाणा में 20000 सस्ती हाउसिंग इकाईयों में निवेश किया जायेगा।

7. मि0 वाग जियानलिग वाडा ने राज्य में 15000-20000 के बीच नोकरियाँ उत्पन्न करने के लिए निवेश करने की घोषणा की।

8. एच.ई. केन्जी हिरामात्सु, राजदूत, जापान: ने झज्जर में जापानी इन्टरग्रेटिड औद्योगिक टाउनशिप के लिए 30 बिलीयन यू.एस. डालर निवेश करने की घोषणा की।

9. श्री दलीप साघवी ने घोषणा की कि सन.फारमास्यूटीकल, गुड़गांव में एक फार्मा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करेगा।

10. श्री राजीव सिंह ने घोषणा की कि डी.एल.एफ. अगले 5 वर्षों में 20000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

11. श्री वाई.सी. देवेश्वर ने घोषणा की कि आई.टी.सी. खाद्य प्रोसैसिंग के क्षेत्र में 550 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

11. **उपलब्धियाँ**:

- सम्मेलन की 3 महीने की अवधि में सफल आयोजन (जबकि अन्य राज्यों ने इसे लगभग 1 वर्ष के समय में किया है, राज्य सरकार की सक्रियता तथा कार्य करने की भावना को दर्शाता है)
- हाल ही के विघ्नों के बावजूद सम्मेलन में निवेशकों द्वारा प्रशंसनीय भागीदारी केवल उस भरोसे को दर्शाती है जो उन्होंने वर्तमान सरकार पर किया है।
- हस्ताक्षर किये गये एम ओ यूस इस सकारात्मक प्रतिक्रिया को इंगित करते हैं कि राज्य सरकार की नीतियां उन्नतशील हैं। आगे इस सकारात्मकता का निर्माण करने के लिए सम्पर्क प्रबन्धकों की नियुक्तियां की गई हैं ताकि निवेशकों को सहायता मिल सके तथा इन उद्देश्यों की वास्तव में पूर्ति करना सुनिश्चित किया जा सके।
- इस आयोजन ने हरियाणा वासियों की प्रतिभा, प्रगतिशीलता तथा मेक इन इंडिया का हरियाणा को संचालक बनाने के लिए चुनौती स्वीकार करने की पुष्टि की है।
- इसकी आधारशीला तकनीकी भाग से मिली फीडबैक पर आधारित है जिसमें सैक्टर विशिष्ट नीतियों आईटी/इएसडीएम, टैक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, एयरोस्पेस/ डिफेंस इत्यादि की समस्याओं का समाधान किया जाता है।
- एमओयूस को एन सी आर (गुड़गांव, फरीदाबाद) के लिये हस्ताक्षरित होने के बारे में उठाये गये मुद्दे झूठे तथा आधारहीन है।

12. **कार्य योजना को लागू करना।**

एम.ओ.यूस. को परियोजनाओं में बदलने के लिए एच.एस.आई.आई.डी. सी. ने निवेशकों की सुविधा के लिए तथा एम.ओ.यूस. के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 16 सम्पर्क प्रबन्धक नियुक्त किए हैं। हरियाणा उद्यम उन्नययन बिल-2016, एक अधिनियम पहले ही तैयार कर लिया गया है तथा शीघ्र ही सदन ही सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि नियामक फ्रेमवर्क का सरलीकरण की व्यवस्था की जाये तथा निर्माताओं को हरियाणा राज्य में औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए उद्यमों की स्थापना के लिए आवश्यक एकल बिन्दु समयबद्ध स्वीकृतियाँ देकर सहायता दी जाये। 10 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं तथा 1 एकड़ भूमि से अधिक

[कैप्टन अभिमन्यु]

के सी.एल.यू. मामलों पर मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव, की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त क्रियान्वयन समिति द्वारा स्वीकृति दी जायेगी। 10 करोड़ तक के निवेश की परियोजनाएं तथा 1 एकड़ तक भूमि सी.एल.यू. मामलों पर स्वीकृति संबंधित जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तर स्वीकृति समिति द्वारा दी जायेगी। कार्यकारी अधिकार समिति एम.ओ.यूस.के क्रियान्वयन की समीक्षा समय-समय पर अपनी बैठक में करेगी। विकसित भूमि बैंक से भूमि उपलब्ध करवाई जायेगी। एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने औद्योगिक सम्पदाओं में खाली भूमि के बारे में निवेशकों को सूचना देने के लिए ऑनलाईन भू-सन्दर्भित प्रदर्शित प्रणाली भी आरम्भ की है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में एक ऐतिहासिक ग्लोबल इन्वैस्टर सम्मिट हैपनिंग हरियाणा के नाम से हुआ था उस बारे में माननीय विधायकगण श्री रणबीर सिंह, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल, श्री जाकिर हुसैन, श्री नगेन्द्र भडाना, श्री केहर सिंह और श्री उमेश अग्रवाल ने कालिंग अटैंशन के माध्यम से उसके बारे में कुछ विषय चर्चा के लिए उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के 50 वें साल में पहली बार कोई ग्लोबल इन्वैस्टर्ज सम्मिट हरियाणा प्रदेश ने आयोजित किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल आपको ध्यान होगा कि जब हमारी सरकार अपना जनादेश लेकर आई थी तो हमने हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण, विवेचन और समीक्षा करते हुए एक श्वेत पत्र के माध्यम से इसी महान सदन में उस पर अनेक प्रकार से चर्चा की थी। हरियाणा की आर्थिक स्थिति का वर्णन किया था और जो सच्चाई है उसको समझने की कोशिश की और उसको प्रकाशित करने की कोशिश की। इसके मोटे मोटे बिन्दु जो ध्यान में आए मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। कहीं न कहीं पिछले एक दशक में हरियाणा प्रदेश जो ओद्यौगिक विकास की दृष्टि से आगे बढ रहा था, उसकी उन्नति की रफ्तार में कमी आई है। हमारा टोटल जी.डी.पी. में मैनुफैक्चरिंग सैक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वह पिछले एक दशक में 2-3 प्रतिशत गिरा। इसके अलावा जो उसका ग्रोथ रेट था, बड़े हैरान करने वाली बात है कि 2008 के आस पास जो 8 प्रतिशत था वह घटकर 4 प्रतिशत हो गया है यानि मैनुफैक्चरिंग सैक्टर की जो राष्ट्रीय विकास दर थी उससे भी कम हो गई। हरियाणा में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से हरियाणा का औद्योगिक वातावरण बिगड़ गया। सरकार की अनदेखी हुई या कहीं न कहीं लाल फीताशाही हुई, या कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के विषय हुए या जो उद्योग और श्रमिक का आपसी सम्बंध है उनके बिगड़ने से मारूति और होंडा जैसे कांड हो गए और हरियाणा से उद्योग उस समय पलायन की सोच रहे थे या जो पुराने स्थापित उद्योग थे वे अपनी एक्सपैंशन की नई इकाईयां हरियाणा में लगाने की बजाय दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए सोच रहे थे। यह हरियाणा के लिए बहुत ही चिंता की बात थी। हरियाणा का नौजवान जो हमारी अढ़ाई करोड़ की जनसंख्या है उसमें यदि हम 2 प्रतिशत ग्रोथ बर्थ रेट में मानें तो हर साल 5 लाख नौजवान रोजगार के बाजार में शिक्षा पूरी करके आते हैं और उन्हें रोजगार की आवश्यकता पड़ती है। यह महान सदन जानता है कि जो पांच लाख लोग रोजगार के बाजार में आयेंगे औसतन प्रति वर्ष वे 7 हजार के आसपास ही सरकारी नौकरी में आ सकते हैं। उसके अतिरिक्त 4.90 लाख नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था करने का केवल मात्र माध्यम रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त

कृषि क्षेत्र में ऐसी संभावनाएं पैदा करना ताकि कृषि से आमदनी हो सके जिससे नौजवान अपना गुजर बसर कर सकें। अध्यक्ष महोदय, या तो कोई व्यापार करे या उसको उद्योग लगायें या स्वरोजगार के अवसर मिलें, उसके लिए हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में एक नई पूरी उद्योग की व्यवस्था को समझने के लिए सैक्रेटरी स्तर की कमेटी का गठन किया है। उनसे यह कहा गया है कि आप यह तय करके बतायें कि हरियाणा में उद्योगों की ऐसी स्थिति क्यों है कि रफ्तार कम हो रही है और इसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। उसके उपरांत हमने इंटरप्राईजिज प्रमोशन पॉलिसी बनाने का तय किया कि उद्यम प्रौत्साहन नीति हरियाणा के अंदर हम बनायें ताकि उद्योग की परमीशन से लेकर उसको चलाने तक, सफल बनाने तक आमूलचूल परिवर्तन किया जा सके। इस इंटरप्राईजिज प्रमोशन पॉलिसी के माध्यम से हमने अपने प्रदेश के पूरे औद्योगिक संगठनों और देश के औद्योगिक संगठनों से बात-चीत करके, उनसे मिल करके राय ली है कि कहां-कहां उनको दिक्कत आती है उसके बाद हमने इंटरप्राईजिज प्रमोशन पॉलिसी बनाई। इसी के साथ-साथ हमने हरियाणा के 40 से अधिक विभाग जिनको उद्योगों के लिए कोई न कोई क्लीयरैंस देनी पड़ती है या उद्योग का कहीं न कहीं उनसे संपर्क आता है। उनसे भी बात की गई है कि किस तरह से उद्यागों को सहूलियतें दी जा सकती हैं ताकि और ज्यादा उद्योग लग सकें। हमने उद्यागों को बढ़ावा देने के लिए भारी परिवर्तन की योजना बनाई है। हम हरियाणा सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और प्रोसीजर में भी परिवर्तन करने जा रहे हैं। यहां तक कि बिहेवियर आसपैक्ट में भी परिवर्तन करने की योजना बनाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में इंटरप्राईजिज प्रमोशन पॉलिसी के कुछ बिंदु बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश का जो पुराना ट्रैडीशनल कलस्टर उद्योग है चाहे वह पानीपत का हैंडलूम और होम फर्निसिंग का उद्योग है, चाहे वह जगाधरी का हमारा मैटल उद्योग है, चाहे अम्बाला का हमारा मिक्सचर और साईंटिफिक इन्सट्रूमैंट्स का उद्योग है। हम इस बारे में सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे उद्योग हैं उनको हम किस प्रकार से बनाकर रखें और कामयाब बनायें। हमारे गाईडिंग प्रिंसिपल के दो बिंदु रहे हैं कि ease of doing business को बढ़ाया जाए। यह महान सदन जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राज्यों से आह्वान किया है कि भारत की जो ease of doing business के पैरामीटर में 142 वी रैंकिंग उद्योगों को सहूलियते देने में है लेकिन हमें दो वर्ष के अंदर इसको 50वें नम्बर पर लेकर आना है तब जाकर हमारा देश पूरी दुनिया का manufacturing hub बन पायेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्किल इण्डिया, डिजिटल इण्डिया और मेक इन इण्डिया का नारा दिया है। उनका यह स्वप्न और संकल्प तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक राज्य अपने स्तर पर इस प्रकार के परिवर्तन न लेकर आएं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग के माध्यम से को-आपरेटिव फैडरेलिज्म का एक वातावरण देश में खड़ा किया है। वहीं एक और वातावरण कंपीटेटिव फैडरेलिज्म का खड़ा हुआ है। हर राज्य आपस में कंपीट कर रहा है कि उनके राज्य में अधिक से अधिक उद्योग लगें ताकि नौजवानों को उनमें रोजगार मिल सके। इस ease of doing business के लिए भारत सरकार ने लगभग 350 पैरामीटर तय किए हैं। पहले इसकी रैंकिंग साल दर साल होती थी अब यह रैंकिंग हर महीने होगी और मार्च के महीने से यह आनी शुरू हो गई है। इन तमाम बिंदुओं पर हरियाणा सरकार खरी उतरे उसके लिए हमने पूरे प्रयास किए हैं ताकि ease of doing business में हरियाणा प्रदेश अग्रणी रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था में परिवर्तन किया है। हमने तमाम इण्डस्ट्रीज़ की शुरूआत करने की सभी निर्धारित प्रक्रियाओं को सरल करने का काम किया है। इसी के तहत

[कैप्टन अभिमन्यु]

हमने अधिक से अधिक प्रक्रियाओं को ऑन लाईन करने का काम किया है। अपनी सभी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उद्योगपतियों को किसी भी सरकारी अधिकारी से मिलने की कोई आवश्यकता ही न पड़े ऐसा हमने पूरी की पूरी व्यवस्था को बनाया है। हमने अपने यहां यह प्रबंध किया है कि वह एक बार कम्प्यूटर पर अपनी दरख्वास्त लगा दे और उसको जिस प्रकार की भी क्लीरैंसिज़ की ज़रूरत है वे अपने आप हो जायेगी और उसको उसके लिए किसी दफ्तर, खिड़की और दरवाज़े पर नहीं जाना पड़ेगा। हमने पूरी प्रक्रिया को ऑन लाईन करके इसको सुनिश्चित कर दिया है। आपको यह बात जानकार बड़ी हैरानी होगी कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर तक की परमिशन को भी ऑन लाईन करने का काम किया है। मैं आपके और पूरे सदन की जानकारी में यह बात भी लाना चाहूंगा कि हमनें 10 करोड़ रूपये तक के निवेश की पॉवर और एक एकड़ तक की सी.एल.यू. की पॉवर जिला स्तर पर डी.सी. को दे दी है। जो हमारे से पहले की सरकारें थी उनमें यह पॉवर माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर थी लेकिन हमने इस व्यवस्था में सुधार करके इस पॉवर को डी.सी. को देने का काम किया है ताकि यह सारी की सारी प्रक्रिया सरल से सरलतम हो जाये। इस प्रकार से अब प्रदेश में 10 करोड़ रूपये तक का निवेश डी.सी. के स्तर पर तय होगा। इसके लिए किसी भी उद्योगपति को किसी भी प्रक्रिया को पूर्ण करने और किसी भी प्रकार का सर्टीफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी इंडस्ट्रीयलिस्ट को हमारे यहां पर अपनी इण्डस्ट्री लगाने से पहले लेबर का, पर्यावरण का और बॉयलर इंस्पैक्शन का एक बहुत बड़ा सर्टीफिकेट लेना होता था जिसके लिए बहुत बड़ा खेल पहले की सरकारों के समय में खेला जाता था। हमने इस सारी की सारी प्रक्रिया को सरल कर दिया है। हमने इण्डस्ट्रीज़ लगाने वाले को कहा है कि आपको किसी से परमिशन या सर्टीफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इस सबके बारे में एक सैल्फ सर्टीफिकेट लिखकर दे दीजिए कि मैं तमाम कानूनों का पालन करता हूं। अगर वह कानून के मुताबिक अपना काम नहीं करेगा तो फिर उस कोताही के लिए उसकी जिम्मेदारी फिक्स हो जायेगी लेकिन अगर वह सर्टीफिकेट दे देता है तो उस सर्टीफिकेट को हम मान्य कर देंगे। इसी प्रकार से सैल्फ सर्टीफिकेशन के मोड़ में हम गये। इसके अलावा दूसरी बात है कि इसी प्रकार की कुछ ज़रूरतें होंती हैं जिनमें सरकार के लिए यह ज़रूरी होता है कि वह अपनी रेगूलेटरी ड्यूटीज़ को निभाने का काम करे। जैसे अगर कोई मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ हो या फिर कोई सुरक्षा से ज़ड़ा हुआ विषय हो, इस प्रकार की कोई ऐसी गम्भीर इण्डस्ट्री हो सकती है जिसकी प्रॉपर चैकिंग करने की आवश्यकता पड़ती हो तो सरकार ने इस प्रकार मामले का वह काम उस सैल्फ सर्टीफिकेशन के बजाये जो उस मामले से सम्बंधित स्पैशलिस्ट लोग हैं उन लोगों को थर्ड पार्टी वैरीफिकेशन के नाम से इज़ाजत दे दी है कि कोई भी सम्बंधित इण्डस्ट्रीयलिस्ट इस बारे में सरकार से वैरीफिकेशन मत करवाये लेकिन थर्ड पार्टी से वैरीफाई करवाकर लें कि आपने उस संबंध में निर्धारित पूरे कानून का पालन किया है। हमने उसको भी मंजूर करने का काम किया है। जब पहली सरकारों के समय में पर्यावरण की इंस्पैक्शन हुआ करती थी, कुछेक इण्डस्ट्रीज़ ऐसी थी जिनको हर साल इंस्पैक्शन करवानी पड़ती थी। हमने जो ग्रीन इण्डस्ट्रीज़ हैं उनको 15 साल तक की एकमुश्त परमिशन दे दी है। इसी प्रकार से अब उनको 15 साल तक किसी प्रकार की इंसपैक्शन करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हर साल कोई भी इंसपैक्शन नहीं होगी। हमने विभिन्न प्रकार की इंसपैक्शंज़ के लिए 5, 10 और 15 साल का समय निर्धारित किया है। इस प्रकार से ऑरैंज, ग्रीन और रैड इण्डस्ट्रीज़ की

इंसपैक्शन की हमने समय सीमा तय कर दी है। इसके अलावा कोई लेबर डिपार्टमैंट हो, पर्यावरण विभाग हो या इण्डस्ट्री डिपार्टमैंट हो या इस प्रकार का कोई और विभाग हो इन विभागों में से कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से कहीं पर भी इंसपैक्शन करने के लिए नहीं जा सकेगा। इस इंसपैक्टरी राज़ की व्यवस्था को हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब जो सम्बंधित विभागों के प्रिंसीपल सैक्रेटरीज़ हैं उनकी अनुशंसा पर ऑन लाईन मंजूरी लेने के बाद ही कोई इंसपैक्शन अधिकारी किसी इण्डस्ट्रीयलिस्ट की इण्डस्ट्री की इंसपैक्शन के लिए जा सकेगा और अपनी मर्जी से कोई अधिकारी इंसपैक्शन के लिए नहीं जा सकेगा। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था को हमने बदलने का काम हमने किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह एक लम्बी प्रक्रिया चली है। हमारा पूरा एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन विभाग जो है वह ऐसा विभाग है जिससे पिछले समय में बिजनैस को बड़ी भारी परेशानियां हुआ करती थी। जो सी-फार्म है वह उनको हर रोज़ लेना पड़ता था। हर महीने तीन हज़ार के करीब सी-फार्म ऑफ लाईन प्राप्त करने के लिए लोगों को दफ्तरों में आकर मिलना पड़ता था और उसके लिए एप्लाई करना पड़ता था। हमें इस मामले में अनेकों शिकायतें मिलती थी कि इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। यह एक छोटा सा काम था लेकिन हमारी सरकार से पहले किसी ने भी इस छोटे से काम की प्रक्रिया को सरल करने के बारे में विचार नहीं किया। हमें यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि इस छोटे से काम की प्रक्रिया को भी हमारे प्रदेश में सरल क्यों नहीं किया गया। किसी ने भी इस बारे में विचार नहीं किया। यह सी-फार्म प्राप्त करना बहुत छोटा सा काम था लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी हो गई थी। हमने इस सी-फार्म की प्रक्रिया को भी ऑन लाईन किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस महान सदन के पटल पर यह बताना चाहता हूं कि पिछले 8-10 महीने में पांच लाख से ज्यादा सी-फार्म को ऑन लाईन करने के बाद बिना किसी एक भी पैसे की गड़बड़ के हम उद्योग और व्यापार जगत को जारी कर चुके हैं। 31 मार्च को हमारा पूरा एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन विभाग जो वैट डिपार्टमैंट को डील करता है उसकी सारी की सारी प्रक्रिया को ऑन लाईन कर दिया है। हमारी जितनी भी रिटर्न हैं वे सभी की सभी ऑन लाईन हैं और उनकी असैसमैंट भी ऑन लाईन है। इस हेतू किसी को भी आकर किसी से भी मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे यह आंकड़ा सही याद नहीं है इसलिए अगर मैं कोई गलती करूं तो उसके लिए हाऊस मुझे माफ करे। मैं इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि लगभग 2 लाख के करीब डीलर्ज अपनी रिटर्न को हमारे यहां ऑन लाईन दाखिल कर चुके हैं। जैसे-जैसे प्रशासन के कामों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है वैसे-वैसे ही बहुत सी चीज़े निकलकर सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर इण्डस्ट्री सैक्टर को अपनी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर किसी भी अन्य अधिकार से मिलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के वही अधिकारी जिनके ऊपर कभी अंगुलियां उठाई जाती थी कि ये ब्यूरोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं उन सभी अधिकारियों ने इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा सहयोग किया इसी से सारी की सारी व्यवस्था में इतना बड़ा परिवर्तन आया। यह देखकर हमें बड़ी भारी खुशी हुई। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों सहित हरेक अधिकारी व नीचे के स्तर तक का कर्मचारी माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न के साथ एक लाईन में खड़ा दिखाई दिया है। उनके मन में यही विश्वास परिलक्षित हो रहा था जैसे वे यह कहना चाह रहे हों कि अब हमको प्रदेश बदलना है और अब हमें देश को भी बदलना है। इसके कारण एक विश्वास बना। इंडस्ट्री में अविश्वास की खाई खड़ी हो गई थी और उनको लगता था

[कैप्टन अभिमन्यु]

कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो लोग हैं उनका काम इंडस्ट्री से सिर्फ लूटने-खसोटने का है। हमने उस अविश्वास को खत्म करके ऐसा वातावरण बनाया कि अब सरकार और सरकार के अधिकारी/कर्मचारी किसी गलत दृष्टि से नहीं बल्कि सहयोग की भूमिका में हैं, फैसिलिटेटिंग की भूमिका में हैं ताकि एक अच्छा कंजिनियल और कंड्यूसिव वातावरण बना सकें एक फ्रैंडली वातावरण बना सकें। अगर कोई यहाँ पर उद्योग लगाना चाहता है तो हम उसका इंतजार नहीं करेंगे कि वह आयेगा और हम उससे कहेंगे कि आईये और बताईये क्या करना चाहते हो बल्कि हम उनके पास जायेंगे और कहेंगे कि आप हरियाणा में आईये और उद्योग लगाईये। हमारे नौजवानों को रोजगार दीजिए और आने वाले समय में हरियाणा की आर्थिक उन्नति में सहयोग कीजिए। उससे एक विश्वास बना और जो ट्रस्ट डेफिसिट था उसको दूर किया गया। Confidence Building Measures जो हमने लगाये उससे पूरी इंडस्ट्रीज में एक मैसेज गया कि हरियाणा ने अपनी व्यवस्था को बदला है। तब जा कर हमने हैपनिंग हरियाणा सम्मिट के तहत इस first ever Global Investment meet of Haryana को आयोजित करने का निर्णय किया। अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्य भी ग्लोबल इन्वैस्टमैंट मीट करते रहे हैं परन्तु वे एक-एक साल की तैयारी के बाद उसको सफल कर पाते हैं लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने महज तीन महीने की तैयारी में ही इस सफल मीट का आयोजन किया है। इसी दौरान हरियाणा प्रदेश में आरक्षण आंदोलन का एक भयंकर तूफान आया लेकिन उस सबके बावजूद भी औद्योगिक निवेशकों के उत्साह के कारण हमें एक विश्वास मिला। उन्होंने हमें एक भरोसा दिया कि जो कुछ हरियाणा में बीता है इस प्रकार की प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाएं दुनिया के किसी भी कोने में आ सकती हैं लेकिन हमारा विश्वास इस बात में है कि हरियाणा की सरकार और हरियाणा के समाज ने इस वातावरण में जिस प्रकार का आचरण किया है, हरियाणा की सरकार ने इस आन्दोलन में इंडस्ट्रीज और बिजनेस का जिसका नुकसान हुआ उनको तुरन्त मुआवजा देने की पहल करके उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। इसी प्रकार से जो विदेशी निवेशक फंसे हुये थे उनको निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर लेकर निकालने में जो सहयोग और भूमिका सरकार की रही है उससे उनमें एक विश्वास पैदा हुआ है। हरियाणा के समाज ने एक अंदरूनी शक्ति का परिचय दिया कि इतना बड़ा तांडव होने के बाद भी वह समाज 3-4 दिन में ही फिर से अपने काम के लिए सड़क पर आगे बढ़ रहा था। ये जो रजीलियंस ऑफ दा सोसायटी हमारे स्टेट के लोगों की है और जो response of the administrative frame work है उसने इस बात के लिए विश्वास पैदा किया है कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर भविष्य के लिए इसके समाज, सरकार और इसकी प्रशासनिक मशीनरी के भरोसे पर हर कोई यहाँ उद्योग का निवेश कर सकता है। उस वातावरण को देखते हुए मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके आयोजन के समय को ले कर पुनर्विचार कर रहे थे तब विदेशों से हमारे निवेशकों के फोन आये और उन्होंने ई-मेल तथा पत्र लिख कर हमें विश्वास दिलाया कि आप हैपनिंग हरियाणा सम्मिट का आयोजन कीजिए हम सब आपके साथ हैं और इसका परिणाम हमको देखने को मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथियों ने एक शब्द का प्रयोग किया है। वे शब्द कहते हैं कि There is a great frustration and resentment in the people of Haryana because the programme of Haryana totally flopped. अब यह फ्रस्ट्रेशन और रिजैन्टमैंट हरियाणा के लोगों में है या विपक्ष के साथियों में ज्यादा है ? हरियाणा की पब्लिक को इस बात की खुशी हुई है कि इतने बड़े

तांडव के बाद कम से कम हरियाणा पटरी पर आया है। 12 देशों ने हरियाणा के पार्टनर बनना स्वीकार किया है और 15 देशों के 160 प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति से हरियाणा की जनता को यह भरोसा दिलाने के लिए वहाँ पर आये कि हम आपके साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने 357 एम.ओ.यू. के माध्यम से 5 लाख 84 हजार करोड़ रूपये के निवेश का प्रस्ताव किया है। मैं अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह 5 लाख 84 हजार करोड़ रूपये का निवेश या ग्लोबिल इन्वैस्टर्स सम्मिट हरियाणा में पहले आयोजित नहीं हो सकता था, क्या इतने बड़े स्तर पर उद्योग लगाने की सोच हरियाणा में पहले नहीं आ सकती थी ? यह इंडस्ट्रीज आ सकती थी लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ी सोच चाहिए थी लेकिन वह सोच हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने हमको दी है। अध्यक्ष महोदय, हमारे साथियों की इसके लिए चिन्ता थी क्योंकि इस कॉलिंग अटैन्शन नोटिस से पहले भी नेता प्रतिपक्ष और हमारे कई साथियों ने इसके कम्पोजीशन पर प्रश्न चिह्न लगाये थे कि 5 लाख 84 हजार करोड़ के निवेश में से 75 प्रतिशत निवेश तो रियल ऐस्टेट में है तथा इसमें तो केवल गुड़गांव में निवेश है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो हरियाणा के एम.ओ.यूज. हुए हैं, मान्यवर उसमें एक जानकारी तो ये दे दूं कि हमारे पंजाब राज्य ने भी पिछले दिनों प्रोग्रेसिव पंजाब के नाम से इन्वैस्टर सम्मिट किया। आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड, तमिलनाडू, और महाराष्ट्र ने भी यह इन्वैस्टर सम्मिट किया। पंजाब में केवल 390 एम.ओ.यूज. हुए हैं। इसमें कुल जो एम.ओ.यूज. हुए वह एक लाख 19 हजार 901 करोड़ रूपये के हुए थे। अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश के जो एम.ओ.यूज. हुए हैं मैं, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वह टोटल 5 लाख 83 हजार 885 करोड़ रूपये के हुए हैं। मैं इस महान सदन को यह जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें से रियल इस्टेट सैक्टर की जो इन्वेस्टमैंट है वह केवल 18.30 प्रतिशत है। इस सैक्टर में एक लाख 18 हजार 802 करोड़ रूपये पोटेंशियल एम्पलॉयमैंट के लिए हैं तथा एक लाख 6 हजार 854 करोड़ रूपये की वैल्यू के एम.ओ.यू. का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर के सैक्टर में 2 लाख 87 हजार 925 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इन्फ्रास्ट्रकचर में जहां एक ओर प्राईवेट कम्पनियां, विदेशी कम्पनियां आई हैं वहीं भारत की जो डी.एम.आई.सी.डी.सी. जो कम्पनी है उसके साथ हरियाणा सरकार ने जो समझौता किया है उसमें तीन अरली बर्ड प्रोजैक्ट में एक लाख 10 हजार करोड़ रूपये के निवेश की योजना का तो हमने भारत सरकार के साथ एम.ओ.यू. साईन किया है जो वास्तव में बहुत जल्दी क्रियान्वयन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसमें जैसा मैंने बताया एक तो ग्लोबल सिटी है इसमें जो एच.एस.आई.आई.डी.सी. से ज्वाईंट वैंचर में एस.सी.जैड. की जमीन वापिस आई है उसमें ग्लोबल सिटी का विकास किया जाएगा। इसके अलावा गुड़गांव से लेकर मानेसर से बावल तक एक मैट्रो रेल की परियोजना का भी इसमें प्रस्ताव है। इसके अलावा इन्टेग्रेटिड मल्टी मॉडल लोजिस्टिक हब जो दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कोरिडोर का एक अरली बर्ड प्रोजैक्ट है। इन तीन प्रोजैक्ट में एक लाख 10 हजार करोड़ रूपये का निवेश है। मान्यवर, आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूंगा कि मैनूफैक्चरिंग के अन्दर हमारे जो प्रस्ताव हैं वह कुल मिलाकर 53 प्रतिशत मैनूफैक्चरिंग सैक्टर का प्रस्ताव है। इसमें से सर्विसिज सैक्टर के 6 प्रतिशत अतिरिक्त और रिन्यूवेबल ऐनर्जी के सैक्टर में 21 प्रतिशत का प्रस्ताव उपलब्ध है, जिसको हम सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानकारी भी महान सदन को देना चाहूंगा कि यह पूरा 5 लाख 84 हजार करोड़ रूपये का निवेश है जिसमें आपने चिन्ता व्यक्त

[कैप्टन अभिमन्यु]

की थी कि हरियाणा प्रदेश का समुचित विकास होना चाहिए। पूरे प्रदेश का रिजनल डवैल्पमैंट बराबर होना चाहिए जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की चिन्ता रही है और हमारी इन्टरप्राईज प्रमोशन पॉलिसी में भी हमने इस बात की चिन्ता की है कि उद्योग उन क्षेत्रों मे लगने चाहिए जिनमें आज तक उद्योग नहीं लग पाए जिसके लिए हमने अपनी नीति में बहुत परिवर्तन किये हैं। अध्यक्ष महोदय हमने ऐसे लगभग 31 इन्डस्ट्रियल ब्लॉक आईडैंटिफाई किये हैं जिनमें इण्डस्ट्रीज की प्रेजेंस लगभग ना के बराबर है। उसमें अगर कोई इण्डस्ट्रीज लगाता है तो हमने उसके अन्दर अनेक प्रकार के प्रमोशनल इन्सैंटिव देने की परियोजना बनाई है इसमें जो सबसे बड़ी बात है उसमें सी.एल.यू. नहीं लेनी पड़ेगी उसमें कोई जमीन खरीदेगा तो उसकी स्टाम्प डयूटी भी वापिस देनी पड़ेगी। उसमें बिजली भी सस्ते दर पर दी जाएगी। उसमें लोन भी सस्ते दर पर दिया जाएगा। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से इतना निवेदन करूंगा कि कालिंग अटेंशन मोशन जिस विषय का है अभी उसी विषय पर चर्चा की जाए। अगर आप इस पर अलग से कालिंग अटैंशन मोशन लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर हम इसका जवाब देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें एक तरफ जो आम उपभोक्ता है उसको तो आप बिजली महंगी देते जा रहे हो उसके रेट आपने 40 से 50 प्रतिशत बढ़ा दिये और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जो उद्योग लगाने वाला व्यक्ति बाहर से आएगा उसके लिए आप कह रहें हैं कि उसको बिजली सस्ती दी जाएगी जो आपके प्रदेश का व्यक्ति है उसको तो आप महंगी बिजली दे रहे हो और जो बाहर का व्यक्ति है उसको आप बिजली सस्ती दे रहे हो। अध्यक्ष महोदय मेरा इसमें यह कहना है कि अगर बाहर वाले व्यक्ति को आप बिजली सस्ती दे रहे हैं तो अपने प्रदेश की जनता के लिए भी सस्ती कर दो।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महादय, जो नेता प्रतिपक्ष ने चिन्ता जताई है उनकी चिन्ता के साथ मैं अपने को भी सांझा करता हूं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय आपका आदेश इस कालिंग अटैंशन मोशन पर बात करने का हुआ है तो मैं अभी इण्डस्ट्रीज से संबंधित जो विषय हैं उन्हीं पर चर्चा करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, अभी आपकी जो चिन्ता थी वह इण्डस्ट्रीज पर ही थी और मंत्री जी इण्डस्ट्रीज पर ही अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमने इण्डस्ट्रीज के लिए क्या सस्ता किया और क्या-क्या सुविधाएं दी मंत्री जी तो अभी उसी पर बता रहे हैं।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश में पहली बार जो विदेशी बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं उनकी यहां निवेश लगाने की रूचि बनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिष्ट मंडल चीन गया वहां दुनिया का सबसे बड़ा जो रियल इस्टेट है वह इंडस्ट्रियल इस्टेट, थीम पार्क इंटरटेनमैंट्स तथा टाउनशिप को डिवैलप करता है और अपनी इंडस्ट्रियल इस्टेट में अनेक चाईनीज इंडस्ट्रीज को लेकर आने का भी उसका प्रस्ताव है। आज के दिन पूरे एशिया में रैंकिंग के हिसाब से सबसे अग्रणी वांडा ग्रुप का हरियाणा प्रदेश में 10 बिलियन डॉलर अर्थात 60 हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा का इंवेस्टमैंट करने का प्रस्ताव है। (इस समय मेजें थपथपाई गई) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इंवेस्टमैंट गुड़गांव में नहीं है बल्कि गुड़गांव से बाहर करने का प्रस्ताव है। इसी तरह चाईना की दूसरी कम्पनी है जिसका नाम है चाईना फॉरचूनर लैंड डिवेलपर्ज। 36000 एकड़ में बसी इस कम्पनी की इस्टेट को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी

के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल गया। यहां के माईनस टैम्प्रेचर में चाईना के युवा और युवतियों द्वारा हरियाणा प्रदेश की वेशभूषा पहनकर कार्यक्रम की प्रस्तुति ने हम सबको हैरान कर दिया। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने हरियाणा में निवेश करने से पहले हरियाणा की संस्कृति का करीब से अध्ययन कर लिया था। उन्होंने पूरे प्रोजैक्ट और प्रपोजल को बहुत ही गहराई के साथ वीडियों फिल्म के माध्यम से दिखाने का काम किया। ऐसा भी नहीं है कि यह कम्पनी केवल इंडस्ट्रियल इस्टेट ही डिवेलप करेंगी बल्कि 3000 एकड़ में फैली इसकी इंडस्ट्रियल इस्टेट में कौन-कौन सी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जायेंगी उन इंडस्ट्रीज के साथ भी चाईना में हमारी सरकार के साथ एम.ओ.यूज. साईन किये किए गए। अब दुनिया में यह बात पहुंच रही है कि चाईना की अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे संकुचित हो रही है, उसमें संकीर्णता आ रही है उसके कारण चाईना की कॉस्ट बढ़ रही है और चाईना में intellectual property rights जो होते हैं उसके उपर कहीं न कहीं खतरा है। चाईना के अन्दर नकली प्रोडक्ट्स की भरमार बढ़ रही है। यही वजह है कि चाईना के उद्योग जगत का विश्वास हिन्दुस्तान में बढ़ा है और मैनुफैक्चरिंग हब के नाम से प्रसिद्ध चाईना से दुनिया का ध्यान बदलकर हिन्दुस्तान की ओर जाने लगा है। इस स्थिति में चाईना के उद्योग समूहों को लगता है कि कहीं हमारे हाथ से यह इंडस्ट्रीज न निकल जाये। चाहे electronic system design and manufacturing की इंडस्ट्री है या वह अनेक इंडस्ट्रीज जिनके क्षेत्र में चायना अपनी लीडरशिप के रोल में है, उनको भी चाईना की इंडस्ट्रीज हिन्दुस्तान में शिफ्ट करना चाहती है और वह एक पूरा इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाकर उसमें आना चाहते हैं। मैं इस सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि जब हम जापान गये तो वहां हमने देखा कि वहां के निवेशकों के उत्साह में बहुत ज्यादा कमी थी। उनका आचरण देखकर ऐसा लगता था जैसेकि वह हरियाणा प्रदेश से नाराज हो। यही कारण रहा होगा कि उन्होंने हरियाणा से अपना जापनी टाउनशिप शिफ्ट करके उसे भिवाड़ी, राजस्थान में लगाया। 47 बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज इन्होंने वहां लगाई। उन्होंने हमको बताया कि हम हरियाणा प्रदेश को अपना घर समझते थे। अगर जापान की कंपनियों में आज भी रिसर्च करेंगे तो पायेंगे कि हरियाणा प्रदेश उनकी पहली पसन्द होती थी लेकिन कुछ ऐसे कारण बने कि तत्कालीन सरकार ने जापान के निवेशकों के साथ कुछ इस प्रकार से संबंध खराब किए कि जिसके कारण जापानी निवेशक हरियाणा छोड़कर जाने लगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के प्रयासों से क्योंकि जापान के अन्दर इन्होने इस प्रकार की छाप छोड़ी कि जापान के जो बड़े-बड़े निवेशक समूह थे जैसे जॉयका व जैट्रो जो हमसे हिन्दुस्तान में मिलने के लिए तैयार नहीं थे उन्होंने जब मुख्यमत्री श्री मनोहर लाल जी से मुलाकात की तो हमने उनमें एक विश्वास पैदा होते हुए देखा और यही कारण रहा कि इन निवेशकों ने हरियाणा प्रदेश को फिर से अपना घर बनाने का संकल्प लिया है। जापानी एम्बेस्डर सबसे पहले वह व्यक्ति थे जिन्होंने यह कहा कि हैपनिंग हरियाणा सम्मिट जरूर कराईये। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हमारा साथ दिया है, इतने साल हरियाणा ने हमारा पोषण किया है और हम इस दुख की घड़ी में हरियाणा के साथ खड़े हैं। यही कारण है कि जॉयका व जैट्रो के माध्यम से उन्होंने 30 बिलियन डॉलर के प्रस्ताव की हरियाणा प्रदेश में प्रक्रिया प्रारम्भ की है जिसका जिक्र अभी एम.ओ.यूज में नहीं है। इसके अतिरिक्त दो लाख करोड़ रूपये के अलग से निवेश की सोच जापान की हरियाणा प्रदेश में बनी है। आज ज्यादा से ज्यादा निवेश करने का वातावरण हरियाणा प्रदेश में बना है। छोटे जहाज तथा हैलीकॉप्टर्ज बनाने की इच्छुक यूरोप की एक विमान एयर स्पेश इंडस्ट्री है, इन्होंने रिसर्च के बाद हरियाणा प्रदेश में एविएशन इंडस्ट्री में निवेश करने

[कैप्टन अभिमन्यु]

की बात कही। हमने कहा कि प्रदेश में जितने एयरपोर्ट या एयरफील्ड हैं उनमें जाकर आप स्ट्डी करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस इंडस्ट्री से एक बात साफ तौर से कही कि वैसे तो आप हरियाणा प्रदेश में कही पर भी निवेश कर सकते हैं परन्तु मेरी दिली-इच्छा है कि आप दक्षिणी हरियाणा के महेन्द्रगढ़ के बाछौद के एयरस्ट्रिप में अगर इंडस्ट्री लगाते हैं और इस बैकवर्ड एरिया के नाते जो लाभ आप हरियाणा सरकार से डिमांड करना चाहेंगे, सरकार उसमें आपका पूरा सहयोग करेगी और उन्होंने महेन्द्रगढ़ के बाछौद में यह इंडस्ट्री लगाना मंजूर कर लिया। यह विमान एयर स्पेश कम्पनी जो छोटे जहाज और हेलीकॉप्टर्ज बनाती है वह 2000 करोड़ रूपये के साथ निवेश करेगी। (इस समय मेजे थपथपाई गई।) अभी इससे आगे और भी निवेश हरियाणा प्रदेश में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो एविएशन हब हैं यानि अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जोकि भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, उसमें भी कार्गो एयरपोर्ट की जरूरत है। दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का इन्दिरा गांधी एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्टस में से एक है। दिल्ली के आस-पास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के और एयरपोर्ट बनने चाहिएं। हम लंदन और न्यूयॉर्क जाते हैं तो वहां पर भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के तीन-तीन एयरपोर्ट शहर के आस-पास पाए जाते हैं। बिजिंग के आस-पास भी कईं एयरपोर्ट हैं इसलिए दिल्ली को भी जरूरत है। दिल्ली में भीड़ बढ़ने के कारण एयरक्राफ्ट लेट हो रहे हैं। उस नाते से अगर कार्गो एयरपोर्ट हम बनाते हैं तो सारा कार्गो ट्रैफिक दूसरी तरफ डायवर्ट होगा और हिसार में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट सफल होगा। इस सोच के साथ की ऐविएशन इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। जहाजों की बहुत-सी कम्पनियां हमारे देश में आ रही हैं। जहां तक हमारे डिफैंस के जहाजों की बात है, उनको भी रिपेयर की आवश्यकता पड़ती है। हिन्दुस्तान में भी स्किल इम्पलाईज अवेलेबल हो सकते हैं जो एविएशन या एयरोनॉटिकल इण्डस्ट्री को समझते हैं और इससे इस इण्डस्ट्रीज में जहाजों की रिपेयर का बहुत बड़ा बिजनैस हो सकता है। आज के दिन एशिया के दो-तीन देश जैसे दुबई और सिंगापुर में ही यह सुविधा उपलब्ध है। एम.आर.ओ. इण्डस्ट्रीज में भी बहुत बड़ा स्कोप है। हम चाहते हैं कि सिविल एयरक्राफ्ट और डिफैंस एयरक्राफ्ट सबकी मेंटीनेंस और रिपेयर की स्पेशियैलिटी सैन्टर हिसार में बने। बहुत जल्दी इस एविएशन हब की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना की और ज्यादा जानकारी भी इस महान सदन को दे दी जायेगी।

श्री हरि चन्द मिढ्ढा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि आज जीन्द के अंदर 25 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। काफी सारी इण्डस्ट्रीज पलायन करके चली गई और अब तक किसी भी सरकार ने इन फैक्ट्रियों की सुध नहीं ली है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन फैक्ट्रियों के बारे में बताने की कृपा करें।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ. साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि इस सरकार के कार्यकाल में ही जीन्द को औद्योगिक दृष्टि से फलते फूलते आप अपनी आंखों से देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में हाउसिंग और अर्बन डिवैल्पमैंट जिसको रीयल इस्टेट भी कहते हैं के तहत टोटल एम.ओ.यू. की वैल्यू 48.5 प्रतिशत थी। यहां पर 1 लाख 19 हजार 901 करोड़ रूपये के 190 एम.ओ.यू. साईन हुए थे जबकि हरियाणा प्रदेश में रियल इस्टेट में टोटल एम.ओ.यू. की वैल्यू 18.30 प्रतिशत है। हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्ज सम्मिट में 5.84 लाख करोड़ रूपये के निवेश के एम.ओ.यूज. साईन हुए हैं। राजस्थान

में पिछले दिनों रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट हुआ जिससे 3 लाख 21 हजार 199 करोड़ रूपये के 295 एम.ओ.यूज. बड़ी तैयारियों के बाद हुए थे। हरियाणा में पहली बार इतने कम समय के दौरान इतने एम.ओ.यू. साईन हुए हैं। मैं गुजरात के एम.ओ.यू. का केवल ब्रेकअप दे रहा हूँ, जो हमें सी.आई.आई और के.पी.एन.जी. कम्पनी से पता चला है कि सौ प्रतिशत एम.ओ.यूज. में से 40 प्रतिशत एम.ओ.यूज. रीयल इस्टेट सैक्टर में हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हरियाणा की सामान्य इण्डस्ट्रीज तो आगे बढ़े ही उसके साथ-साथ बेसिक इण्डस्ट्रीज भी मजबूत हो। हमारे यहां ऑटो इण्डस्ट्रीज से लगभग 50 हजार करोड़ रूपये का सालाना व्यवसाय हमारी मदर इण्डस्ट्रीज मारूति, होंडा, हीरो आदि से होता है। हमारी सोच है कि हरियाणा में और भी मदर इण्डस्ट्रीज स्थापित हों जिससे नये-नये उद्योग स्थापति हो सकें। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हरियाणा की इकॉनोमी मतलब ग्रोस डोमैस्टिक प्रोडक्ट का 57 प्रतिशत हिस्सा सर्विस सैक्टर से आता है। इन्टरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी के माध्यम से हॉस्पिटल, हैल्थ केयर, मेडिकल, टूरिज्म, एजुकेशन और हॉस्पीटैलिटी अनेक प्रकार की सर्विसिज़ को इण्डस्ट्रीज का स्टेटस दिया गया हैं। वे न केवल बड़ा रेवेन्यू देती हैं बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध करवाती हैं। इन सर्विसिज सैक्टर पर हमारा अलग से विशेष फोकस रहता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों ने जो चिंताएं प्रकट की हैं, मैंने आपके माध्यम से उन सभी चिंताओं के समाधान के लिए आश्वस्त करने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग और संकल्प से हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को औद्योगिक क्रांति के युग में रोजगार लेने के लिए दर-दर भटकना नहीं पड़ेगा और किसी के आगे हाथ फैलाना नही पड़ेगा इसलिए हरियाणा में औद्योगिक क्रांति आनी चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी सदस्यों के सहयोग की कामना करता हूं। (विघ्न)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने बड़े विस्तार से सारी बातों का जिक्र किया है। मंत्री जी ने सदन में बताया कि सरकार ने डिप्टी कमीशनर्स को पावर दी है और इन्सपैक्ट्री राज को समाप्त किया है। माननीय सदस्य डॉ. कमल गुप्ता मेरे अच्छे मित्र हैं। इन्होंने एक मुहावरा सुनाया था। यह मुहावरा इस हैपनिंग हरियाणा सम्मिट पर सही बैठता है क्योंकि ये "मुंगेरी लाल के हसीन सपने" देख रहे हैं। आज प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है। अभी हाल में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ जिसमें बड़े-बड़े शोरूम जला दिए गए, लोगों के घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई और कई युनिट्स को जला दिया गया। इतने गम्भीर माहौल में माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी सहजता से कह दिया कि कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं लेकिन इनके आने से जो नुक्सान होता है उससे किसी के मन में ग्लानी नहीं होती और न ही किसी के दिल को चोट पहुंचती है। बाढ़ या भूकम्प की वजह से घर टूटने से किसी को ग्लानि नहीं होती। हम अपनी झोपड़ी बनाकर भी रह सकते हैं लेकिन अगर कोई आपके घर के दरवाजे पर पत्थर मार दे या लात मारकर दरवाजा तोड़ दे तो उसकी मैंटेलिटी से जो तकलीफ होती है उसको केवल वही बता सकते हैं जो इस उपद्रव में भुक्तभोगी हैं। आज हरियाणा प्रदेश का माहौल जिस तरीके का है वह सभी के सामने है परंतु आज हरियाणा प्रदेश के निवासियों के मन में एक असुरक्षा की भावना भर चुकी है। प्रदेश सरकार को इस भावना को दूर करने के प्रयास करने चाहिएं। आज सरकार का दायित्व यही है कि वह प्रदेश में लगी हुई युनिट्स को पलायन करने

[श्री रणबीर गंगवा]

से रोके और लोगों को विश्वास दिलाए कि हम प्रदेश के माहौल को जल्दी से जल्दी ठीक करने का काम करेंगे और माहौल ठीक करने का क्या तरीका है ? प्रदेश में जो आंदोलन हुआ उसके दौरान ...(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अगर माहौल ठीक नहीं होगा तो ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रणबीर गंगवा जी, यह चर्चा हैपनिंग हरियाण समिट पर हो रही है लेकिन आप विषय से भटक गए हैं। मैंने जाट आरक्षण आंदोलन पर एडजर्नमंट मोशन स्वीकार कर रखा है। (विघ्न)

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष जी, मैं विषय से नहीं भटक रहा। हरियाणा प्रदेश में माहौल कैसे ठीक होगा ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रणबीर गंगवा जी, खराब माहौल के बावजूद सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में हैपनिंग हरियाणा समिट के कॉलिंग अटैंशन मोशन पर चर्चा होनी थी। माननीय सदस्यों का विचार था कि यह समिट सफल नहीं रहा और यदि सफल हुआ भी है तो केवल गुड़गांव में ही सफल हुआ है। हमने इसके जवाब में माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाया था कि यह समिट पूरी तरह से सफल रहा है और इसका तुलनात्मक अध्ययन करके भी बताया था। इनकी चिंता थी कि निवेश सिर्फ रियल इस्टेट सैक्टर में होगा। हमने इनको ब्रेक अप दिया है और दोबारा क्लेरिफिकेशन भी दी है। माननीय सदस्यों के विचारों से इनके मन में जो फ्रस्ट्रेशन है वही अभिव्यक्त हो रही है। (विघ्न) हमने 11 अगस्त को इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी चलाई थी। यह हमने इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराई है। 75 ब्लॉक ऐसे हैं जिनको हमने कैटेगरी 'सी" में डाला है। इसके लिए हमने इनसैनटिव भी दिए हैं। वैसे इंटरप्राइजिज प्रमोशन पॉलिसी के बारे में सारी जानकारी नेट पर उपलब्ध है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी हमारी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि कुछ साथी फ्रस्ट्रेशन में हैं।(विघ्न) इन्होंने जो कहा है मैं तो वही बात कर रहा हूं हम 100 फीसदी इस बात के हक में हैं कि हरियाणा में उद्योग आएं और उद्योग लगें। हरियाणा में बाहर से इन्वैस्टमैंट आए। हम तो चाहते हैं कि हमारा प्रदेश टैक्स फ्री प्रदेश बने ताकि लोगों के सामने जो कठिनाईयां हैं वे खत्म हो जाएं। अध्यक्ष महोदय, जिस किसी सदस्य ने कालिंग अटैंशन पर साइन करके दिए हैं उनको कहीं न कहीं इस बात को लेकर चिंता है और वे अपनी चिंता को जाहिर करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना चाहिए। मंत्री जी, आपने तो विस्तार से सारी बातें यहां इस तरह से प्रस्तुत कर दी कि जैसे सारी चीजें यहां कल आनी शुरू हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, हम एक साल तक इस चीज का इंतजार करेंगें । अगले साल जो बजट सैशन आएगा उसमें हम आपसे पूछेंगे कि मंत्री जी, आप जो लम्बी लम्बी डींगें सरकार की तरफ से हांक कर आए थे उनका क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, पहले भी सरकार की 10 हजार करोड़ रूपये की इन्वैस्टमैंट की बात कनाडा और यू.एस.ए. से हुई थी लेकिन उस का एक पैसा भी हरियाणा में नहीं आया (विघ्न) इसलिए जो हमारे साथी चिंता कर रहे हैं उनकी यह चिंता वाजिब है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, वे चिंता कानून और व्यवस्था पर कर रहे हैं जिस पर एडजर्नमैंट मोशन आया हुआ है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कोई भी इंडस्ट्री हरियाणा में आएगी तो कानून और व्यवस्था के इशू को वह जरूर देखेगी। बाहर से कोई निवेश करने यहां आएगा और यहां प्रदेश के हालात ठीक नहीं होंगे तो वह 100 फीसदी यहां इंडस्ट्री लगाने के बारे में दस बार सोचेगा। अध्यक्ष महोदय, आज फरीदाबाद से हिन्दुस्तान इलैक्ट्रोनिक्स कम्पनी जोकि बहुत बड़ी कम्पनी है और सरकार जिससे सारे कलपुर्जे खरीदती है वह प्लायन करके जा रही है। यह चिंता का विषय है इसलिए हमारे साथियों ने कालिग अटैंशन मोशन दिया था ताकि इस पर खुलकर चर्चा हो और सबको जानकारी हो कि हमारी क्या चिंता है। अध्यक्ष महोदय, हमारा विरोध नहीं है कि आपने हरियाणा हैपनिंग सम्मिट क्यों किया। यह बहुत अच्छी बात है कि आपने हरियाणा हैपनिंग ग्लोबल इन्वैस्टर सम्मिट का आयोजन किया। मैं तो कहूंगा कि आप इस तरह का एक और सम्मिट आयोजित करो। कोई और इन्वैस्टमैंट हरियाणा में आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हरियाणा में उद्योग लगें लेकिन उद्योग लगाने के लिए हालात तो बनने चाहिएं। इसी कारण ही हमारे साथी इस कालिंग अटैंशन के माध्यम से अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री(श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने यह कहने की कोशिश की है कि इन्वैस्टर्स कानून व्यवस्था को देखते हैं। पिछले दिनों जो कुछ हरियाणा प्रदेश में हुआ उसके बाद ही ये एम.ओ.यू. साइन हुए हैं। जो इन्वैस्टर्स हैं वे इस बात को जानते हैं कि किसी भी देश या प्रदेश में यह बात हो सकती है। इन्वैस्टर्स को चिंता तो तब होती है जब सरकार लूटने लग जाती है। पहली बार इन्वैस्टर्स का इस सरकार में भरोसा हुआ है। हरियाणा में इस बार वह सरकार है जिसमें कोई पैसा लेने वाला नहीं है। ये इन्वैस्टर्स तो सरकार द्वारा लूटे जाने पर भागने की कोशिश करते हैं। इन्वैस्टर्स सरकार द्वारा लूटे जाने के कारण ही यहां से प्लायन करने की सोचते थे। पहले सरकारें इन्वैस्टर्स को लूटने का काम किया करती थीं। अब इन्वैस्टर्स का सरकार में विश्वास बना है और इसी कारण ही इतने सारे एम.ओ.यूज. साइन हुए हैं और यह सम्मिट सक्सैस रहा है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विज साहब ने अभी चर्चा की कि इन्वैस्टर्स का हमारी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है इसीलिए ही एम.ओ.यूज. साइन हुए हैं। लेकिन आपकी पार्टी के ही विधायक श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का ब्यान आया था जो अभी भी सदन में बैठे हैं। मैंने पहले भी उनका ब्यान पढ़कर सुनाया था अब दोबारा पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा था कि जानमाल के नुकसान के लिए सरकार जिम्मेवार है। (विघ्न) आज भी वे यह बात कहते हैं। जब आपकी पार्टी के विधायक मानते हैं कि सरकार की वजह से जानमाल का नुकसान हुआ है तो उस स्टेट में इनवैस्टर कहां से आयेंगे ?

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, हरियाणा के लोगों पर और सरकार पर इनवैस्टर्ज ने विश्वास किया है इसलिए वे यहां उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं।

श्री तेजपाल तंवर : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनी जाये। हमारे बुजर्गों ने कहा है कि कोई जैसा बोयेगा, वैसा काटेगा। पहले क्या हुआ था कि किसानों को ऋण दे दिया जाता और फिर

[श्री तेजपाल तंवर]

माफ कर दिया जाता। फिर किसानों को कहा जाता कि बिजली के बिल न भरें उसके बाद वे भी माफ कर दिए गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इतने पैसे सरकार कहां से लेकर आयेगी। सरकार को पैसा उद्योगों से ही मिलता है। पूर्व की सरकारों ने प्रदेश में इस तरह का माहौल बना दिया था कि उद्योग यहां से प्लायन करने लगे। अब भी जिस क्षेत्र में उद्योगों को लूटा गया और आग के हवाले कर दिया गया उस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं लगायेगा। अध्यक्ष महोदय, उद्योगपति शांति चाहते हैं और जो हजारों लोग उनमें काम करते हैं उनकी जिंदगी की सलामती चाहते हैं। हमें सही बातों को मानना चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गंगवा जी, आप मोशन से हटकर दूसरी तरफ चले गये थे। कृपया आप विषय पर बोलें।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने कहा है कि इतना इनवैस्ट प्रदेश में और आयेगा लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज के माहौल में जो उद्योग प्लायन कर रहे हैं उनको तो बचाओ। आज हरियाणा प्रदेश में असुरक्षा की भावना आ गई है इसलिए उसको दूर करने का काम सरकार करे। इसी तरह से पिंजौर में जो एच.एम.टी. फैक्ट्री है उसके कर्मचारियों को 2014 से सैलरी नहीं मिली है। जिसके कारण उसके कर्मचारियों को अपने बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो रखा है। एच.एम.टी. में दस हजार के करीब कर्मचारी काम कर रहे हैं आज उनकी हालत बहुत दयनीय है। इस तरफ सरकार ध्यान देकर उनको सैलरी दिलवाये। उस फैक्ट्री की कीमत तीन हजार करोड़ रूपये के बराबर है परन्तु सरकार की अनदेखी की वजह से वह बंद होने के कगार पर है। वहां से लोग प्लायन करने की सोच रहे हैं। मंत्री जी इसके बारे में पुरी जानकारी सदन में दें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने मुझे कहा कि मैंने लाईन चेंज कर दी। मैंने लाईन चेंज इसलिए की क्योंकि वित्तमंत्री जी ने आंदोलन के दौरान जो नुक्सान हुआ उसके बाद जो प्राकृतिक आपदा आई उसको सहजता से लिया इससे लोगों को और तकलीफ होती है। (इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई)

श्री सुभाष बराला : उपाध्यक्ष महोदया, स्पीकर सर, जैसा कि विपक्ष के माननीय नेता श्री अभय सिंह जी चौटाला कह रहे थे कि हरियाणा में निवेश के लिए सही माहौल नहीं है जिसके कारण से फरीदाबाद से फैक्टरियां पलायन कर रही हैं। मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र टोहाना मैं कभी चौधरी देवी लाल जी ने भूना शूगर मिल लगवाई थी और उस शूगर मिल में एक दूसरी बहुत बड़ी प्राईवेट प्लाईवुड फैक्टरी थी। वह प्लाईवुड बनाती थी। इन दोनों के कारण वहां पर हज़ारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिला हुआ था। मैं बड़े नम्र शब्दों में चौटाला साहब को यह बात बताना चाहूंगा कि जब हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो उस समय ये दोनों फैक्टरियां बंद करने की बुनियाद रखी गई थी।

श्रीमती लतिका शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं एच.एम.टी. के बारे में यहां पर एक बात बताना चाहूंगी कि जितना प्रयास हमारी सरकार ने एच.एम.टी. को चलाने के लिए किया है उतना किसी भी अन्य सरकार ने नहीं किया। इसके लिए हमारे उद्योग मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और

माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। एच.एम.टी. की हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले बहुत बुरी हालत थी। हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी ने लगातार इसकी बेहतरी के लिए बैठकें की और वहां के कर्मचारियों के वेतन का बंदोबस्त किया। हमारे लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो टूल्ज़ वाला विभाग है वह तो हमारा हर हालत में सरवाईव करेगा ही करेगा। अब वह किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा। हमारा यह विभाग पिछली कांग्रेस की राज्य और केन्द्र सरकार के समय में बंद होने के कगार पर पहुंच गया था। यह आज हमारी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि वहां पर कर्मचारियों के हित के लिए बहुत अच्छे फैसले किये गये हैं। हमारी सरकार की सम्बंधित पक्षों से अभी भी मामले का बेहतर हल निकालने के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इसके लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, इस बारे में उद्योग मंत्री जी को जवाब दे चाहिए। क्या माननीय उद्योग मंत्री जी ने अपने विभाग का जवाब देने के लिए श्रीमती लतिका शर्मा जी को नियुक्त किया हुआ है?

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैं श्री अभय सिंह जी को यह बताना चाहूंगा कि श्रीमती लतिका शर्मा जी इस मामले में विशेष रूचि ले रही हैं इसलिए इनको भी इस बारे में पूरी जानकारी है। इसलिए ये सारी बातें वास्तविक तथ्यों के साथ यहां पर बता रही हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, हम तो बहन लतिका शर्मा जी को यही कहेंगे कि वे इस मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा करवायें और वहां के कर्मचारियों की ज्यादा से ज्यादा मांगों को मनवाने का काम करें।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो इन्होंने बताया कि हैपनिंग हरियाणा इंवैस्टरर्ज सम्मिट के अंदर 32 परसैंट निवेश गुड़गांव और फरीदाबाद में आयेगा और बाकी का पूरे हरियाणा में बंटेगा, इन्होंने परसैंटेज़ के साथ गुड़गांव और फरीदाबाद का तो जिक्र कर दिया लेकिन हरियाणा प्रदेश के अन्य जिलों का परसैंटेज के साथ कहीं भी जिक्र नहीं किया कि इस-इस जिले में इतने परसैंट निवेश आयेगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को यह बतना चाहूंगा कि जींद जिला एन.सी.आर. में आता है इसलिए मुझे बताया जाये कि जींद जिले में हैपनिंग हरियाणा सम्मिट के अंतर्गत कितने उद्योग लगेंगे ? कौन-कौन सी कम्पनियां यहां पर अपने उद्योग लगायेंगी और उनसे कितना रोज़गार यहां पर पैदा होगा ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो यह आप हैपनिंग हरियाणा सम्मिट के माध्यम से उद्योग लगायेंगे इनमें क्या हरियाणा के स्किल्ड और अस्किल्ड बेराज़गारों को कुछ रिजर्वेशन दी गई है कि इन उद्योगों में स्किल्ड और अनस्किल्ड की इतनी सीटें रिज़र्व होगी ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस हैपनिंग हरियाणा सम्मिट के अंतर्गत हरियाणा में जो भी उद्योग लगाये जायेगें उनमें हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा बच्चे लगने चाहिए जिससे हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी अधिक से अधिक दूर हो। इस बात की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसा न हो जाये की हैपनिंग हरियाणा सम्मिट के अंतर्गत लगने वाले उद्योंगों से हरियाणा प्रदेश में रोज़गार तो पैदा हो लेकिन उनमें हरियाणा के बेरोज़गार युवकों और युवतियों की अनदेखी हो जाये। इसकी सरकार के स्तर पर बराबर निगरानी होनी चाहिए। दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस इंवैस्टर मीट में कितने इंवैस्टर हरियाणा की बैकग्राऊंस से थे और जितने भी हरियाणा के

[श्री परमि-द्र सिंह ढुल]

लोगों ने इस हैपनिंग हरियाणा इंवैस्टर मीट में एम.ओ.यूज. पर साईन किये उन इंडस्ट्रीलिस्टस की क्या बैकग्राऊंड रही है ? संक्षेप में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा सरकार ने इन सभी इंवैस्टरस की वास्तविक वित्तिय स्थिति का आकलन किया है जिन्होंने विभिन्न प्रकार की एम.ओ.यूज. साईन किये हैं। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि ये एम.ओ.यूज़. वास्तव में कारगर सिद्ध हो जायेंगे या नहीं ?

प्रोफैसर रवीन्द्र बलियाला : स्पीकर सर, इस बारे में मेरी भी एक शंका है जिसका मैं माननीय वित्त मंत्री जी निवारण करवाना चाहूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हैपनिंग हरियाणा इंवैस्टर मीट के अंदर हरियाणा सरकार ने एम.ओ.यूज. साईन करवाये हैं, यह बहुत अच्छी बात है और जब इन एम.ओ.यूज. पर इफैक्टिवली काम होने लगेंगे तो फिर और भी अच्छी बात हो जायेगी। इससे हरियाणा प्रदेश में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन होगा। इस बारे में मेरी शंका यह है कि उस प्रोडक्शन को खरीदने वाले कौन लोग होंगे। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर यह हालात बने हुए हैं कि लोग बिजली का बिल भी नहीं भर पा रहे हैं। यह एक वास्तविक सच्चाई है कि आज हरियाणा प्रदेश में लोग रोज़ी रोटी को भी तरस रहे हैं। आज के दिन जो हरियाणा प्रदेश का गरीब आदमी है वह भर पेट रोटी भी नहीं खा सकता है। बिजली का बिल भरने के लिए भी उसको दूसरे लोगों से उधार लेना पड़ रहा है। वित्त मंत्री जी को यह बात अच्छी तरह से पता है कि कोई भी प्रोडक्शन तब तक कारकर नहीं है जब तक उसकी इफेक्टिव डिमाण्ड न हो। जब तक हमारे पास परचेज़र नहीं होगा तब तक हमारी किसी भी प्रोडक्शन का कोई भी महत्व नहीं है। मैं वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के लोगों की परचेजिंग पॉवर को बढ़ाने के लिए मंत्री जी और पूरी हरियाणा सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं। उपाध्यक्ष महोदया, इसके अलावा एक क्वैश्चन मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि यह जो एम.ओ.यूज. साईन किये हैं क्या इनमें यह इंश्योर किया गया है कि इनके अंदर हरियाणा के कितने परसैंट लोगों को रोज़गार दिया जायेगा। क्या हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसी प्रकार का विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा अर्थात क्या उस प्रकार की ट्रेनिंग हरियाणा प्रदेश के लोगों को दी जायेगी ताकि एम.ओ.यूज. साईन करने वाली कम्पनियों के अधिकारीगण हरियाणा प्रदेश के लोगों को रोज़गार दे सकें। मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने ऐसा किया है तभी इस मामले में हरियाणा प्रदेश के लोगों को इससे सही मायनों में फायदा होगा।

12:00 बजे **श्री उमेश अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदया, उद्योग मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव में जो ग्लोबल इन्वैस्टर्स सम्मिट का आयोजन किया उससे विशेष तौर पर गुड़गांव को जो लाभ हुआ उसके बारे में मैं एक-दो बातें बताना चाहूँगा। इस सम्मिट के आयोजन में 13 केन्द्रीय मंत्रियों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एन.पी.आर. और एस.पी.आर. को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा की। इसी प्रकार से मैटरिनों पर्सनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम धौला कुआं से मानेसर तक 980 करोड़ रूपये की लागत से बनेगा। इसी तरह से जो केबल कार की व्यवस्था दी है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जो 150 लाख करोड़ रूपये के एम.ओ.यू. साइन हुये हैं उनमें से 90 हजार करोड़ रूपये का निवेश गुड़गांव में ही होगा उसके लिए भी मैं इनका आभार

प्रकट करता हूँ। हमारे माननीय साथी श्री रणबीर गंगवा जी ने एक बात उठाई थी कि हरियाणा प्रदेश का माहौल खराब है और उसके बावजूद भी यह सम्मिट आयोजित हुआ उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुये एक बात कही थी जिस पर मुझे ऐतराज है। उन्होंने डी.एल.एफ. और M3M कम्पनी को कम्पेयर करते हुये कहा था कि M3M कम्पनी जिसने 45 हजार करोड़ रूपये का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है उसके पास उसका अपना घर भी नहीं है और उसने किसी के घर पर कब्जा किया हुआ है। मैं माननीय साथी श्री रणबीर गंगवा से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो इस तरह का वातावरण बनाया जाता है, जो लोग उद्योगों में निवेश करना चाहते हैं उनको धमकाने और डिमोरलाईज करने का कार्य किया जाता है इसके कारण से ही हरियाणा में पहले निवेश नहीं हुआ। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई थी कि इस निवेश में से ज्यादातर निवेश **** होने वाला तो क्या **** हरियाणा का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब **** में निवेश हो रहा है तो क्या उनको इस बात से ऐतराज है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने जो बोला है उसका जवाब या तो मुख्यमंत्री जी देंगे या वे इसके लिए किसी मंत्री को जवाब देने के लिए अथॉराईज करेंगे। माननीय साथी श्री उमेश अग्रवाल जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उमेश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने **** की बात कही है कि ज्यादातर निवेश वहीं पर होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने जो अभी कहा है कि मैंने **** और **** के लिए ऐसा कहा है उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : अभय सिंह जी, इन्होंने क्या कहा है?

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने कहा है कि मैंने अभिभाषण पर बोलते हुये यह कहा है कि ये सारे उद्योग **** में ही लगेंगे। मुझे सारे हरियाणा की चिन्ता है इनको अकेले **** की चिन्ता हो सकती है। अगर जो कुछ भी कहा है उसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे ये नहीं। इसलिए उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाये। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, वे शब्द सदन की कार्यवाही से निकाल दिये जायें।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, ये सरकार की बडाई करें इससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन ये बिना मतलब के कटाक्ष न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उमेश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ बल्कि इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने डी.एल.एफ. और M3M का जिक्र करते हुये कहा था कि उन्होंने किसी के घर पर कब्जा किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मुझे सच में चिन्ता है कि जिस आदमी के पास अपना घर भी नहीं है वह 45 हजार करोड़ रूपये का निवेश कहाँ से करेगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री उमेश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदया, यह चिन्ता करना सरकार का काम है, माननीय सदस्य का नहीं है। मैंने एक बात और कही थी कि ये जिस तरह की बात करते हैं उससे हरियाणा का वातावरण खराब होता है और उससे इन्वैस्टर्स हरियाणा से दूर भागते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, M3M का मालिक आज की तारीख में भी फ्रस्ट्रेट पुर्जा है और वह किराया भी नहीं देता है। अगर उस आदमी के एम.ओ.यू. पर साइन होंगे तो मुझे तो चिन्ता होगी ही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उमेश अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ****और ****में होने वाले निवेश का विरोध किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ****और ****हरियाणा का हिस्सा नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा को सबसे ज्यादा टैक्स गुड़गांव जिला देता है लगभाग 50 प्रतिशत टैक्स अकेला गुड़गांव जिला देता है और गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों मिलकर 70 प्रतिशत टैक्स देते हैं। अगर ऐसे शहरों के अन्दर उद्योग नहीं आएंगे तो कहां आएंगे। (शोर एवं व्यवधान) उनका विकास जरूरी है और जहां पर विकास हो रहा है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि वह प्रदेश का विकास कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी से सप्लीमैंट्री पूछिये।

श्री अभय सिंह चौटाला : **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री उमेश अग्रवाल : **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री उमेश अग्रवाल : **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : **** (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : ये जो सदस्य आपस में वाद-विवाद कर रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, ***** (शोर एवं व्यवधान)

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, दूसरों पर आरोप लगाने की बजाय इनको अपने अन्दर भी झांक कर देख लेना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष महोदया : अभय सिंह जी, सदन के किसी माननीय सदस्य पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, ***** (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन की मर्यादाओं को परे रखकर विपक्ष द्वारा सदन में अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस तरह की बातों को रिकॉर्ड पर न आने दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष महोदया : सदन में जो यह शोर शराबा हो रहा है इसका कोई भी अंश रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया,***** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, ***** (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : उपाध्यक्ष महोदया, सदन में किसी भी सदस्य के साथ इस तरह का बर्ताव करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, ***** (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया,***** (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष महोदया : जसविन्द्र जी, आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, ***** (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष महोदया : माननीय वित्त मंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, अत: आप सब प्लीज बैठने की कृपा करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष महोदया : अभय जी, माननीय वित्त मंत्री जी खड़े हुए हैं। एक बार उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिये, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहुत ही अच्छी चर्चा दोनों तरफ से हो रही थी। मुझे खेद है कि सदन का वातावरण इस तरह की प्रतिकूल स्थिति में आ पहुंचा। मैं सदन के सभी साथियों से निवेदन करता हूँ हमें इस सदन की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। हमारे कुछ साथी बहुत ही सीनियर हैं और इस महान सदन में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। हम तो पहली बार चुनकर इस सदन में पहुंचे हैं। इस महान सदन की गरिमा हम सबको बनाई रखनी चाहिए। हम इस सदन में व्यक्तिगत लांछन लगाने के लिए नहीं आये हैं। हरियाणा प्रदेश के अढ़ाई करोड़ लोगों की जन भावना अपने-अपने तरीके से हम अपने माध्यम से इस सदन में रखती है। सदन में हमारे विपक्ष के साथियों ने जो चिंताएं व्यक्त की हैं उनकी चिंताएं अपनी जगह बिल्कुल वाजिब हैं। आप आलोचना के माध्यम से अपना विपक्ष का फर्ज निभा रहे हैं क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की स्वस्थ आलोचना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपके एक-एक शब्द पर विचार करना तथा ध्यानपूर्वक कार्यवाही करना भी हमारा कर्त्तव्य है और हम उस कर्त्तव्य को जरूर निभायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया,. . .(विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, जाकिर हुसैन जी भी इस सदन के सीनियर मैम्बर हैं। वह जो कुछ भी पूछना या कहना चाह रहे हैं, उसको मैं भलीभांति जानता हूँ। मेवात के विकास को लेकर भाई नसीम अहमद और जाकिर हुसैन की बराबर चिंता बनी रहती है। आपकी चिंताएं वाजिब है (शोर एवं व्यवधान)

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो प्रदेश के हित की बात उठाना चाहता हूँ लेकिन कैप्टन साहब मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री जी ने बहुत ठीक फरमाया है कि विपक्ष की जो चिंता है वह उसके बारे में इस सदन में पूछ सकता है। यह बात पक्ष और विपक्ष की नहीं हे बल्कि मैं कहता हूँ कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य को अपने-अपने क्षेत्र की चिंता होती हैं और उसी चिंता के मद्देनज़र हमने एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया था। हमने किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप करने के लिए या इस सदन का माहौल खराब करने के लिए कोई बात नहीं की थी। मैंने जब खड़ा होकर माननीय उपाध्यक्ष महोदया से रिक्वैस्ट की थी तो केवल इस बात पर की थी कि मेरा नाम कोट करके कहा गया है कि मुझे गुड़गांव में उद्योग लगने पर आपत्ति है तो मैंने कहा कि मुझे ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त मैंने जो कोई भी बात माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कही थी उसका जवाब या तो मुख्यमंत्री जी स्वयं देंगे या फिर जिसकी जिम्मेवारी लगाई जायेगी वह देंगे। मेरी बात का जवाब देना किसी विधायक का काम नहीं है। विपक्षी बैंच की तरफ से जब कोई सवाल किया जाता है तो आपकी तरफ भी कई सीनियर साथी बैठे हैं, विज साहब बैठे है, उनको पूरी तरह से मालूम है कि विपक्षी बैंच का जवाब देना कंशर्ड मिनिस्टर की ही जिम्मेवारी होती है या फिर कंशर्ड मिनिस्टर किसी दूसरे मिनिस्टर की जिम्मेवारी लगा दे। उपाध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी के कईं विधायक बीच में खड़े होकर उत्तर देना शुरू कर देते हैं, यह गलत है। इसके बावजूद भी हम उनको यह नहीं कहते कि आप क्यों बोल रहे हो। हम सोचते हैं की ठीक है बोलने दो कम से कम यदि इनको किसी मैटर की जानकारी है तो यह हमें भी उससे अवगत करवा सकते हैं। हम इस सदन का कोई समय खराब नहीं करना चाहते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कम से इस बात का पता होना चाहिए कि सदन में ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे माहौल खराब होता हो। मैं अपनी पार्टी के सदस्यों की गारंटी लेता हूँ कि हमारा कोई भी सदस्य बेवजह किसी पर कटाक्ष नहीं करेगा और न किसी को गलत बात कहेगा। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहां सदन में बैठे हुए हैं अगर हमारी पार्टी के किसी सदस्य ने आप लोगों के विरूद्ध कोई व्यक्तिगत कटाक्ष किया हो तो आप बता दो ? हम उस बात के जिम्मेवार हैं लेकिन कम से कम अपने साथियों को यह बात जरूर समझाएं की माहौल खराब ना करें। हाउस का माहौल खराब होते हुए हमने कई बार देखे हैं। कांग्रेस शासनकाल के दौरान इस तरह के माहौल खराब होते थे। जो लोग हाउस के सदस्य नहीं थे, उनके नाम लेकर के और हमें हाउस से बाहर निकाल कर पता नहीं कितनी गलत ब्यानबाजी करते थे। उपाध्यक्ष महोदया, अगर आप पिछला रिकॉर्ड निकलवा कर देखेंगी तो आपको पता लगेगा कि जितनी भी हाउस की सीटिंग्ज हुई हैं, उनमें 80-90 प्रतिशत इसी तरह की ब्यानबाजी का प्रयोग हुआ है। मैं चाहता हूँ कि अब फिर उस तरह

का माहौल ना बने। मेरी जिम्मेवारी तो मेरी पार्टी के साथियों की है, ये अपनी तरफ से इस तरह का माहौल हाउस में नहीं बनायेंगे।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय प्रतिपक्ष की बातों से सदन को लगता है कि उनका पिछले 10 सालों का अनुभव बहुत कड़वा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान माननीय प्रतिपक्ष नेता को ऐसी ब्यानबाजी का सामना करना पड़ता था। उपाध्यक्ष महोदया, कभी-कभी बोलते हुए व्यवहार में अक्रामकता आ जाती है। लेकिन मैं सभी विधायकों से कहना चाहूँगा कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सभी सदस्यों का अपना-अपना एक अनुभव और विवेक होता है। सभी सदस्यों को हरियाणा प्रदेश के हितों की चिंता है। सभी विधायकों का काम करने का अपना-अपना तरीका और भाव होता है। यदि हम एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो दिक्कतं नहीं आएंगी। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे ख्याल से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। (विघ्न) इसलिए हाउस का समय बर्बाद ना किया जाये।

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, यदि माननीय मंत्री जी को लगे कि मैं आउट ऑट कंट्रोल बोल रहा हूँ तो आप मुझे बोलने के लिए मना कर देना। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट में स्किलड और अनस्किलड इम्पलोयमैंट के बारे में बहुत लम्बे चौड़े दावे किए गए हैं। इम्पलोयमैंट के दावों को लेकर के पूरे हरियाणा प्रदेश में चिंता है जैसे माननीय प्रतिपक्ष नेता ने भी कहा है कि हम एक वर्ष में देखेंगे कि यें चीजें आएगी या नहीं आएंगी? चिंता इस बात की भी है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं है और माननीय मंत्री जी ने भी कहीं इस प्रकार का जिक्र नहीं किया है। आज भी हरियाणा के इंजीनियरिंग कॉलेजिज़ एवं टैकनिक्ल कॉलेजिज में एक लाख से ज्यादा छात्रों की सीटें खाली पड़ी रहती हैं, यह रिकॉर्ड की बात है। उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से एक तो मैं यह जानना चाहूँगा कि ये सीटें क्यों खाली पड़ी हैं? इसके बारे में सरकार क्या प्रयास कर रही है? माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की घोषणा नं0 2 में 'सबका साथ-सबका विकास' की बात कही गई है। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी जो हरियाणा की ओर से राज्यसभा के सांसद है उन्होंने रेल कोच फैक्ट्री की घोषणा की है, जो बहुत पुरानी घोषणा है। क्या माननीय मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री से यह जानने की कोशिश की है कि यह इण्डस्ट्री मेवात क्षेत्र और गुड़गांव के विकास के लिए मेवात में क्यों नहीं लगाई जा सकती? उपाध्यक्ष महोदया, यह सभी लोग जानते हैं कि रेलवे से बहुत डिवैल्पमैंट होती। सन् 1970 के दशक में गुड़गांव से अलवर तक रेलवे लाइन बिछाने की जो घोषणा हो चुकी थी उसका क्या हुआ? रेल कोच फैक्ट्री हरियाणा के किसी इन्टीरियर क्षेत्र में लगे चाहे वह फिरोजपुर झिरका में लगे, चाहे वह महेन्द्रगढ़ में लगे, चाहे वह सिवानी में लगे, चाहे वह बाढडा में लगे और चाहे वह सिरसा में लगे तब इसका ज्यादा फायदा होगा। क्या आप यह बतायेंगे की यह रेल कोच फैक्ट्री कहां पर लगेगी? (विघ्न)

श्री अभय सिंह यादव : जाकिर हुसैन जी, इसमें फ्रेट कॉरीडोर और जोड़ दें (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, इसका फ्रेट कॉरीडोर से कोई मतलब नहीं है। (विघ्न) आपके ऊपर से हवाई जहाज तो रोज आ जा रहे हैं। महेन्द्रगढ़ के ऊपर हवाई अड्डा तो पहले ही लगा हुआ है। हमें लाभ तो तभी मिलेगा जब ट्रेन हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए रूकेगी।

[श्री जाकिर हुसैन]

अगर हमारे क्षेत्र से राजधानी एक्सप्रेस जाती है तो हमें उसका कोई फायदा नहीं है। यूं तो महेन्द्रगढ़-रिवाड़ी से ट्रेन रोज ही जाती हैं। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को इस विषय पर रेल मंत्री जी से बात करनी चाहिए। इससे हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। गुड़गांव जिले का यह अकेला ऐसा क्षेत्र है जहां पर रेल लाइन नहीं है। अगर इस क्षेत्र में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियां चलेंगी तो अलवर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है उससे यह क्षेत्र जुड़ सकेगा। तीसरी बात, किसी भी इंडस्ट्री के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पहली लॉ एंड ऑर्डर है, दूसरी रोड्स का इनफ्रॉस्ट्रक्चर और तीसरी चीज पीने का पानी और उद्योग के लिए प्रयोग होने वाला पानी है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत बात हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदया, लॉ एंड ऑर्डर के प्रदेश में जो हालात है उसे आप खुद जानती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज मेवात के रोज का मेव में आई.एम.टी. जो निर्माणाधीन है इसके बारे में सरकार लम्बे-चौड़े दावे कर रही है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आज तक वहां पर पीने के पानी की सुविधा क्यों नहीं है ? वहां पर पीने के पानी की लाइन बिछाने का अगले कई वर्षों तक भी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जिस क्षेत्र में पीने के पानी की ही सुविधा नहीं होगी वहां पर उद्योग भला कैसे लग सकता है। अगर कोई उद्योगपति वहां इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वह यह देखकर भाग जाएगा यहां के लोगों के लिए ही पीने का पानी नहीं है तो मुझे इंडस्ट्री के लिए पानी कहां से मिलेगा। सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे को लेकर बड़े-बड़े दावे किये जाते हैं। दस साल तक कांग्रेस शासन में रही परंतु के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे पर काम इसी सरकार के शासन काल में शुरू हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र नूंह से मुझे कई टेलीफोन आए कि के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे का काम शुरू हो गया है। लोगों को आशंका है कि के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे को पहाड़ पर प्राक्रतिक रिजर्व जंगलात, 5-7 सौ वर्ष पुरानी मस्जिद, और झरना आदि की तरफ से घुमाया जा रहा है। इससे वहां के लोगों में भारी रोष है। सरकार लोगों की भावनाओं के ऊपर से के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे का निर्माण नहीं कर सकती। मेरे क्षेत्र की जनता प्रकृति को नष्ट नहीं होने देगी। सरकार हमारे नैचुरल रिजर्व को खत्म करके कोई सड़क नहीं बना सकती। यह निर्माण कार्य क्षेत्र के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे के लिए घुसपैठी से फौड़बसई की पी.डब्ल्यू.डी. की रोड़ को इन्होंने खत्म कर दिया। इस के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे को बनाने के लिए पहले तो प्लान ठीक से नहीं बनाया गया और इस सड़क को बनाने का हमसे वादा किया गया था। के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे के उदघाटन से पहले मेवात के लाखों लोग इस चिंता में थे कि जो सड़क तावडू और नूंह को जोड़ती थी उस पर आज तक न तो अंडरपास बना है और न ही ओवर ब्रिज बना है। जबकि इनका बनाना स्टेट गवर्नमैंट और सैंटर गवर्नमैंट के नॉर्म्स में है लेकिन इस पर एक इंच भी निर्माण नहीं हुआ है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, सदन में हैपनिंग हरियाणा समिट के ऊपर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्य विषय से भटककर दूसरी बात कर रहे हैं। (विघ्न) एच.एस.आई.आई.डी.सी. और भी बहुत-से कार्य कर रही है। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने कहा है कि के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे को एच.एस.आई.आई.डी.सी. बना रही है। उस पुरानी सड़क को दोबारा नहीं बनाया जाएगा तो लोग के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे का निर्माण नहीं होने देंगे। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की भावना को पूरी तरह समझ गया हूँ। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूं कि हमें आपस में बैठकर इस इशू को सुलझा लेना चाहिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा है और उनके बाद हमारी महापंचायत यह विधान सभा है। सरकार लागों से वादा करके मुकर नहीं सकती और अगर ऐसा हुआ तो सरकार लोगों की भावनाओं के ऊपर से के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे का निर्माण कभी नहीं कर पाएगी।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश का ओद्यौगिक और आर्थिक विकास हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन ने चर्चा की है। अपवाद छोड़कर चर्चा बड़ी गम्भीर वातावरण में हुई है। बहुत महत्वपूर्ण विषय इस चर्चा के माध्यम से यहां उठाए गए हैं। हमारे सीनियर साथी भाई जसविन्द्र सिंह संधू जी ने सी. और डी. कैटेगरी के ब्लॉक्स की लिस्ट मांगी थी। वह लिस्ट मैंने इनको उपलब्ध करवा दी है। उपाध्यक्ष महोदया, यदि आप अनुमति दें तो मैं सदन के समय को बचाने के लिए उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं समझता। (विघ्न) मैं यह लिस्ट सदन के पटल पर उपलब्ध करवा देता हूं। वैसे यह जानकारी इंटरनैट पर भी उपलब्ध है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं नेता प्रतिपक्ष का दो मिनट का समय लेते हुए उनको कहना चाहूंगा कि आपका जो पहला विषय था उसके बारे में मैं जवाब देना जरूरी समझता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने चिंता व्यक्त की कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यू.एस.ए. का दौरा हुआ और उसमे 10 हजार करोड़ रूपये के एम.ओ.यूज. साइन हुए थे। चौटाला जी, आपकी समझ यह बनी होगी कि उसमें से एक पैसा भी निवेश के लिए हरियाणा में नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदया, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यूनाइटिड टैक्नोलोजी कम्पनी की कैरियर एयरकोन बरैटन नाम की कम्पनी ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है। एप्लाइड मैटीरियल कम्पनी के साथ हमारा समझौता हुआ और उन्होंने एक्सपैंशन का काम शुरू कर दिया है। हनीवैल नाम की कम्पनी के साथ हमारा समझौता हुआ था, हमने उसको जमीन दे दी है तथा उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, वहां जितने भी एम.ओ.यूज. साइन हुए थे उनमें से लगभग हर एम.ओ.यूज. के फोलो अप में काम हो रहा है। इसी तरीके से इनको चिंता थी कि जो इतने सारे एम.ओ.यूज. साइन हुए हैं इनको क्रियान्वयन कैसे कराया जाएगा तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जो इनका काम है वह अब शुरू होगा। जितने लोगों ने ये प्रस्ताव दिए थे उनके साथ सरकार ने एक मैमोरण्डम आफ अंडरस्टैडिंग साइन किया है कि हम मिलकर एक समझौता करते हैं कि जो निवेश का प्रस्ताव आप लेकर आ रहे हैं, इस प्रस्ताव को क्रियान्वयन करने में हम परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगें। यही मैमोरण्डम आफ अंडरस्टैडिंग का भाव होता है। उस नाते से सरकार ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमैंट की तरफ से 16 रिलेशनशिप मैनेजर्स की नियुक्ति की है। हम इन रिलेशनशिप मैनेजर्स को तमाम 357 या 359 एम.ओ.यूज. बांटकर दे रहे हैं। 357 और 359 मैंने दो आंकड़े दिए हैं इनमें से कोई एक आंकड़ा है और मैं जिम्मेवारी लेते हुए अपनी इस गलती के लिए सदन से माफी चाहूंगा। ये 16 रिलेशनशिप मैनेजर

[कैप्टन अभिमन्यु]

एक एक एम.ओ.यू. साइन करने वाले उद्योगपति के साथ बातचीत करेंगे ताकि काम को आगे बढ़ाया जाए। हमारी डेली बेसिज पर इन एम.ओ.यूज. पर फोलो अप करने की योजना है। सदन के दौरान हमने इसके ऊपर एक समीक्षा बैठक की है ताकि वह काम भी आगे बढ़ता रहना चाहिए और सदन का काम भी चलता रहना चाहिए और सरकार का काम भी चलता रहना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार का एक गम्भीर प्रयास होगा कि ये जितने भी एम.ओ.यूज. साइन हुए हैं उन सबको क्रियान्वयन की दिशा में लेकर जाएं तथा और भी इस तरह के एम.ओ.यूज. हम भविष्य में साइन करेंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, मैंने तो पहले भी कहा है कि हम तो सरकार से इस बारे में एक साल के बाद बात करेंगे।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ये एक साल बाद इस बारे में बात करेंगे तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि हम इतने काम करते चले जाएंगे कि आप अनेकों वर्षो तक देखते चले जाएंगे। रणबीर सिंह जी, नलवा से विधायक हैं उन्होंने बड़े भावपूर्ण तरीके से कहा है कि हमने बड़ी सहजता से इतने बड़े कांड को लिया। (विघ्न) नलवा जी, मैं अपना सब कुछ फूंकवा कर बैठा हूं फिर भी आपके साथ काम में लगा हुआ हूं। व्यक्तिगत पीड़ाएं और दर्द अपनी जगह पर हैं लेकिन ये काम आगे बढ़ते रहने चाहिएं। हमें हरियाणा को आगे बढ़ाना है और जो जिम्मेदारी प्रदेश ने हम को दी उसको निभाते हुए हमें आगे बढ़ना है। यह सहजता के शब्द हमारे नहीं थे। मैंने ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकारा है कि जब मुख्यमंत्री और हम सब इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि इस हैपनिंग हरियाणा समिट को इन वर्तमान परिस्थितियों में करना है या नहीं क्योंकि एक ऐसा वातावरण था जिसमें जापान के ऐम्बैसडर के साथ ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक विश्वास बहाली उनके साथ हुई है। जापान के लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री जी के व्यवहार, भाषा और तरीके को सराह है। मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयासों के बात जापान के ऐम्बैसडर ने आगे बढ़कर यह कहा कि हम आपके आभारी हैं कि इस कष्ट के समय में सरकार का जो आचरण रहा है, वह सराहनीय है। इस कष्ट के समय में बिजनैस और इण्डस्ट्री को सरकार ने अपने हाल पर नहीं छोड़ा। सरकार ने पहले दिन से ही मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार के अधिकारियों ने एक-एक घर जाकर आकलन करके मुआवजा दिया गया है। यह जो सरकार का आचरण है और समाज की जो अंदरूनी शक्ति उभर कर आई और फिर से हरियाणा को पटरी पर लाने की भूमिका निभाई। इन दोनों बातों के समावेश ने निवेशकों में एक विश्वास पैदा किया है। जिस राज्य की व्यवस्था और समाज औद्योगिक निवेश के पक्ष में हैं यह बहुत सकारात्मक सोच है जिसके कारण यह माहौल बना है। हम पूरी तरह से गंभीर और संवेदन हैं और वह काम भी अपनी दिशा में आगे बढ़ेगा और निर्माण का काम भी आगे बढ़ेगा। एच.एम.टी. का विषय आया जो कि पहले भी आया था। माननीय सदस्य ने आंकड़ा दे दिया कि एम.एम.टी. पिंजौर की कीमत 3 हजार करोड़ रूपये है। हमारी भारत सरकार के साथ जो त्रिपक्षीय वार्ता हुई है। जिसमें एच.एम.टी. के कर्मचारी, हरियाणा सरकार और भारत सरकार के मंत्री से लेकर सचिव स्तर के अधिकारी उस वार्ता में शामिल थे। उस वार्ता में विस्तार से इसको लेकर चर्चा हुई।

माननीय सदस्य जो 3 हजार करोड़ रूपये कीमत बता रहे हैं यदि ये उसका तीसरा हिस्सा भी दिलवा दें तो हम काम चला देंगे। कभी-कभी हम आंकड़े फेंक देते हैं। हमें जिम्मेवारी से इन बातों को लेना होगा। विपक्ष के साथी सहयोग करें, हम इनके सहयोग का स्वागत करेंगे। एच.एम.टी. हरियाणा के बहुत महत्वपूर्ण जगह पर लगा हुआ उद्योग है। हम इसको बचाना भी चाहते हैं और इसकी जगह दूसरा उद्योग लगाना भी चाहते हैं। इसको लेकर तीन-चार विकल्पों पर केन्द्र सरकार और हम काम कर रहे हैं। हमें उन कर्मचारियों की भी चिंता है जिनकी तनख्वाह रूकी हुई है वह उनको मिले। भारत सरकार ने उसमें पहली किस्त देने का आश्वासन भी हमें दिया है। (इस समय श्री अध्यक्ष चेयर पर आसीन हुए।) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय साथियों ने समिट में आये निवेश की जिलेवार जानकारी भी मांगी है। गुड़गांव का मैंने 90 हजार करोड़ रूपये बताया था। जो मलटीपल लोकेशंज हैं, जो अलग-अलग जिलों में होंगी उनका 2 हजार 39 लाख करोड़ रूपये का निवेश आया है। इसके अतिरिक्त जो yet to be decided हैं वे 82300 करोड़ रूपये का निवेश आया है। इसी तरह से सोनीपत के लिए 72508 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है। मेवात के लिए 60100 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है जिसमें 51 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए जाकिर जी और नसीम अहमद जी खुश भी होंगे और मेजें थपथपायेंगे।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेवात में पीने के पानी की बहुत समस्या है उसका समाधान किस तरह से किया जायेगा। उद्योग वहां तभी लगेंगे जब पीने के पानी की व्यवस्था होगी।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, वे सारी व्यवस्थाएं भी की जायेंगी। इसी तरह से फरीदाबाद में 10396 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है। इसी तरह से महेन्द्रगढ़ में 2146 करोड़ रूपये का निवेश प्रस्तावित है। सभी जिलों का बताने की बजाय मैंने मोटा-मोटा बताया है। (विघ्न) जींद जिले का अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जो दो कैटेगरीज मलटीपल लोकेशंज और yet to be decided हैं उनमें आयेगा। मैं पूरे सदन का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि Happening Haryana Summit में जो एम.ओ.यूज. साईन हुए हैं वे आप सभी के सहयोग से साईन हुए हैं।

सदन के कार्य में परिवर्तन करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, एक ध्यानाकर्षण सूचना न.31 जो ओलावृष्टि से सम्बंधित थी और 21 मार्च, 2016 के लिए स्वीकृत थी उसे 21 मार्च, 2016 को बजट पेश होने की वजह से 28 मार्च, 2016 को लिया जायेगा। इसी प्रकार से एक स्थगन प्रस्ताव न. 2 जो राज्य में तत्काल की हिंसक घटनाओं से सम्बंधित है वह भी 21 मार्च, 2016 के लिए स्वीकृत था वह भी अब 22 मार्च, 2016 को लिया जायेगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा। श्री मनीष ग्रोवर जी सदन में इस चर्चा पर अपनी बात रखेंगे।

श्री मनीष ग्रोवर (रोहतक) : स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्पीकर सर, महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने 1 घंटा और 40 मिनट में 44 पन्नों का अपना अभिभाषण हम सभी माननीय सदस्यों को सम्बोधित किया। उस दिन आपने यह कहा था कि कोई भी विधायक किसी भी सीट पर बैठ सकता है। मैं उस दिन बहन सीमा त्रिखा के साथ वाली सीट पर बैठ गया था। राव नरबीर सिंह जी उस दिन सदन में उपस्थित नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में मैंने सोचा कि क्यों न आज मंत्री जी वाली सीट पर बैठकर देखा जाये। इसलिए उस दिन मैं उनके लिए निर्धारित सीट पर बैठ गया। जब महामहिम राज्यपाल महोदय जी के 1 घंटा 40 मिनट के अभिभाषण के दौरान मैं बहन सीमा त्रिखा जी के साथ बैठा तो महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण सुनने के बाद बहन सीमा त्रिखा जी ने मुझे कहा कि हमारी सरकार ने डेढ़ साल के छोटे से समय के अंदर विकास के इतने कार्य करवा दिये और इतने विकास कार्यों की रूप रेखा तैयार कर दी जिसका ब्यौरा 44 पन्नों पर आया और महामहिम राज्यपाल महोदय जी को उसको पढ़ने के लिए 1 घंटा 40 मिनट का समय लगा। हरियाणा प्रदेश की अढ़ाई करोड़ जनता की भावनाओं इसमें भरी हुई हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इससे पहले की सरकारें भी ऐसे काम करती थी। उनके द्वारा ऐसे पूछने पर मैंने उनसे कहा कि पहले की सरकारें भी काम करती थी। मैंने उनसे यह भी कहा कि हमारी सरकार से पहले जितनी भी सरकारें हरियाणा प्रदेश में रही हैं उनके सोचने का दायरा सिर्फ और सिर्फ अपने जिले तक ही सीमित था और जिले के बाद उनकी सोच यह होती थी कि अपने लिए हरियाणा प्रदेश में एक विधान सभा क्षेत्र को अपने व अपने परिवार के लिए सदा-सदा के लिए पक्का कर लिया जाये परन्तु हमारी सरकार की सोच इतनी संकुचित नहीं है बल्कि हमारी सरकार ने तो समस्त हरियाणा प्रदेश की अढ़ाई करोड़ जनता की भावनाओं को देखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो और चाहे उद्योग और व्यापार जगत हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो सभी के बारे में इस 44 पन्नों के अभिभाषण के अंदर पूरी की पूरी चिंता ज़ाहिर की गई है। मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसा करके हमारी सरकार ने एक करिश्मा करके दिखा दिया है। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, ***

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र संधू जी की कोई बात रिकार्ड न की जाये क्योंकि यह बिना परमिशन के बोल रहे हैं। संधू जी, आप कृपया करके बैठ जाईये और माननीय सदस्य श्री मनीष ग्रोवर जी को अपनी बात कहने दें।

श्री मनीष ग्रोवर : स्पीकर सर, मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश की पूरी अढ़ाई करोड जनता की चिंता की है। मेरे से पहले भी आदरणीय मिड्ढा जी स्वयं कह रहे थे कि उनका जींद जिला पिछड़ा हुआ है। वे यहां पर अपने भानजे के सामने अपनी बात रख रहे थे। मैं यह बात उसी एंगल से कह रहा हूं कि जो सरकारें पिछले समय में हरियाणा में सत्तासीन रही हैं उनकी चिंता सिर्फ अपने जिले तक ही सीमित होती थी लेकिन हमारी सरकार पूरी हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

को ध्यान में रखते हए समान रूप से आगे बढ़ी है जिसका ब्यौरा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिया गया है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी सुधारों की बात हो हमारे काबित शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के प्रगतिशील और कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के शिक्षा विभाग की कमान बड़ी कुशलता से सम्भाले हुए हैं और हमें उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का शिक्षा विभाग नई-नई बुलंदियों को छुयेगा। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश में सारी की सारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर से बेहतर और विश्व स्तरीय बनाने के लिए हमारी सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ईमानदारीपूर्वक दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। यह बात हमारे सभी विपक्ष के साथियों ने भी दिल से स्वीकार की है कि जहां-जहां पर भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी जाते हैं वहां-वहां के सारी अस्पतालों की हालत पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यहां पर हमारे माननीय कृषि एवं सिंचाई मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी भी बैठे हैं। वे भी उन्हें सौंपे गये सभी विभागों का कामकाज बेहतर तरीके से करते हुए हरियाणा की पहचान पूरे देश ही नहीं अपितु विश्व स्तरीय बनाने की ओर अग्रसर हैं। जब पंचायत के चुनावों से पहले उम्मीदवारों की शिक्षा से सम्बन्धित बिल यहां पर आया तो हमारी विरोधियों ने इसके लिए पूरा ज़ोर लगाया कि जो पंचायत के उम्मीदवारों के लिए हमारी सरकार शिक्षा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने के लिए बिल लेकर आए हैं यह किसी भी सूरत में पास नहीं होना चाहिए लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद भी हमारी सरकार यहां पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए शिक्षा का बिल लेकर आई जिसको कोर्ट के अंदर स्टे मिली लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी लम्बी बहस के बाद हमारी सरकार के निर्णय पर अपनी सहमति की मोहर लगाई तो सभी गांवों में यह चर्चा होने लगी कि "छोरा पड़ा है मनोहर लाल, जो कहता है वह करके दिखाता है।" (शोर एवं व्यवधान) हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जुबान के पक्के हैं और जो भी कहते हैं उसे हर हालत में करके दिखाते हैं उसके लिए चाहे उन्हें कोई भी बलिदान करना पड़े और चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पूरे हरियाणा प्रदेश की पंचायतों के चुनाव जिस प्रकार बिना किसी लड़ाई-झगड़े और दंगे फसाद के शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो गये इस सबका श्रेय हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे मंत्री मण्डल, पूरी सरकार और पूरे प्रशासन को जाता है। इसी तरह से अगर उद्योगों की बात की जाये तो उसके बारे में अभी सदन में एक घण्टे तक चर्चा हुई है और हरियाणा में 5 लाख 84 हजार करोड़ रूपये का निवेश होने वाला है। आज प्रदेश में जो औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है उससे जनता में एक अच्छा सन्देश गया है। हमने वह समय भी देखा है जब यहाँ से उद्योग पलायन करके जा रहे थे और उनको रोका भी नहीं जा रहा था। इसी तरह से हमारे विपक्ष के साथी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने गुण्डाराज खत्म किया है, हमने गुण्डों को प्रदेश से भगाया है। फरवरी महीने में दुर्भाग्य से जो दुर्घटना घटी थी उसके लिए मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं अधिकारी जिम्मेदार हो सकते हैं। हमारे बड़े भाई श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास की जो चिन्ता थी वह बिल्कुल जायज थी लेकिन हमारी सरकार की नीयत साफ थी। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि सरकार कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं देगी। इसी प्रकार से रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाईन जो स्वीकृत हुई है जिसके बारे में श्री कमल गुप्ता जी ने भी उल्लेख किया था उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। उसमें सैक्शन 9 लगा कर अवार्ड देकर शीघ्र काम शुरू किया

[श्री मनीष ग्रोवर]

जाये। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी जो अपने आपको किसानों का मसीहा कहते थे, रोहतक से गोहाना रेलवे लाईन शहर से बाहर गांवों में से निकाल रहे थे जिससे 7 गांवों की किसानों की कीमती जमीन खराब हो जाती जिसमें सिंहपुरा, समरगोपालपुर, सुन्दरपुर, टिटौली, अहमदपुर, चमारियाँ और मकड़ौली गांवों की जमीन आ रही थी। जब उन किसानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई तो किसानों को इस बात का आश्वासन दिया गया कि हम किसानों की जमीन रेलवे लाईन के कारण खराब नहीं होने देंगे। रोहतक से गोहाना रेलवे लाईन पर रोहतक में 3 रेलवे फाटक आते हैं जहाँ पर जाम लगता है जिनसे मुक्ति दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र और राज्य सरकार की तरफ से 300 करोड़ रूपये की योजना ला कर किसानों की जमीन बचाई है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा,स्वास्थ्य और पंचायतों पर विशेष जोर दिया गया है तथा हमारी सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि पहले जो केन्द्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी उसने वक्फ बोर्ड की जमीन पर 60 साल से काबिज लोगों को नोटिस भेज रखे हैं जिससे लोग परेशान हैं इसलिए उस काले कानून को रद्द किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर झिरका): अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पहले के जो दो तीन पैराज हैं मैं उन पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन हमारा साल में एक बार राज्यपाल महोदय का अभिभाषण आता है जो पूरे प्रदेश के विकास की गति और सरकार के नजरिये के बारे में बताता है कि सरकार का क्या विजन है। लेकिन सर, इस साल के अभिभाषण के अन्दर और पिछले साल के अभिभाषण के अन्दर कोई बहुत ज्यादा अन्तर नहीं है। इसमें वही बातें दोहराई गई हैं जो पिछले अभिभाषण में थी। यह अभिभाषण ऐसा लगता है मानो पुराने अभिभाषण की कॉपी करके ही यहां रख दिया गया है। स्पीकर सर जो अभिभाषण और सरकार का विजन एक साल का होता है उसमें नई-नई स्कीमें और नई-नई योजनाएं लानी चाहिए। लेकिन इसमें "स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत"। "थारी पैंशन, थारे गांव" "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", आदर्श ग्राम योजना आदि चीजों का जिक्र है जो पिछले साल के अभिभाषण में भी थी वही पुरानी योजनाएं इस साल रखी गई हैं। सर, मेरा यह मानना है कि सरकार ने जो माननीय राज्यपाल महोदय को अभिभाषण दिया वह पुराना था और बिल्कुल नीरस था। स्पीकर सर, कानून व्यवस्था पर बहुत बातें हुई हैं जिसमें सरकार अपनी तरफ से कुछ कह रही है और हमारी पार्टी के विधायकों ने हमारे नेता ने अपनी बात रखी जिसकी डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं कानून व्यवस्था पर एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा का जो आपसी भाईचारा है वह जो पिछले 50 सालों में खत्म नहीं हुआ लेकिन पिछले एक साल में वह भाईचारा टूटा है। इसके अलावा एस.वाई.एल. का मुद्दा कल भी पूरे जोर शोर से उठा और पहले भी यह मुद्दा कई बार उठा है इसलिए इस मुद्दे पर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन केवल एक बात मैं अपनी तरफ से रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार से

सरकार भी, विपक्ष भी और पूरा प्रदेश यह चाहता है कि हरियाणा को अपने हिस्से का पानी मिले जिससे हरियाणा की जनता उस पानी से अपनी फसलों और खेतों को पानी दे सकें लेकिन पंजाब अपनी दादागिरी से और अपने सख्त रवैये से हमें पानी नहीं दे रहा है। इसके लिए हमें भी अपनी तरफ से थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए। हमें भी पंजाब वालों को यह दिखाना चाहिए कि अगर तुम दिल्ली जाओगे या हिन्दुस्तान से जुड़ोगे तो हरियाणा में से होकर ही जाओगे। हमारी सरकार ने भी पंजाब के लोगों को थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए। स्पीकर सर, जहां तक हैल्थ की बात है आज हरियाणा प्रदेश हैल्थ में बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। मैं खासकर मेवात की बात करूंगा आज मेवात के अन्दर डॉक्टरों की भारी कमी है, दवाइयां भी पूरी तरीके से मुहैया नहीं करवाई जाती और जो गरीब आदमी है उसका ईलाज नहीं होता क्योंकि हमारे साथ में जिला गुड़गांव लगता है वहां पर बड़े-बड़े आलीशान फाईवस्टार कैटेगरी के हस्पताल हैं जिसके बारे में सरकार को सब मालूम है कि उन हस्पतालों में इलाज करवाने का कितना महंगा रेट है। स्पीकर सर मैं ज्यादा न कहते हुए सरकार से एक बात के लिए निवेदन करूंगा कि ई.वी.एस. की एक स्कीम है जो आज की तारीख में दिल्ली में लागू है और उस स्कीम के तहत किसी भी प्राईवेट हॉस्पिटल में किसी भी गरीब आदमी को मुफ्त ईलाज की सुविधा मुहैया कराई जाती है। स्पीकर सर, हरियाणा में भी यह सुविधा लागू होनी चाहिए ताकि जो इतने बड़े-बड़े हस्पताल हैं जिनमें बहुत महंगा ईलाज होता है उनमें पिछले 10 प्रतिशत गरीब लोगों का भी ईलाज हो सके। इसके साथ मैं एजुकेशन पर भी अपनी बात रखना चाहता हूं कि जो एजुकेशन के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं जैसे पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और उस समय कांग्रेस के लोगों ने शिक्षा की बड़ी-बड़ी दुकानें खुलवा दी जिनमें खासकर बी.एड के कोर्स के लिए थी। इसके अलावा जो सोनीपत में एजुकेशन सिटी के नाम से शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बनाया गया उसके अन्दर सरकार की यह मंशा थी कि यहां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एजुकेशन क्वालिटी आएगी जिससे एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा जिससे हरियाणा प्रदेश भी उन्नति करेगा। सर, वर्ष 2006 में जो वह दो हजार एकड़ भूमि एकवायर की गई थी वहां पर अभी तक कोई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एजुकेशन की संस्था नहीं आई है। यह इस बात का प्रमाण है कि पिछली सरकार द्वारा अपने चहेतों को और अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह स्कीमें लाई गई थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत अच्छे और बहुत कारगर कदम उठाए। इसी में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर 491 बी.एड कॉलेज हैं। जिनमें कुल 60762 सीटें है। पिछले वर्ष जो काउंसलिंग हुई है उसके द्वारा इनमें से केवल 32811 सीटें भरी गई हैं। इसके अतिरिक्त 27851 सीटें खाली रही हैं। इस तरह के कार्य से सरकार की बेकायदगी ही उजागर होती है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। स्पीकर सर, अब मैं अपने मेवात जिले की समस्यायें सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : नसीम जी, सदन के दूसरे सदस्यों को भी सदन में अपनी बात रखनी है अत: आप वाईंड अप कीजिए।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो पहले ही ज्यादा चिंता है कि मैं सदन के निश्चित समय में से ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र की बात रख सकूँ परन्तु चण्डीगढ़ से मेवात पहुंचने में थोड़ा समय तो लगता ही है। बस मैं मेवात पहुंचने ही वाला हूँ। (हंसी)

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप कम से कम समय में अपनी बात पूरी कर लें।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मेवात में ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की बात कही जा रही है लेकिन अभी तक इस ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल का कोई खाका तैयार नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें एक बेकायदगी और देखने को मिल रही है। ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल रोडवेज डिपार्टमैंट का काम है जबकि उसका काम मेवात डिवेलपमैंट ऐजेंसी देख रही है जबकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की तरफ से यह उत्तर मिलता है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यह काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को दिया जाये और वह देखे कि इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है। ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए आठ एकड़ जमीन एक्वॉयर की गई थी जबकि इसके नार्म्ज के हिसाब से यह जमीन ग्यारह एकड़ होनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, 1980 में एम.डी.वी. का तथा 1982 में एम.डी.ए. का गठन हुआ था। इनके गठन के पीछे मंशा केवल मात्र मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र का विकास तथा उन्नति करना था। बड़े अफसोस की बात है कि आज 35-40 वर्ष के बाद भी मेवात पर उसी पिछड़ेपन का धब्बा लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेवात के लोगों में ऐसी क्या कमी या दोष रहा है कि हमेशा से मेवात के साथ दोगला व्यवहार किया गया है। मेवात हर तरीके से विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि मेवात पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए डेढ़ साल हो गया है लेकिन बावजूद इसके मेवात में कोई नया प्रोजैक्ट या स्कीम नहीं आई है जिससे मेवात के लोगों को यह लगे कि यह सरकार मेवात क्षेत्र के लिए चिन्तित है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के फिरोजपुर झिरका की कुछ समस्यायें है जिनकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा। वर्ष 1982-83 में फिरोजपुर झिरका में बस का सब डिपो हुआ करता था लेकिन पिछले 10-12 साल से यह बस सब डिपो यहां पर नहीं है। 20 साल तक यह बस सब डिपो कार्यरत रहा उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया। आज यहां पर बस अड्डा बनाया जा रहा है लेकिन बनने से पहले ही यह बहुत जर्जर हालात में पहुंच गया है। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री तथा परिवहन मंत्री जी ने उसका उद्घाटन तक नहीं किया है पर बावजूद इसके इसकी सीलिंग तथा अन्य निर्माण कार्य बिल्कुल जर्जर हालत में पहंुच चुका है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरजोर निवेदन है कि फिरोजपुर झिरका में बस सब डिपो बनाने की घोषणा की जाये। फिरोजपुर झिरका बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर पर पड़ता है। यहां से बाला जी तीर्थ के लिए, जैनियों का का जो बहुत बड़ा तीर्थ है वहां पर जाने के लिए, अलवर के लिए, भरतपुर के लिए, आगरा के लिए तथा मथुरा के लिए बस का प्रबन्ध होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग इन तीर्थ स्थानों पर अपनी भावनायें व्यक्त करने के लिए जाते हैं। यदि यहां पर बस सब डिपो बनाया जाता है तो इससे मेरे क्षेत्र के लोगों को बहुत सहूलियत होगी। इसके अतिरिक्त फिरोजपुर झिरका के अन्तर्गत जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। पिछले वर्ष भी सड़कों की मरम्मत संबंधी लिस्ट तैयार कर दी गई थी लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्य शुरू नहीं हो पाया है। मेरी पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री राव नरवीर जी से प्रार्थना है कि इन रोड्ज का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाये। आज पूरे प्रदेश में राजकीय स्तर की 9 यूनिवर्सिटिज हैं। इनमें सबसे पहले कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी का नाम आता है। यूनिवर्सिटी की कमी होना भी कहीं न कहीं मेवात के पिछड़ेपन को ही परिलक्षित करता है। यदि यहां पर यूनिवर्सिटी खोल दी जाये तो गरीबों के बच्चों को भी पढ़ने का मौका

मिलेगा और वे भी तेज रफ्तार भरी इस जिंदगी में दूसरों के साथ चलते नजर आयेंगे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वह जल्द से जल्द मेवात में यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा करें। इसके अतिरिक्त मेवात में पंचायत विभाग का भी बहुत बुरा हाल है। मैं माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पंचायत विभाग में बहुत जयादा बेकायदगियां हुई हैं। पिछली सरकार में पंचायत के लिए जितने भी फंड रिलीज़ हुए उन्हें तत्कालीन सरकार ने मात्र अपने उन चहेतों तक सीमित रखा जिनकी विकास कार्यों को करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही पैसा उनके अकाउंट में गया उन्होंने उस पैसे को निकालकर अपनी जेबों में भर लिया। मेवात के गांवों में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय, मेवात में झिर मन्दिर है, माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी को पता है कि इस मन्दिर के पास टूरिस्ट पैलेस बन सकता है क्योंकि वह काफी अट्रैक्टिव जगह है। इसलिए अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि वहां पर टूरिस्ट पैलेस बनाया जाए क्योंकि इस मन्दिर के प्रति लोगों की काफी गहरी आस्था है। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भाई नसीम अहमद जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह भगवान शंकर जी का बहुत प्राचीन मन्दिर है। जब मैं वर्ष 1987 में जनस्वास्थ्य मंत्री था, वहां पानी सुख गया था। चौधरी अजमत खाँ भी उस समय मंत्री थे। हम दोनों ने उस मन्दिर में शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया था। सिंचाई विभाग के ई.आई.सी. साहब ने बताया था कि यह चट्टान भूमि काफी कठोर है, जिसके कारण पानी नहीं है। हमने मनोवैज्ञानिक तौर पर एक मिट्टी की कुंडी बनाई और कहा कि इस बार यहां से ट्यूबवैल की बोरिंग शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि लगभग 180 फीट नीचे से पानी निकल कर उसकी एक धार भगवान शंकर की पिण्डी पर जाकर लगी। उसके साथ ही जमीन पर हमने गऊशाला के लिए भी ट्यूबवैल की बोरिंग का काम शुरू किया था। फिरोजपुर झिरका में जो शिव मन्दिर है, उस पर मेव और हिन्दू दोनों शिव रात्रि के त्यौहार पर भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं। हम यहां पर कोई ना कोई पर्यटन केन्द्र जरूर बनायेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री श्याम सिंह राणा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सहमत हूँ। देश और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार पहली बार बनी है। इन दोनों सरकारों का पहला उद्देश्य देश और प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करने का है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पहली बार बागडोर संभाली है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ना मैं खाऊँगा और ना ही खाने दूंगा मतलब ना रिश्वत लूंगा और ना ही लेने दूंगा। भ्रष्टाचार पर लगाम हमेशा केन्द्र की सरकार से ही लगती है, इस प्रकार हरियाणा प्रदेश में भी इस बात की चर्चा हुई कि ना रिश्वत लेंगे और ना ही लेने देंगे। जिस ईमानदारी से प्रशासन चल रहा है, उसका असर लोगों को देश और प्रदेश में देखने को मिल रहा है। काग्रेस शासन के दौरान गैस सिलेंडर लाइन में लगकर ब्लैक में मिलते थे, आज भ्रष्टाचार खत्म होते ही घरों में गैस सिलेंडर उपलब्ध हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा रादौर हल्का है, उसकी एक चिंता यह है कि वह यमुना नदी के पास है। उत्तर पद्रेश ने पिछले

[श्री श्याम सिंह राणा]

चुनावों के दौरान यमुना नदी के ऊपर बांध बनाने का काम शुरू किया था। अध्यक्ष महोदय, भंयकर बारिश के कारण जब बाढ़ की स्थित उत्पन्न होगी तो यमुना नदी से क्या परिणाम निकलेंगे, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। अभिनेता संजय दत्त का गांव मंडोली है और वह भी खतरे में है, माननीय सदस्य श्री घनश्याम दास का गांव करेड़ा खुर्द वह भी खतरे में है और राज्य मंत्री श्री कर्ण देव कम्बोज का गांव मदार भी खतरे तक पहुँच गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इस समस्या का समाधान क्या होगा ? उत्तर प्रदेश के साथ लगते हुए यमुनानगर के यमुना नदी पार हमारी हजारों एकड़ भूमि है। गुमथला गांव का कोई किसान अगर यमुना पार अपना गन्ना लेने जाता है तो उसे सहारनपुर की मुख्य सड़क से होकर जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वहां तक किसान को अपने खेतों में जाने के लिए 7-7 घंटे आने-जाने के लिए लगते हैं। उन किसानों का क्या होगा ? यह एक चिंता 13:00 बजे का विषय है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार को फ्लड को रोकने का इंतजाम करना चाहिए। यमुना दरिया पर एक पुल का निर्माण होना चाहिए। अगर इस पुल के निर्माण का सरकार प्रावधान करेगी तो हम बाढ़ से बच पाएंगे। इसलिए सरकार को इस पुल का निर्माण करके हमारे क्षेत्र की जनता की चिंता को दूर करना चाहिए। हमारी सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह किसान विरोधी, व्यापारी विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार है। मैं इस महान सदन को बताना चाहूंगा कि यह सरकार किसी भी वर्ग की विरोधी नहीं है बल्कि प्रत्येक वर्ग की हितैषी सरकार है। यह अढ़ाई करोड़ लोगों के समर्थन से बनी हुई सरकार है। मेरे क्षेत्र की दूसरी समस्या यह है कि वहां जब यमुना नदी में ज्यादा पानी नहीं आता है तो कभी-कभी किसानों के टयूबवैल और बिजली की लाइन खत्म हो जाती है। उस समय उनके ट्यूबवैल, मोटर, खंभे और लाइन सब खत्म हो जाते हैं। जब किसान नये ट्यूबवैल कनैक्शन लेने के लिए बिजली बोर्ड के पास जाते हैं तो वे किसान को पिछला बिल भरने के लिए कहते हैं। किसान विभाग को दलील देता है कि मेरे खेत में न तो कोठा है, न बिजली है न मोटर है और न ही ट्यूबवैल है। इस तरह से जब मैंने बिजली प्रयोग ही नहीं की तो बिल किस बात का हुआ। जब विभागीय अधिकारी ऐसे किसानों के खेतो में सर्वे करने के लिए जाते हैं तो वे देखते हैं कि किसान सच्ची बात कह रहा है। माननीय साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसे किसानों के बिल माफ करने और नये कनैक्शन देने की घोषणा की है। यह सरकार किसान विरोधी नहीं बल्कि किसान समर्थक सरकार है। ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : श्याम सिंह राणा जी, आप प्लीज, वाइंड-अप कर लीजिए।

श्री श्याम सिंह राणा : अध्यक्ष जी, कुछ समय पहले हमारे क्षेत्र की शुगर मिल खतरे में थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मिल को बचाने के लिए सौ करोड़ रूपये का अनुदान दिया और आगे चालू रखने की गारंटी दी है। मिल मालिक कह रहा था कि अगर चीनी 31 रूपये प्रति किलोग्राम बिकेगी तो मैं 310 रूपये प्रति क्विंटल दूंगा और अगर चीनी 29 रूपये प्रति किलोग्राम बिकेगी तो मैं 290 रूपये प्रति क्विंटल मूल्य दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया है कि चीनी जितने कम रेट में बिकेगी उसकी भरपाई सरकार करेगी। अध्यक्ष जी, क्या सरकार का यह फैसला किसान विरोधी है ? इस सरकार ने किसान और व्यापारी दोनों ही वर्गों के हित मे फैसला किया है। हरियाणा प्रदेश में बहुत-सी सरकारें आती रही हैं। किसी सरकार ने हांसी-बुटाना नहर को

अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए खोद दिया तो किसी ने एस.वाई.एल. और दादूपुर-नलवी नहर को चलने नहीं दिया। क्या पूर्व की सरकारों ने किसी नहर में पानी चलने दिया ? नेताओं के राजनतिक स्वार्थों की वजह से नहरों को बनाने और खोदने में प्रदेश की जमीन और पैसा ही बर्बाद हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तब तक प्रदेश में कोई नई नहर न बनाई जाए जब तक पूर्व की बनी हुई नहरें चालू नहीं हो जाती हैं। इन पुरानी नहरों को चालू करके ही कोई नई नहर बनाने पर विचार होना चाहिए। जब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो उस समय प्रदेश में हर चीज बहुत महंगी थी। हमने सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल किया। जब हमारी सरकार बनी तो उस समय कोयले का रेट 13 हजार मीट्रिक टन था परंतु आज सिर्फ 56 सौ रूपये मीट्रिक टन है। इसके साथ-साथ लोहे और ईंट के रेट भी कम हुए हैं। कांग्रेस शासनकाल में जो मकान 2 लाख रूपये में बनता था आज वही मकान 1 लाख रूपये में बन रहा हे। क्या ये अच्छे दिन नहीं हैं ? ईमानदारी से काम करने के लिए प्रशासन की नीयत में तो गड़बड़ हो सकती है परंतु शासन की नीयत बिल्कुल साफ है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जब लोगों को नौकरी देते थे तो पूछते थे कि किस माँ के पेट से जन्म लिया है। अध्यक्ष जी, क्या इस तरह के वाहियात प्रश्न प्रदेश के सम्मानित पद पर विराजमान मुख्यमंत्री के द्वारा पूछे जाने चाहिए ? हर व्यक्ति की माँ सम्माननीय होती है। बच्चा किस माँ के पेट से जन्म लेगा यह उसके वश में नहीं है। प्रदेश में ऐसा वातावरण किसने बनाया था ? प्रदेश के आज तक जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बैठें हैं यह उनकी जिम्मेवारी थी। हमने बहुत से आंदोलन देखे हैं। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उस समय कानून व्यवस्था को किसने बिगाड़ा ? कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं होता जिसमें किसी बड़े व्यक्ति का हाथ न हो। अगर यह सदन जांच कराए तो पता चल जाएगा कि इस आंदोलन में भी कोई-न-कोई बड़ा व्यक्ति अवश्य शामिल होगा। प्रदेश के लोग एक-साथ सद्भावना से रहना चाहते हैं लेकिन कुछ व्यक्ति अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों के लिए उनको भड़काकर हिंसक आंदोलन करवाते हैं जबकि राजनीतिक दलों को जनता के दु:खों, कष्टों को दूर करने में सहयोग करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।

श्री राजदीप फौगाट (दादरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। समय को देखते हुए मैं केवल अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक साल पहले मुख्यमंत्री महोदय ने दादरी को जिला बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी का चेयरमैन श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को बनाया गया था। धनखड़ जी अभी रिश्तों की बात करते हुए कह रहे थे कि धर्मपत्नी के साथ रिश्तों की कितनी अहमियत होती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि धनखड़ जी का विवाह फौगाट गोत्र में हुआ है और दादरी फौगाट गोत्र वालों का क्षेत्र है इसलिए मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये दादरी के बारे में जरूर कुछ सोचें। हमारे दादरी शहर को जिला बनाने की जो घोषणा की गई थी उसको पूरा करवाया जाए। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं का भी यहां जिक्र करना चाहूंगा। हमारे दादरी में अंडरपास की बहुत बड़ी प्रोब्लम है और इस बात से धनखड़ जी प्रभावित हैं। अप्रैल में साढे तीन करोड़ रूपये की राशि से वहां बाई पास की घोषणा हुई थी इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि साढे तीन करोड़ की राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है इसलिए इसको बनवाने का काम करवाया जाए। अध्यक्ष

[श्री राजदीप फौगाट]

महोदय, मैं स्वास्थ्य और खेल मंत्री श्री अनिल विज जी से अनुरोध करूंगा कि दादरी में कोई स्टेडियम नहीं है इसलिए कोई जमीन एक्वायर करके हमारे यहां स्टेडियम बनवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के बारे में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। मैं अपने आप को गौरवशाली समझता हूं कि अभी 10 दिन पहले मैंने 25वीं बार ब्लड डोनेट किया है। हमारा दादरी क्षेत्र पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा ब्लड कैंप लगाता है और यह पिछले 6 सालों का रिकार्ड है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे दादरी क्षेत्र में एक ब्लड बैंक खोलने का काम जरूर जरूर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा दादरी में एक अटेला गांव है जो दादरी से 25 किलोमीटर दूरी पर है। उसके आस पास के क्षेत्र में कोई सरकारी होस्पिटल नहीं है इसलिए अटेला में एक पी.एच.सी. खोलने पर जरूर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि वे समान विकास का नारा देते हैं और मैं उनकी इस बात से प्रभावित हूं लेकिन जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो समान विकास हमें कहीं नजर नहीं आता। पिछले सवा साल में मैंने 7 करोड़ रूपये के सरकारी कामों की प्रपोजल्ज सरकार को दे रखी है लेकिन 7 करोड़ तो दूर केवल 7 रूपये के काम भी हमारे यहां नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने घोषणा की है कि 5 करोड़ रूपये के काम प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कराए जाएंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये 5 करोड़ रूपये के काम हम विपक्ष के सदस्यों के हल्कों में भी कराए जाएं तभी हम इस सरकार की सराहना करेंगे। अभी तो सरकार ने सराहना का कोई काम नहीं किया क्योंकि हम अपनी लड़ाई अपने स्तर पर खुद लड़ रहे हैं इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सबके समान विकास के बारे में सोचा जाए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री बख्शीश सिंह विर्क) : अध्यक्ष महोदय, 14 मार्च को राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया और मुझे उस पर बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 16 महीने में केवल असंध शहर में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में अपना नाम ऊंचा किया है। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे यहां कोई कॉलेज नहीं था लेकिन इस सरकार द्वारा उसकी बिल्डिंग के लिए 15 करोड़ रूपये की मंजूरी देकर उस कॉलेज को मंजूर किया गया है। इस कॉलेज की बिल्डिंग जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री श्री रामविलास जी का भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं राव नरबीर जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी छोटी सी रिक्वैस्ट पर असंध शहर में रैस्ट हाउस मंजूर कर दिया। मंत्री जी कह रहे हैं कि यह रैस्ट हाउस जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। कतलाड़ी से बांसा, पक्काखेड़ा से लेकर पबाना जाते हुए 18 फुट की सड़क जो वाया पाडा गांव जाती है वह भी मंजूर हो गई है तथा जल्दी ही बन कर तैयार हो जाएगी क्योंकि इस सड़क का काम चल रहा है। उस पर काम चल रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ-साथ मैं हमारे कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे असंध विधान सभा क्षेत्र में सड़क पर किसानों की फसल खराब होती थी वह 34 एकड़ जमीन एक्वायर करके किसानों को मुआवजा देने का काम किया है। इसके

अतिरिक्त वहां पर शैड है और फड़ बनाने के लिए 16.70 करोड़ रूपये का टैण्डर हो चुका है जिस पर मई तक कार्य शुरू हो जायेगा। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे हल्के के जयसिंह पुर गांव में 132 के.वी. का पावर हाऊस 1996 से बना हुआ है लेकिन उसके अंदर ट्रांस्फार्मर 33 के.वी. के लगे हुए हैं जिसके कारण पूरी बिजली नहीं मिल पाती। इस बारे में मैंने पिछले सैशन में भी जिक्र किया था। अधिकारी कहते हैं कि 31 मार्च तक वहां ट्रांस्फार्मज बदल दिए जायेंगे लेकिन मुझे लगता है कि कुछ काम स्लो चल रहा है इसलिए अधिकारियों को कहा जाए कि पैडी सीजन आने वाला है वहां बड़े ट्रांस्फार्मर रखकर जल्द ही 132 के.वी. बिजली की व्यवस्था की जाए। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा हमारे वहां से नर्दक ब्रांच जा रही है जिसके अंदर से किसानों को पानी देने के लिए रजबाहा बनाना चाहिए। इस बारे में मैंने पिछले सैशन में भी जिक्र किया था। नर्दक ब्रांच पर रजबाहा 169655 R पर बनाने के लिए सर्वे भी हो चुका है। फाइल तैयार होकर करनाल एस.ई. के आफिस में है। मैं सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उस रजबाहे को जल्द से जल्द मंजूरी देकर पानी दिया जाए। वहां बहुत से गांवों में जमीन के नीचे का पानी खारा है जिससे फसल को नुकसान होता है। यदि यह रजबाहा बन जायेगा तो दो हजार एकड़ जमीन को फायदा मिलेगा। इसी तरह से जलमाना के अंदर अंग्रेजों के समय का एक रैस्ट हाऊस बना हुआ है जो कि कंडम हालत में है। उस रैस्ट हाऊस की रैनोवेशन की जाए। ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रूपये लगेगा। यह रैस्ट हाऊस 4.50 एकड़ पर बना हुआ है इसकी चारदीवारी भी ठीक से नहीं की हुई इसलिए इसकी रेनोवेषन जल्द से जल्द की जाए। इसी तरह से हमारे वहां की जितनी भी ड्रेनेज हैं वे बहुत खराब हालत में हैं इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारी सभी ड्रेनों की आने वाले सीजन से पहले-पहले सफाई करवाई जाये। चाहे वह ड्रेन तरावड़ी से काछवा हो, चाहे निसिंग से प्योंद हो और चाहे प्योंद से सालवन हो चाहे वे शेखपुरा से अलावले तोहली होती हुई सालवन को जाती हो। इन ड्रेनों के बंद होने के कारण पिछली बरसात में किसानों को बहुत नुक्सान हुआ था इसलिए इनकी जल्द सफाई करवाई जाए ताकि आने वाले बरसात के मौसम में किसानों की फसल खराब न हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी जुण्डला के अंदर लड़कियों के कालेज बनाने की विनती की थी। वहां पर कालेज बनाने के लिए सर्वे भी हुआ था लेकिन पंचायत के पास जमीन न होने के कारण सर्वे वालों ने सही रिपोर्ट नहीं दी। जुण्डला में 12वीं तक लड़कियों का स्कूल है। वह स्कूल पूरे प्रदेश में सफाई के मामले में एक नम्बर पर आया है। मैं भी वहां की प्रिंसीपल से मिला था। उन्होंने मुझे बताया कि वहां 5 कमरे स्पेयर बने हुए हैं। इस बार से कालेज की क्लासिज उनमें शुरू हो जायें और अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल के पीछे दो-तीन एकड़ किसानों की जमीन लगती है। अगर उस जमीन को सरकार एक्वायर करके उस स्कूल को कालेज का दर्जा दे दे तो ऐसा करने से 20-25 गांवों की बच्चियों को बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि वहां नजदीक कोई कालेज न होने के कारण बच्चियों को हायर शिक्षा लेने के लिए करनाल जाना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अभी एक बात चल रही थी कि बहुत से सदस्यों ने अपनी ससुराल के लिए सड़क मांगी है। मेरी भी ससुराल बलवंत सिंह सढ़ौरा जी के हल्के में है और वह सड़क 12 फीट की है। मेरी राव नरबीर सिंह जी से प्रार्थना है कि रसूलपुर से लाडपुर, लाडपुर से रठाली तथा रठाली से नारायणगढ़ की सड़क को 12 फीट से 18 फीट की बनवा दी जायेगी तो मेरे परिवार वाले भी खुश हो जायेंगे। इसके बनने से किसानों को भी फायदा मिलेगा क्योंकि रसूलपुर और नारायनगढ़ दोनों जगहों पर अनाजमण्डी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे हल्के में जितने भी पशु

[श्री बख्शीश सिंह विर्क]

चिकित्सालय हैं उनमें से 80 प्रतिशत की हालत बहुत खराब है इसलिए उनको भी जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक सड़क जो ठरी से फफड़ाना होती हुई सालवन जाती है। इस सड़क को बनाने के लिए जमीन एक्वायर की गई थी। वहां पर किसानों की जमीन एक्वायर करने के एक साल के बाद जो उन्हें ठेके के हर साल पैसे मिलने थे वह पैसा अभी तक नहीं दिया गया है इस बारे में अधिकारियों से पूछा जाए कि ऐसा क्यों किया गया है ? आज हमारी विधान सभा में हमारे केन्द्रीय सरकार के माननीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी भी आये हुए थे। मैंने उनसे बाहर जाकर मुलाकात की तो मैंने उनको एक बहुत बड़ी बधाई दी और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात के लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं जो मेरे हल्के के 8 गांवों को मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार की ओर से 120 करोड़ रूपये दिलवाने का काम किया है। इन गांवों में बला, सालवन, बाल पबाना, मूनक, रिसालवा तथा कुलाना इत्यादि आयेंगे। इस प्रकार से जब यह 120 करोड़ रूपये इन 8 गांवों में जाकर लगेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे के सारे गांव शहरों के स्तर की सुविधाओं से लैस हो जायेंगे। इसलिए मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने केन्द्रीय सरकार से वह पैसा लाकर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा परोपकार किया है। स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमारे प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ी ज्यादतियां हुई हैं। मुझे यह बात अच्छी तरह से याद है कि सन् 1947 में हमारे देश का तिरंगा झण्डा बना था। हमारा वह तिरंगा झण्डा ऐसे ही नहीं बन गया था बल्कि वह तिरंगा झण्डा लाखों लोगों की लाशों के ऊपर और लाखों लोगों के खून के साथ वह तिरंगा झण्डा बना था। आज कुछ लोगों ने उस तिरंगे झण्डे का अपमान किया है। उन लोगों को इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही विनती बार-बार करना चाहूंगा कि जिन्होंने तिरंगे झण्डे का अपमान किया है उनको कठिन से कठिन सजा दी जाये।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, हमारे जो माननीय सदस्य महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने से वंचित रह गये हैं उनको भी आप 5-5 मिनट का समय ज़रूर दे दें ताकि वे अपने हल्के की बात कह सकें।

श्री अध्यक्ष : संधू जी, अगर आपकी पार्टी के दूसरे साथियों ने अपनी बात रखते हुए समय का ध्यान रखा होता तो ऐसी नौबत ही न आती। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के 32 सदस्यों को मैने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए चार घंटे 58 मिनट का समय दिया। इसके विपरीत आपकी पार्टी के 19 सदस्य हैं जिनको महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए चार घंटे 21 मिनट का समय दिया गया। आप इससे भली प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए किसको कितना ज्यादा समय दिया है। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी पार्टी के जिन तीन माननीय सदस्यों को बोलने के लिए समय देने की बात कह रहे हैं वे बोलने में बहुत एक्सपर्ट हैं इसलिए हम उनको बजट पर बोलने के लिए पूरा समय देंगे। अभी आप बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा की गई घोषणा

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : स्पीकर सर, सभी सदस्यों को एक इनवीटेशन कार्ड दिया गया है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा" लेकिन हमें वह मेले देखने को कभी नहीं मिले हैं। हमारी सरकार के निर्णय के अनुसार हम 23 मार्च, 2016 को जो भगत सिंह, राजगुरू एवं सुखदेव जी का शहीदी दिवस है उस दिन हिन्दुस्तान के सबसे बड़े प्राईज़ मनी का दंगल आयोजित करवाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्राईज मनी भारत केसरी का खिताब जीतने वाले को 1 करोड़ रूपये मिलेगी। इसी प्रकार से दूसरे स्थान पर रहने वाले को 50 लाख तथा तीसरे स्थान पर आने वाले को 25 लाख रूपये का ईनाम दिया जायेगा। चौथे स्थान पर रहने वाले को 10 लाख तथा पांचवें स्थान वाले को 5 लाख रूपये ईनामी राशि दी जायेगी। इसी तरह से छठे स्थान पर रहने वाले को 3 लाख, सातवें स्थान वाले को 2 लाख तथा आठवें स्थान पर आने वाले पहलवान को 1 लाख रूपये की राशि ईनाम के रूप में दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह दंगल केवल इसी साल नहीं होगा बल्कि हमने यह निर्णय लिया है कि हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस पर इस तरह के दंगल का आयोजन हम करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके नतीजे भी आने शुरू हो गये हैं। नतीजा यह आया है कि गांव-गांव में और शहरों-कस्बों में जो अखाड़े बंद हो चुके थे वे दोबारा से खुलने शुरू हो गये हैं और पहलवानों में इस बात के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है कि अगली बार का भारत केसरी का खिताब हम ही जीतेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी अच्छे कामों की तरफ लगे। इसी प्रकार से हम सितम्बर-अक्तूबर माह में राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवायेंगे तथा उसमें प्रथम स्थान पर रहने वाली टीम को 1 करोड़ रूपये का ईनाम दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि गांव-गांव, शहर-शहर और कस्बा-कस्बा हर जगह पर कबड्डी और कुस्ती लड़ते हुये हमारे नौजवान नजर आयें। मैं सभी सदस्यों को निमंत्रण देना चाहता हूँ कि 21 मार्च, 2016 से लेकर 23 मार्च, 2016 तक यह प्रतियोगिता चलेगी और 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से विजेताओं को ईनाम दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि सभी सदस्य उस समारोह में शामिल हों।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : अब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय तथा सभी सम्मानित सभासदो, महामहिम राज्यपाल महोदय ने 14 मार्च, 2016 को सदन में जो अपना अभिभाषण पढ़ा उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने अपने अभिभाषण में न केवल सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में स्पष्ट, सशक्त तथा मार्गदर्शी भाषण दिया बल्कि इस महान सदन में कुछ सदस्यों द्वारा उनके अभिभाषण से ठीक पहले अवरोध पैदा करने की चेष्टा की, उसको भी गरिमामयी ढंग से निपटाया। अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा लोकतंत्र का एक मंदिर है और लोकतंत्र के इस मंदिर में सभी सदस्यों को पूरे प्रदेश के एवं अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों की समस्याओं को उठा कर उसका निराकरण करने का अवसर मिलता है। इस गरिमामयी सदन की

[श्री मनोहर लाल]

गरिमा रखने का दायित्व भी सभी सदस्यों का होता है परन्तु इस सत्र के प्रारम्भ में ही एक दल के सदस्यों द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, इस प्रकार के व्यवहार से निश्चित रूप से पीड़ा होना स्वाभाविक था। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से पहले जिस प्रकार का अवरोध पैदा किया और अभिभाषण से बाहर निकलने का जो पूरा व्यू उनका दिखा जिससे राज्यपाल के अभिभाषण की अवमानना हुई और जो उन्होंने उसकी प्रतियां फाड़ी वह निश्चित रूप से एक निन्दनीय कार्य है। जिसके कारण उनको सदन से निलम्बित किया गया था। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का अपना एक रोल होता है। विपक्ष के रोल में सरकार की आलोचना करना स्वाभाविक है क्योंकि सत्ता पक्ष काम करता है जिसमें कोई कमी भी रह जाती है तो उस कमी का ध्यान कराना यह विपक्ष का काम होता है ताकि हम उसको सुधार सकें और जिससे जनता का लाभ हो। कबीर जी ने कहा है कि 'निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटि छवाय।' लेकिन उस समय की बात तो ठीक लगती है लेकिन अब की जो बात होती है। 'निन्दक ऐसे कुछ हमें भी मिल गये जो उठ-उठ कर बाहर जाए और बुलाने पर भी वापिस न आए।' अध्यक्ष महोदय, उसी सत्र में और उसी दृश्य में हमारे इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के मित्रों ने भी वही कार्य किया भले ही उनका उस प्रकार का विषय तो नहीं था लेकिन वह भी अभिभाषण के दौरान काली पट्टी लगाकर सदन में आए वास्तव में यह भी उचित कदम नहीं था जिसके कारण उनके लिए भी इस सदन में एक निन्दा प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद निन्दा प्रस्ताव को वापिस लेने की बात भी आई जिसके लिए मैंने स्वयं भी निवेदन किया। अगर वे इस गलती के प्रति थोड़ा सा खेद प्रकट कर दें तो निन्दा प्रस्ताव वापिस लिया जा सकता है लेकिन मुझे हैरानी है कि उन्होंने आज भी खेद प्रकट नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, एक गलती होने के बाद उसको मानना वास्तव में एक बड़प्पन का काम होता है।

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता ने कहा था कि हमने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध नहीं किया था उन्होंने कहा कि हम तो हादसे में जो 30 लोग मारे गये थे उनके शोक स्वरूप पट्टियां लगाकर आए थे। वह बात तो उन्होंने क्लीयर कर दी थी कि जो 30 लोग मारे गये थे उनके शोक के रूप में, उनके दु:ख के रूप में और हादसे में जो सम्पत्ति नष्ट हुई है उसके कारण वह काली पट्टियां लगा कर आए थे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा कहना है कि सदन निश्चित रूप से एक लम्बी अवधि के लिए होता है लेकिन हमने तो उसके लिए यह भी नहीं कहा कि हम सदन को इतनी लम्बी अवधि के लिए नहीं चलाएंगे। जैसे हम से पहले सदन के हमने ऐसे कार्यकाल देखे हैं कि एक दिन बजट पेश किया और अगले दिन उसको अपने आप ही पास कर लिया गया और विपक्ष की जरूरत भी नहीं समझी। उसके बाद सब तालियां बजाते हुए सदन से बाहर निकल गये। तीन-तीन दिन में बजट सत्र का बजट पास होते हुए देखा जो इस प्रदेश का रिकॉर्ड है जबकि हमने बिजनैस एडवाईजरी कमेटी मे कहा कि बजट सत्र के लिए समय की कोई कमी नही है अगर आप कहें कि इसको 29 तारीख तक चलाना है, आप कहें इसको 30 तारीख तक चलाना है और आप कहें इसको 31 तारीख तक चलाना है तो उतनी ही तारीख तक सत्र चलेगा लेकिन उसके लिए विषय वस्तु सूची होनी चाहिए और एक अच्छी सकारात्मक बहस यदि इसमें होती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर विपक्ष को वास्तव में ऐसा प्रदर्शन करना था तो राज्यपाल

महोदय के अभिभाषण के बाद बहुत सारा समय होता है। राज्यपाल का जो एक स्थान होता है उस स्थान के प्रति किसी को लेश मात्र भी, जरा सी भी कहीं कमी नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसमें हमें गम्भीरता दिखानी चाहिए थी और उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए थी। हम राज्यपाल महोदय को हमेशा राज्यपाल महोदय कहते हैं, महामहिम कहते है, his excellency कहते हैं। वह कोई व्यक्ति नहीं है, उनका एक संवैधानिक पद है। उनका एक गरिमामय पद है और उस गरिमामय पद के कारण वह एक निश्चित वातावरण में सदन में आएंगे। उस समय तक स्पीकर भी अपनी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं केवल वे आते हैं अपना भाषण पढ़ते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद स्पीकर महोदय सदन की कमांड लेते हैं। स्पीकर महोदय के कमांड लेने के बाद फिर हम कुछ भी करें हमें बोलने की पूरी छूट होती है। जैसे हम ऊंचा-ऊंचा भी बोलते हैं, हम एक-दूसरे के बारे में भी बोलते हैं। हम समस्याओं के बारे में भी बोलते हैं। हम अकस्मात आई घटनाओं के बारे में भी बोलते हैं। यह एक बड़ी घटना थी कि हमारे प्रदेश में हादसे में 30 लोग मारे गये हैं हमारा उनके शोक के बारे में ऐसा कहना नहीं है कि शोक नहीं करना चाहिए था लेकिन अगर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय यह काम न होता तो ज्यादा अच्छा होता।

पंजाब विधान सभा द्वारा पारित किए गए निन्दा प्रस्ताव के संबंध में मामला उठाना

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में एक जानकारी लाना चाहता हूँ। पंजाब विधान सभा में आज फिर सबने मिलकर एक निंदा प्रस्ताव पास किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एस.वाई.एल. केस में रोक लगाई है, हम उस फैसले को नहीं मानते। जब पंजाब सरकार ने इस तरह का प्रस्ताव पास किया है तो हमारी भी यह मुख्य रूप से जिम्मेदारी बन जाती है कि आज सदन में सरकार द्वारा भी इस बारे में निन्दा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान को भी चुनौती देने का काम किया गया है। सरकार को इसके लिए निन्दा प्रस्ताव लाना चाहिए और यदि सरकार नहीं ला सकती तो हम इस पर निन्दा प्रस्ताव लेकर आते हैं और यह इस सदन की जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रकार के निन्दा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इसकी जानकारी मिल चुकी है। यह जो प्रस्ताव पारित किया गया है यह बहुत ही खेदजनक है लेकिन सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि प्रस्ताव में जो भाषा प्रयोग की गई है उसमें कहीं पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र नहीं किया गया है। प्रस्तावना रखते समय पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम लिया गया था परन्तु जब प्रस्ताव पारित किया गया था तो उसमें कहीं पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायलय का नाम नहीं लिया गया है। प्रस्ताव की भाषा में जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है वह इस प्रकार है:-

[श्री मनोहर लाल]

> "पंजाब इस वक्त पानी के गम्भीर संकट का सामना कर रहा है, राज्य के पास अपनी नदियों के पानी में से किसी और को देने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है इसके मद्देनजर सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने की न कभी कोई जरूरत थी और न ही आज है। यह सदन सर्वसम्मति के साथ फैसला करता है कि सतलुज-यमुना लिंक नहर को किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे।"

इस प्रकार का यह प्रस्ताव पंजाब विधान सभा के सदन में पारित किया गया है। इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही हमें करनी चाहिए तथा किस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए यह विचार का विषय है। हम इस मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लेकर जायेंगे। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय मामले को बड़ी गम्भीरता से लेगा और यह गम्भीरता हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा काम आयेगी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके उपर गम्भीरता से एक्शन हो तो उस समय हरियाणा प्रदेश के हितों को प्रस्तुत करते समय पंजाब द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि पंजाब इस मामले में क्या एक्शन लेता है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कांग्रेस पार्टी के कारनामें देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि वह किसी पूर्व निर्धारित योजना के तहत ही इस सदन में आये थे कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि उनको सदन से बाहर जाने का अवसर मिल जाये। स्वाभाविक है कि यदि सदन में कोई भी ऐसा कृत्य किया जायेगा जो नियम के अनुसार अवांछनीय है तो उस नियम का हवाला देकर निश्चित रूप से एक्शन लिया जायेगा। कांग्रेस की सरकार वर्ष 2005 में सत्ता में आई थी और हरियाणा प्रदेश में 10 साल तक कांग्रेस पार्टी का शासन काल रहा परन्तु उसने एस.वाई.एल. नहर निर्माण के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया और न ही एस.वाई.एल. नहर के उपर कोई सुनवाई करवाई। कांग्रेस पार्टी के मित्रों को पहले से ही पता था कि एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा आने वाला है अत: उन्होंने पूरी तैयारी के साथ एस.वाई.एल. नहर निर्माण के मसले को मुद्दा बना दिया। कांग्रेस के वर्ष 2005 के शासन काल से पहले वर्ष 2004 में इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी की सरकार भी रही थी। हमने सत्ता में आते ही फरवरी, 2015 में एस.वाई.एल नहर मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने के बारे में लिखा। प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन किया गया, उत्तर भारत राज्य परिषद् की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में भी इस विषय को उठाया गया और बार-बार इस विषय को उठाने का परिणाम यह निकलकर सामने आया कि अंततोगत्वा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई शुरू कर दी। पिछली चार मीटिंग्ज में हम लगातार अपना पक्ष रखते आ रहे हैं। अभी 30 मार्च, 2016 को इस विषय पर सुनवाई होने वाली है। कांग्रेस की जो भूमिका एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर रही है वह संदिग्ध है। अभी पिछले दिनों प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी उसमें पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रही है। कांग्रेस पार्टी ने जाट आरक्षण के मुद्दे को राजनीति का मोहरा बना दिया। इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्त्ता तथा लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। उनके बाकायदा सबूत भी मिले हैं और इन्हीं सबूतों के बल पर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता प्रोफेसर बीरेन्द्र सिंह पकड़े भी जा चुके हैं। इनके अलावा और भी कई कांग्रेसी लोग इस जाट आरक्षण आंदोलन की आंग को भड़काने के विरूद्ध पकड़े जा चुके हैं। आगे की

कार्यवाही निश्चित रूप से वैसी होगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा राग अलापती रहती है कि वह हमेशा भले के लिए ही काम करती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि

'मेरे पास से गुजर कर,
मेरा हाल तक ना पूछा।
मैं कैसे मानूं दूर जाकर रोए भी होंगे'

निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के बारे में शंका पैदा होती है कि क्या वह कभी भी प्रदेश के हित में काम करेगी ? अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है। अपने न्यायोचित हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे। अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए किसानों की अधिग्रहित भूमि को डी-नोटिफाई करने के लिए बिल पास किया है। जैसे मैंने बताया कि यह मामला हरियाणा से संबंधित हैं, पंजाब से नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति संदर्भ कई वर्षों से रूका हुआ था और हरियाणा सरकार ने इसकी शीघ्र सुनवाई करने की माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक भी शामिल थे। जिनमें अध्यक्ष महोदय आपने, चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर, वैद्य कपूर चंद, श्रीमती सरिता नारायण, श्रीमती वीना छिब्बर व श्री चन्द्र भाटिया सब सदस्यों ने मिलकर सरकार के कार्यकाल के 9 महीने पहले ही विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एस.वाई.एल. नहर मुद्दे पर कितनी गंभीर हैं, वह अपनी भावना पहले ही प्रकट कर चुकी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से हरियाणा के इस अनुरोध को स्वीकार किए जाने के बाद पंजाब में चाहे कांग्रेस पार्टी या अकाली दल की सरकार हो, सबके पसीने छूट गए थे। मैं समझता हूँ कि वे उसी दिन से इस मुद्दे पर एक्टिव हैं। अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर हरियाणा के किसानों की जीवन रेखा है और भाजपा ने सदैव इसे गंभीरता से लिया है। वर्तमान सरकार एस.वाई.एल. नहर के मामले पर चुप नहीं बैठी बल्कि हमने दिल्ली में अपने विधायकों और सांसदों की एक संयुक्त बैठक बुलाने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को इस गंभीर विषय से अवगत करवाया था। माननीय गृहमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया और कहा कि पंजाब सरकार ने यह ठीक नहीं किया है। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि मैं पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से इस विषय के बारे में अवश्य बात करूँगा। बाद में माननीय गृहमंत्री महोदय ने मुझे टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया कि उनसे इस गंभीर विषय पर बात हो चुकी है और वे इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश में चल रहे दो गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी का शामिल न होने के बारे में यह कहना कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर न्यौता नहीं दिया गया, समझ से परे हैं। विषयों की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में आना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे बेटे-बेटी की शादी होती तो मैं व्यक्तिगत रूप से न्यौता भेजता। संयोग से मेरे जीवन में ऐसा दिन कभी भी नहीं आने वाला।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ कि बेटा-बेटी तो भाई-बहन के भी हो सकते हैं। आप उनको शादी का न्यौता भेज सकते हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर और जाट आरक्षण के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में आने के बारे में कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि हमें व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण नहीं दिया गया, यह तो सिर्फ एक ना आने का बहाना था, असल में वे सर्वदलीय बैठक में आना ही नहीं चाहते थे। सिवाय कांग्रेस पार्टी के सभी दलों ने आपस में मिलकर माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह किया कि एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए किसानों की अधिग्रहित भूमि को डी-नोटिफाई कराने वाले बिल को पारित ना किया जाये। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए हमें भरोसा दिलाया कि संविधान के हिसाब से निर्णय लिया जायेगा। पंजाब सरकार द्वारा लाए गए बिल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त तो नहीं किया है बल्कि स्टेटस क्वॉ (status quo) कर दिया है। आगे इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, इस प्रकार का माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो निर्णय आया है वह संतोषजनक है। एस.वाई.एल. नहर के लिए हम पहले जैसे प्रयास करते रहेंगे। एस.वाई.एल. नहर के पानी को रोकने का प्रस्ताव पारित करना लोकतंत्र के हित में नहीं है, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है। पंजाब सरकार आने वाले चुनावों में एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा बनाकर इसका लाभ उठाने के लिए जानबूझ कर ऐसा कर रही है। अध्यक्ष महोदय, हमें तो लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए किसानों की अधिग्रहित भूमि को डी-नोटिफाई करने का बिल पास करके आगामी विधानसभा चुनाव के डर के कारण बीच में ही सरकार को छोड़ने का मन बना चुके हैं। क्योंकि यह सिर्फ राजनैतिक गोटियां फिट करने के उद्देश्य से ही हो रहा है। इस बात का पंजाब सरकार को भी पता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवेहलना कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, अब यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय और पंजाब सरकार के बीच में है। इसमें हरियाणा की कोई भूमिका नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को उठाया है और उस पर पंजाब सरकार ने यह प्रस्ताव पास किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर सख्त से सख्त संज्ञान ले सकता है। अध्यक्ष महोदय, हम भी चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा जरूर करें। हमें तो सिर्फ न्यायसंगत चीज मिलनी चाहिए इसके लिए हमें चाहे माननीय राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करना पड़े चाहे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री से मिलना पड़े, चाहे इसके लिए हमें किसी अन्य व्यक्ति से मिलने का समय लेना पड़े हम निश्चित तौर पर एस.वाई.एल. का पानी हरियाणा में लाएंगे। एस.वाई.एल.हमारी जीवन-रेखा है। इसके लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी हम अवश्य उठाएंगे। माननीय साथियों, हमारे लिए किसान का हित सर्वोपरि है। हमारे प्रदेश की अधिकांश आबादी किसान वर्ग की है। यह प्रदेश एक प्रकार से कृषि प्रधान प्रदेश है। किसानों को कोई समस्या होगी तो उससे प्रदेश को भी समस्या होगी। ओलावृष्टि की वजह से खराब हुई फसल पिछले वर्ष हमने जितनी मुआवजा राशि दी उतनी मुआवजा राशि आज तक किसी अन्य सरकार ने नहीं दी है। उस मुआवजा राशि को अपनी सारी प्रशासनिक ताकत लगाकर हमने मई महीने में ही बांट दिया था। इस मुआवजा राशि को सिर्फ एक महीने के अंदर बांटकर हमने सुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। इसी प्रकार से जब केंद्र में हमारी सरकार आई तो उन्होंने भी इस मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया। इसके साथ-साथ हमने मुआवजा राशि में जितनी बढ़ोतरी करना संभव था उतनी की है। हमने किसानों को 12 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया है। यह राशि आज तक किसी भी सरकार द्वारा दी गई सर्वाधिक राशि है। इसी तरह सफेद मक्खी के प्रकोप से जो कपास की फसल खराब हुई है हमने उस फसल के खराब होने पर

967 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि जारी की है। इस मुआवजा राशि का शीघ्र ही बंटवारा कर दिया जाएगा। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी की जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं। इन्होंने कपास के मुआवजे की बात सदन में उठाई है। सरकार ने कपास की फसल का जो मुआवजा किसानों को दिया है उसमें बड़ा भेदभाव हुआ है। उसमें जिस किसान की जितनी भी फसल खराब हुई थी जैसे किसी किसान की 5 एकड़ फसल खराब हुई थी तो उसे तो 5 एकड़ का मुआवजा मिल गया परंतु जिसकी 20 एकड़ फसल खराब हुई थी उसको पूरी 20 एकड़ फसल का मुआवजा नहीं दिया गया। आपने सिर्फ 5 एकड़ का स्लैब बनाया है जिसकी वजह से जिस किसान की 20 एकड़ फसल खराब हुई है आप उसे केवल 5 एकड़ फसल का मुआवजा दे रहे हो। यह किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। अगर किसी किसान की 20 एकड़ फसल खराब हुई है तो आपको उसे 20 एकड़ का ही मुआवजा देना चाहिए था। इस बार सफेद मक्खी की वजह से केवल कपास की ही फसल खराब नहीं हुई है बल्कि इसके साथ-साथ ग्वार और ज्वार की फसल भी खराब हुई है लेकिन आपने इन दोनों फसलों को बिल्कुल छोड़ दिया है। इन फसलों का आज तक एक पैसा भी मुआवजा नहीं दिया गया है। किसान की अगर ग्वार और ज्वार की फसल खराब होती है तो इनको भी कपास के साथ शामिल करके मुआवजा देना चाहिए क्योंकि ये फसलें भी किसान के खेत में ही पैदा होती है। किसान ग्वार की फसल इसलिए पैदा करता है चूंकि ग्वार के भाव आजकल अच्छे चल रहे हैं। इसकी वजह से किसान को ग्वार की फसल से कम लागत में ज्यादा मुनाफा होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इन दोनों फसलों को भी साथ जोड़ें और 5 एकड़ के स्लैब की वजह से जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है इसे भी दूर करें। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष जी, मेरा विधान सभा क्षेत्र कलायत जिला कैथल में पड़ता है और वह शायद सरकार की भूल-चूक से गिरदावरी से वंचित रह गया है। कलायत क्षेत्र में नरमा काफी मात्रा में पैदा होता है। वहां पर सारी की सारी नरमे की फसल खराब हो गई है। यह फसल सफेद मक्खी की वजह से खराब हुई है। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कलायत की स्पैशल गिरदावरी करवाई जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ग्वार, ज्वार और बाजरे की फसल की गिरदावरी का विषय उठाया है। विभाग की जानकारी के अनुसार सफेद मक्खी का असर सिर्फ कपास की फसल पर होता है। कपास के अलावा इसका असर दूसरी किसी अन्य फसल पर नहीं होता इसलिए सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई फसल की गिरदावरी की गई थी। सफेद मक्खी केवल कपास को खराब करती है और कपास की फसल के नुक्सान की वजह से 5 जिलों की गिरदावरी हुई थी। अगर सफेद मक्खी की वजह से खराब हुई फसल की किसी अन्य जिले में गिरदावरी होती तो उसमें उस जिले की भी गिरदावरी की जा सकती थी। अब गिरदावरी कर पाना संभव नहीं है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब गिरदावरी कर पाना संभव नहीं है। कल सी.पी.एस. श्री बख्शीश सिंह विर्क ने हाउस में कहा था कि हमारे क्षेत्र में जिस समय फसल खराब हुई थी उस वक्त एस.डी.एम. ने गिरदावरी नहीं की। सरकार

[श्री अभय सिंह चौटाला]

असंध हल्के में 'जे' फॉर्म के बिहाफ पर नई गिरदावरी करवा रही है और वहां के किसानों को 90 लाख रूपये भी देगी। अगर एक माननीय सदस्य के हल्के में गिरदावरी हो सकती है तो फिर पूरे प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती ? (विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव(श्री बख्शीश सिंह विर्क) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि पटवारी ने गिरदावरी की थी और एस.डी.एम. ने पता नहीं क्यों उसको कैंसिल कर दिया और उसने रिपोर्ट हमारे विपरीत भेज दी। उसकी दोबारा गिरदावरी नहीं हो सकती थी क्योंकि फसल कट चुकी थी इसलिए एफ.सी.आर. ने जे.फार्म कोलैक्ट करके मुआवजा देने का काम करवाया था।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जे. फार्म के आधार पर मुआवजा दिलवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, उस समय केवल सफेद मक्खी की वजह से ही नुकसान नहीं हुआ था बल्कि उस दौरान ओला वृष्टि की वजह से भी फसलों का नुकसान हुआ था। उस वक्त उनकी गिरदावरी करवानी चाहिए थी। यदि उस वक्त उनकी गिरदावरी नहीं करवाई गई तो अब "जे" फार्म के आधार पर उनका मुआवजा दिलवाया जाए। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई। उप तहसील, जुलाना की बात मैं यहां बताना चाहता हूं जहां गिरदावरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी रिकार्ड है। यह जुलाना के विधायक द्वारा तैयार किया गया कागज नहीं है। उसमें बकायदा तौर पर साफ लिखा हुआ है कि करीबन 2577 एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें ओला वृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जींद में कपास भी बोई जाती है इसलिए कपास और दूसरी फसलों पर ओला वृष्टि की वजह से नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे कहना है कि या तो आपको कोई गुमराह कर रहा है, जैसे कापड़ीवास जी कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, इस मामले में भी या तो आपको गुमराह किया जा रहा है। यदि गुमराह नहीं किया जा रहा है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जींद भी तो हरियाणा का हिस्सा है इसलिए वहां भी खराब हुई फसलों का मुआवजा दिलवाया जाए।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, जिन बातों पर चर्चा पूर्व में हुई है उन बातों पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब के बीच में चौटाला जी को अपनी बात इतनी लम्बी नहीं करनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल मुख्यमंत्री महोदय जी को याद करा रहा हूं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कपास की गिरदावरी 5 जिलों में हुई है। यह विषय आज का विषय नहीं है बल्कि यह विषय 8 महीनों से चल रहा है। जिस समय 5 जिलों की चर्चा आई थी उसकी जानकारी सबको है। उस समय जिस भी जिले से आपत्तियां आई थी हमने उन पर सब पर विचार किया था। जिन 5 जिलों में मुआवजा दिया गया है जींद भी उन 5 जिलों में है और जुलाना जींद जिले में ही आता है लेकिन मैं एक बात जरूर क्लीयर कर देना चाहूंगा कि मुआवजा केवल सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई फसल का दिया गया है। इसके अलावा कोई कम्पनसेशन नहीं दिया गया।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय,------ (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: अभय सिंह जी, आपने डेढ़ घंटे तक अपनी बात रखी थी इसलिए अब मुख्यमंत्री महोदय के रिप्लाई में इतना इंटरवीन करना ठीक नहीं है इसलिए आप बैठ जाएं।(विघ्न) आपने अपनी बात पूछ ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं सफेद मक्खी की ही बात कर रहा हूं। यदि एफ.सी.आर. के माध्यम से किसी भी जिले का किसी और कारण से किसी प्रकार के नुकसान का जायजा आया होगा तो उसके लिए अलग प्रकार से मुआवजे की बात होगी। अब केवल सफेद मक्खी के नुकसान की बात हो रही है। सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुइ कपास की फसल के नुकसान का मुआवजा 967 करोड़ रूपये 5 जिलों में दिया गया है। कोई भी सदस्य बता दे कि इतना ज्यादा मुआवजा पहले कभी सफेद मक्खी के प्रकोप से खराब हुई फसल का दिया गया हो। अध्यक्ष महोदय, पंजाब में हमारे यहां के एरिया से ज्यादा सफेद मक्खी का प्रकोप हुआ था लेकिन वहां केवल 600 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया गया है जबकि हमने 967 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है। हमने पंजाब से ज्यादा मुआवजा दिया है। अध्यक्ष महोदय, तीसरा विषय था कि 5 एकड़ तक ही मुआवजा दिया गया तो इस बारे में मैं बताना चाहूंगा 5 एकड़ का विषय हरियाणा सरकार का नहीं है बल्कि ये भारत सरकार के निर्देश हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के नुकसान में वही किसान आएंगे जो 5 एकड़ तक के किसान होंगे अथवा जिनकी 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनको 5 एकड़ यानि दो हेक्टेयर का ही मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा सहायता राशि होती है। मुआवजा से कोई टोटल हानि की भरपाई नहीं होती है। यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि बड़े किसान इस तरह की प्राकृतिक आपदा होती है तो उसको अपने आप झेल लेंगे। 5 एकड़ के बारे केंद्र सरकार का नियम बना हुआ है उसी को हमने लागू किया है। अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं किया।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिस समय गेहूं की फसल खराब हुई थी उस समय 5 एकड़ का कोई नियम लागू नहीं किया गया। उस समय सबको मुआवजा दिया गया था इसलिए इसमें भी सबको मुआवजा दिया जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, आगे इस तरह कभी नहीं होगा। आगे भारत सरकार के नियमों के अनुसार ही होगा। नियम ध्यान में आये तभी ऐसा किया गया है। अब उन्होंने पूछ लिया कि आप इतना ज्यादा क्यों देते हो? (विघ्न)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब क्या यह चाहते हैं कि जिनको गेहूं की फसल खराब होने पर मुआवजा दिया गया था उनसे वापिस ले लिया जाये ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, प्लीज आप बैठें। आपका यह कोई तरीका नहीं है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारा विषय स्पष्ट कर दिया है। अब जो फसल जिसकी कटाई हो रही है इसका बीमा नहीं है। लेकिन इसके बाद अगली जो फसल खरीफ की होगी उसका बीमा करने का प्रावधान प्रधान मंत्री जी ने फसल बीमा योजना के तहत किया है। इस बीमा योजना के माध्यम से मिनिमम प्रीमियम खरीफ पर 2 प्रतिशत और रबी पर 1.50 प्रतिशत देना होगा। उसके बाद जितने पैसे का किसान बीमा करवायेंगे फसल का नुकसान होने पर बिना कटौती के पूरे पैसे मिलेंगे। उसके बाद इस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बहसबाजी खत्म

[श्री मनोहर लाल]

हो जायेगी। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के किसानों को प्रेरित करें कि अब सरकार की तरफ से फसल खराब होने पर मुआवजा नहीं दिया जायेगा इसलिए आप फसल का 2 प्रतिशत और 1.50 प्रतिशत प्रीमियम देकर समय पर बीमा करवायें। जितना सरकार का पैसा जाता है जो सरकार द्वारा प्रीमियम दिया जायेगा उसमें कंट्रीब्यूशन होगा और बीमा कंपनीज सीधा किसान को पैसे देंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब दे रहे हैं और विपक्ष के साथी जब देखो खड़े हो जाते हैं। यह ठीक बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठें।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, क्या सदन विपक्ष के साथी चलायेंगे या आप चलायेंगे। विपक्ष के साथी मुख्यमंत्री जी को बीच में टोका-टाकी क्यों कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : संधू साहब आपको आपकी बात कहने के लिए समय निश्चित किया गया था जिसकी आपको पहले सारी जानकारी मिल गई थी। आपने करीबन 30-35 मिनट अपनी बात रखी और डेढ़ घंटे के करीब विपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी। अब आप मुख्यमंत्री जी को इस तरह बीच में टोका टाकी न करें। प्लीज आप बैठें। आप लोगों ने भी सरकार चलाई है और आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी के रिप्लाई पर किस प्रकार का व्यवहार रहना चाहिए। आपका यह कोई तरीका नहीं है कि जब मर्जी आए तब आप खड़े हो जाएं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अभिभाषण पर रिप्लाई देते हुए शुरूआत में ही कहा है कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप किस तरीके से चर्चा करना चाहते हैं। अगर आप इसी तरह टोका-टाकी करेंगे तो मुख्यमंत्री जी अपनी स्पीच किस तरह से पूरी करेंगे। यदि आप मुख्यमंत्री जी को इस तरह से बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो रिप्लाई पूरी कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर आप ऐसे ही बार-बार डिस्टर्ब करते रहे तो फिर माननीय मुख्यमंत्री अपनी बात को कैसे कम्पलीट करेंगे। अगर हर तीन मिनट के बाद आप खड़े हो जायेंगे, हर तीन मिनट के बाद सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी खड़े हो जायेंगे और हर 15 मिनट के बाद आपकी पार्टी का कोई दूसरा सदस्य खड़ा हो जायेगा। इस प्रकार से सदन की कार्यवाही नहीं चल पायेगी। आप एक बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं और इस हाऊस में बहुत बार चुनकर आ चुके हैं आपसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। हम तो यह चाहते हैं कि आपका व्यवहार आपकी पार्टी के साथ-साथ दूसरी पार्टियों के सदस्यों के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत होना चाहिए अर्थात आपके इस सदन में व्यवहार से इस हाऊस के सभी सदस्यों को कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सदन की परम्परा के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा का रिप्लाई देना है वह उसी हिसाब से अपना रिप्लाई देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उसी के अनुसार अपना रिप्लाई दे रहे

हैं। आप बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी को डिस्टर्ब करेंगे तो यह कोई सही तरीका नहीं है। आपने डेढ़ घंटे में यहां पर अपनी सारी की सारी बातें रख दी। अब आपको उनके ऊपर माननीय मंत्री जी का जवाब शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये सवालों का जवाब दे रहें हैं और आप सभी द्वारा सरकार के ध्यान में लाई गई समस्याओं के समाधान के बारे में ही बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : स्पीकर सर, जो इन्होंने कहा ये दो अलग-अलग विषय हैं। जो इन्होंने कहा वह हमने अभी नोटिफाई नहीं किया। केन्द्र सरकार की जो योजना आई है हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। केन्द्र सरकार ने डेढ़, दो और पांच परसैंट का ही जिक्र किया है। यह केन्द्र की अपनी योजना है हम उसके ऊपर यहां क्या कर सकते हैं और कितना हिस्सा दे सकते हैं। हमारी सरकार इस बारे में अपने स्तर पर कार्य कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की रिप्लाई में उसको रोकने का विषय नहीं था इसलिए अगर आप हर विषय में माननीय मुख्यमंत्री के रिप्लाई को रोकने का काम करेंगे तो यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी। आपने इस बारे में बताया है तो हम आपको यह बताते हैं कि हम उस विषय पर काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अगर आप हर तीन मिनट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को टोकते रहेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। क्या आप यह चाहते हैं कि हर तीन मिनट के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बार-बार एक ही बात बतायें तो यह कहां तक उचित होगा। मैं आपको फिर से यह कह रहा हूं कि मेरी जानकारी के मुताबिक आप इस सदन में चौथी बार विधायक चुनकर आये हैं अगर आपको भी ये बातें समझानी पड़ेंगी तो यह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं होगा।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से श्री अभय सिंह चौटाला जी से यही निवेदन है कि अगर उनके मन में कोई बात मेरी रिप्लाई के दौरान आती है तो ये उसको बजट प्रस्तुत होने के बाद यहां पर कह दें क्योंकि अभी हमारा वर्तमान सत्र खत्म होने नहीं जा रहा है। अभी बजट पेश होगा और उसके बाद तीन दिन तक उसके ऊपर माननीय सदस्यों को चर्चा का मौका दिया जायेगा। बजट पर चर्चा के बाद भी हमारे पास कई प्रकार के ऐसे अवसर आते हैं उनमें हमें अपनी प्रत्येक बात कहनी चाहिए। सभी माननीय सदस्यों को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर 9 से 10 घंटे चर्चा करने का समय माननीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया है। चर्चा के दौरान जो-जो भी बातें सभी माननीय सदस्यों के ध्यान में आई हैं वे उन्होंने यहां पर कही हैं। इन 9 से 10 घंटे की चर्चा के दौरान में नहीं बोला हूं। अगर कहीं बहुत आवश्यक हो गया होगा तभी मैंने कुछ कहा होगा। जो आप सभी माननीय सदस्यों ने संदर्भ दिये मैं उन्हीं के ऊपर ही अपनी बात कह रहा हूं और जो-जो प्रदेश के हित में है वही बोल रहा हूं। मेरा यह कहना है कि जो यह फसल बीमा योजना है चाहे हम विधायक हैं, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है हम पूरे प्रदेश में जहां-जहां पर भी गांवों में जाते हैं हमें वहां-वहां के गांवों के किसान भाईयों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कभी-कभी स्टेट के ऊपर प्राकृतिक आपदाओं की वजह से स्टेट एक्सचेकर के ऊपर इतना बड़ा और अनएक्सपैक्टिड बोझ आ जाता है जिससे प्रदेश का सारे का सारा आर्थिक ढ़ांचा चरमरा जाता है। हम यह भी नहीं चाहते कि हमारे किसान भाईयों का किसी भी प्रकार से एक पैसे का भी नुकसान हो और उसको उसकी फसल के प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई न हो। यह

[श्री मनोहर लाल]

भरपाई 1000 करोड़ रूपये की पिछले साल आ गई और लगभग 967 करोड़ रूपये की अब आ गई। मान लो अगर इस प्रकार का नुकसान हमें ऐसे ही झेलना पड़ गया तो 1000 करोड़ रूपया हम हर साल कहां से लायेंगे क्योंकि यह अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। इसके लिए अगर हम अपनी फसल के लिए थोड़ी राशि देकर उसका बीमा करवाकर निश्चिंत हो जायेंगे। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि हमें ऐसा करने पर प्राकृतिक आपदा से फसल के खराबे पर मुआवज़े का पैसा भी बहुत ज्यादा मिलेगा। सरकार की किसी भी फसल के 100 प्रतिशत खराबे के लिए अधिकतम लिमिट 12000 रूपये की है। इसके विपरीत अगर हम अपनी किसी फसल का बीमा करवाते हैं तो उस स्थिति में हम उसकी लिमिट खुद फिक्स करेंगे। अगर किसी किसान को अपनी एक फसल के लिए 20,000/- रूपये का बीमा करवाना है तो हमें उसके लिए 400/- रूपये का भुगतान बीमा कम्पनी को करना पड़ेगा और अगर 25,000/- रूपये का बीमा करवाना है तो उसके लिए हमें 500/- रूपये बीमा कम्पनी को देने होंगे। मैं समझता हूँ कि कोई भी किसान 400/- या 500/- रूपये प्रति फसल प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकता है क्योंकि फसल को होने वाले नुकसान के जोखिम को देखते हुए यह कोई बड़ी राशि नहीं है। फसल बीमा योजनायें तो इससे पहले भी बहुत सी बनी है लेकिन यह प्रीमियम उनमें सबसे कम प्रीमियम है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जनप्रतिनिधियों और समाज के दूसरे जिम्मेदार वर्ग को भी किसान को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि अपनी प्रति एकड़ प्रति फसल के लिए वह इतना कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करवाकर निश्चिंत हो सकता है। इस प्रकार से अगर उसकी फसल को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हो जायेगी। इसी प्रकार से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एक विषय मेवात के बारे में भी आया था। माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी ने यहां पर मेवात के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेवात की एक जगह भी चर्चा नहीं की गई। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेवात की चर्चा चार जगह है और चारों जगह अलग-अलग प्रकार से है लेकिन मैं उनको यह बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि मेवात और दूसरे जिलों की चर्चा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हर जगह होगी तभी उसकी काऊंटिंग की जायेगी कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसी जिले का सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा बार आई है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रदेश व्यापी योजनायें ऐसी होती है जिनके अमल में आने से पूरे प्रदेश के विकास पर एक समान असर होता है। उनके लिए किसी क्षेत्र विशेष का कोई महत्व नहीं होता अर्थात प्रदेश व्यापी योजनाओं में हर जिला आता है और अगर हर जिला आता है तो नेचुरली मेवात भी स्वत: ही आ जायेगा। अगर विशेष योजनाओं का नाम लेना हो तो हम एस.वाई.एल. और हांसी-बुटाना नहर की बात करते हैं। मैं माननीय जाकिर साहब से पूछना चाहता हूं कि वे मुझे बतायें कि क्या इसका लाभ मेवात को नहीं होगा। यह बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन दोनों योजनाओं का लाभ प्रदेश के बहुत से जिलों को होगा और जिनमें से मेवात भी एक है। मैं पुन: इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इन दोनों योजनाओं से मेवात के साथ-साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के दक्षिण के जितने भी जिले हैं उनको ही ज्यादा लाभ होने वाला है। इसी प्रकार से अगर हम दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना की बात करते हैं तो दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के अंदर प्रदेश के सभी गरीबों

के लिए मकान बनाने की बात हैं अर्थात Houses for all की बात है तो ये प्रदेश के हर जिले में बनेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि मेवात में भी बनेंगे। यहां एक बात मैं और क्लीयर कर देना चाहता हूं कि इस योजना के तहत मकानों का निर्माण कार्य हर जिले में अवश्य आरम्भ होगा यह अलग बात है कि उसकी शुरूआत किस जिले से हो। किसी जिले में कोई कम्पनी बनायेगी, किसी जिले में सरकार अपने स्तर पर इन मकानों का निर्माण करेगी और जैसे ही निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा उसके बाद उन मकानों को गरीबों को सौंप दिया जायेगा।

बैठक का समय बढ़ाना

14:00 बजे **श्री अध्यक्ष** : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये ?

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे बनने की जहाँ तक बात है मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि क्या के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे मेवात के कुछ हिस्से से हो कर नहीं गुजरता है और क्या मेवात को भी उससे फायदा नहीं होगा ? उसके लिए मेवात का अलग से जिक्र नहीं किया जायेगा। जहाँ तक महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेवात का जिक्र होने की बात है तो अभिभाषण के पैरा नं. 88, 128, 134 में तो मेवात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त पैरा नं. 11 में के.एम.पी. एक्सप्रैस-वे बनने के बारे जिक्र किया है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माफ करना मैं मुख्यमंत्री महोदय के भाषण में अवरोध पैदा नहीं कर रहा हूँ। मैं मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की बात कह रहा था।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, उसमें मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की बात नहीं होगी लेकिन जब हम सभी जिलों का समेकित विकास करने की बात करते हैं तो मेवात भी उन सभी जिलों में शामिल है। इसी प्रकार से 10 हजार से ऊपर की आबादी वाले गांवों की हमने अलग से बात की है। मैं उन गांवों की लिस्ट देख रहा था उसमें 8 गांव मेवात जिले के भी हैं। जहां 10 हजार से अधिक आबादी होगी वहाँ पर वैसे तो पंचायत होगी लेकिन विकास के काम नगर की तरह होंगे। हमारा जो नगरीय बजट बनता है उसी में से इन गांवों में सीवरेज, बिजली, सड़क और पानी जैसी शहरी सुविधाएं हम प्रदान करने वाले हैं। यहाँ सदन में एक और विषय पर चर्चा हुई थी कि हर विधायक के लिए 5 करोड़ रूपये विकास निधि के रूप में नहीं दिये गये। इस बारे में मेरा कहना यह है कि हमने जो 5 करोड़ रूपये की बात की थी वह किसी विधायक को देने की बात नहीं थी। इसका विषय यह था कि हर विधान सभा क्षेत्र में साल में कम से कम 5 करोड़ रूपये के विकास कार्य अवश्य होने चाहिएं। जिन विधान सभा क्षेत्रों में मेरी जनसभाएं हुई हैं वहाँ पर तो उन लोगों की मांग के अनुसार विकास के कार्य 5 करोड़ या इससे ऊपर के भी हुये हैं और

[श्री मनोहर लाल]

वे 5 करोड़ के विकास के कार्य हर विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं। कहीं-कहीं पर बड़ी परियोजनाएं भी हैं जिनकी घोषणाएं अभी बाकी हैं जो अभी शुरू होनी हैं। हेतू यह है कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में वहाँ की परियोजनाओं के हिसाब से कम से कम 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य एक साल में हो जाने चाहिएं। इस बारे में मैंने अभी पिछले साल की रिपोर्ट मंगवाई है जिसमें चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र मिला कर हैं, उस रिपोर्ट के हिसाब से 6 विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ग्रामीण अथवा शहरी विकास कार्यों पर 5 करोड़ रूपये से कम खर्च किये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूँ कि उनमें 5 करोड़ रुपये से कम खर्च हुये हैं और जितना कम रहा है उसको अगले वर्ष में उतना अधिक फंड दे कर पूरा किया जायेगा। उन विधान सभा क्षेत्रों के नाम बाढड़ा, मुलाना, फिरोजपुर झिरका, सढ़ौरा, बरोदा और आदमपुर हैं हालांकि बाढड़ा में मेरी जनसभा हुई है और वहाँ पर जो और बड़े काम होने वाले हैं वे होंगे लेकिन फिर भी मुझे इस बात का कष्ट है कि वहाँ पर 5 करोड़ रूपये विकास कार्यों पर खर्च नहीं हो पाये। (विघ्न) जिस भी विधायक को इस बारे में जानकारी चाहिए कि मेरे हल्के में कितना काम हुआ है तो वह मेरे ओ.एस.डी. को लिख कर दे दें वे उसकी पूरी डिटेल आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। यह तो विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट है इसमें मेरे अपने कोई आंकड़े नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हैपनिंग हरियाणा सम्मिट का विषय आज बहुत चर्चा में रहा और आज उस पर कालिंग अटैन्शन नोटिस भी लगा हुआ था मुझे लगता है उसमें बहुत सारी बातें आ गई होंगी लेकिन मैं फिर भी इस विषय पर अवश्य जवाब देना चाहूँगा। हमारे हरियाणा प्रदेश की आबादी लगभग अढ़ाई करोड़ की आबादी है और उसमें बेरोजगार लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। उस अढ़ाई करोड़ की आबादी में से अगर 50 प्रतिशत लोग भी काम करने वाले हों तो कम से कम सवा करोड़ लोगों को काम चाहिए। सरकार सभी को तो सरकारी नौकरियाँ दे नहीं सकती। सरकारी नौकरी तो बहुत ज्यादा करेंगे तो अब लगभग अढ़ाई लाख हैं और अगर सभी पदों को भर लिया जाये तो लगभग 3 लाख हो जायेंगी। इन 3 लाख नौकरियों में हम सवा करोड़ लोगों को तो एडजैस्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी लोगों को अपने व्यवसाय में चाहे वह खेती है, दुकान है, इंडस्ट्री है या इंडस्ट्री में प्राईवेट नौकरी है या बिजनेस है उसमें नौकरी के अवसर पैदा करने पड़ेंगे। हम जब सत्ता में आये तो हमने विचार किया कि इसके लिए हमें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए और हमने अपनी नई उद्यम पॉलिसी बनाई है। नई उद्यम पॉलिसी के माध्यम से हमने यह तय किया है कि कम से कम 1 लाख करोड़ रूपये का निवेश और 4 लाख लोगों को व्यवसाय मिलना चाहिए। ये अनुमानित आंकड़े होते हैं और जब उस पर काम करना शुरू करते हैं तो वे कम भी रह सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। हमने जो अपनी पॉलिसी बनाई थी उसमें इन्वैस्टर्स सम्मिट की बात भी कही गई थी। उसी के तहत 4 देशों जापान, चीन, अमेरिका और कनाडा में तो एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल के साथ उद्योग मंत्री और मैं स्वयं जा कर आये हैं। उसके बाद इन्वैस्टमैंट सम्मिट को सफल बनाने के लिए देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा कोलकाता में रोड शो किये ताकि हम अपने प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निवेश के लिए ला सकें। दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति ऐसी हुई कि 10-15 दिन पहले जो घटनाक्रम प्रदेश में हुआ उससे एक बहुत चेलेंज का विषय बन गया था कि हम इन्वैस्टर सम्मिट करें या न करें। हमें बहुत लोगों ने सुझाव दिया कि हमें सम्मिट नहीं करना चाहिए लेकिन हमने कहा कि अब एक ऐसा अवसर है कि जब इन्वैस्टर कहता है कि मैं आऊंगा, जिसके लिए जापान से मेरे पास फोन आता

है कि आप इन्वैस्टर सम्मिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम उसके बारे में सोच ही रहे थे तो जापान का राजदूत हमें कहता है कि आप इन्वैस्टर सम्मिट कीजिए। वाडा कम्पनी का जो चेयरमैन है उनके साथ हमारी एम.ओ.यूज. पर बातें चल रही थी क्योंकि उनको हरियाणा में आकर निवेश करना था जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टर सम्मिट कीजिए। इसके लिए हमारे जितने भी इन्वैस्टर्ज हैं वह यहां आएंगे। ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन वास्तव में यह नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसी घटनाएं होती भी हैं तो उसमें से रास्ता कैसे निकालना है यह हमारा काम है। आखिर ये हरियाणा कुरूक्षेत्र की भूमि है, भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दिया तो उस समय अर्जुन का दिमाग बिल्कुल वेवरिंग था कि लड़ाई करूं या न करूं? आखिर उसने वह लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त की तो फिर उस धरती पर रहने वाले लोगों को क्या उससे उत्साह नहीं मिलता ? हमने कहा उत्साह मिलता है। हमने यह तय किया कि इस सम्मिट में जो मनोरंजन के कार्यक्रम हैं, कल्चरल प्रोग्राम हैं उनको छोड़ देंगे। हमने चार दिन की बजाए दो दिन का सम्मिट किया और उस दो दिन के सम्मिट के अन्दर जैसा रिजल्ट निकला है वह आपको पता है कि 359 एम.ओ.यूज. साईन हुए हैं जिसमें 5 लाख 84 हजार करोड़ रूपये का निवेश हरियाणा में आएगा। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में यह भी हो सकता है। हो सकता है कि 5 लाख 84 हजार करोड़ रूपये में से सब के सब एम.ओ.यूज. मैच्योर न हों क्योंकि मैच्योर करने में टाईम लगता है। हमने इसकी योजना बनाई है सभी एम.ओ.यूज. करने वालों के साथ एक-एक रिलेशनशिप मैनेजर को लगा दिया है और उनको कहा है कि इसको मैच्योर कराना आपकी जिम्मेवारी है। ऐसे जो भी रिलेशनशिप मैनेजर लगाए हैं वह इन सभी लोगों से सम्पर्क बनाए हुए हैं और सबके साथ मिलकर उनको जो-जो कठिनाईयां है, तकलीफे हैं उनको दूर कर रहे हैं। एडमीनिस्ट्रेटिव तौर पर जो मुख्य कठिनाईं उनके ध्यान में आई थी वह यह है कि उनको सभी को ऑफिसिज के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई प्रकार की कुछ कलियरैंसिज है उनको लेने में कठिनाई आती हैं हमने कहा कि आपको एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी आप एक बार अप्लाई कीजिए, Within thirty days you will get the clearances. केवल 30 दिन के अन्दर इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं और इस व्यवस्था के अन्तर्गत निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आने वाले हैं अध्यक्ष महोदय,उन परिणामों से हम उत्साहित हैं। इस सम्मिट में वैसे तो सब जानकारियां आई हैं लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि हमारे 12 देश ऐसे थे जो हमारे कंट्री पार्टनर बने थे और उन 12 देशों के लोगों ने भी उस सम्मिट में भाग लिया और वहां पर उसमें बहुत लोगों ने एम.ओ.यूज. भी साईन किये हैं जैसे कि चीन है, चैक गण राज्य है, जापान है, मोरेशिश है, मलावी है, न्यूजीलैंड है, पेरू है, दक्षिण कोरिया है, स्पेन है, टयूनीशिया है, यू.के. है, कनाडा का ऑनटेरियो प्रांत है इन्होंने सब ने भाग लिया। कई बार हैरानी होती है कि इस प्रकार के काम पहले किसी के ध्यान में क्यों नहीं आए। आखिर ये काम जो हम आज कर रहे हैं गुजरात जैसा प्रदेश वाईब्रेन्ट गुजरात के नाम से वर्ष 2003 से कर रहा है। बहुत सारे प्रदेश चाहे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है अथवा आंध्रप्रदेश है इन लोगों ने ऐसे कार्यक्रम कई-कई वर्षों से शुरू कर रखे हैं। हरियाणा ने पहली बार ऐसे कार्यक्रम किये है। जो बड़ी हैरानी की बात है वह यह है कि पिछली सरकार ने इस काम को करने के लिए ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बनाई। मेरे ध्यान में जो आता है पिछली सरकारों के समय जो पॉलिसी थी उसमें वन-टू-वन आओ और अपनी बात करो, हिसाब किताब करो और जाओ। इस प्रकार की पॉलिसिज पिछली सरकारों की थी। बडे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि उनकी पॉलिसी में

[श्री मनोहर लाल]

भ्रष्टाचार के जन्म के अलावा कुछ नहीं था। उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं जीरो टॉलरैंस फॉर करप्शन की बात आते ही हमने कहा कि हमारी मंशा साफ है कि यह जो बड़ा-बड़ा करप्शन है पहले उसको रोकना है और इस बड़े करप्शन के रूकने के बाद स्वाभाविक है कि आज जो कहते हैं कि नीचे सब जगह ये करप्शन चलता है क्योंकि ऊपर भी चलता है लेकिन नीचे के आदमी को प्रेरणा तभी मिलती है जब यह करप्शन ऊपर होता है अगर ऊपर का करप्शन रुकेगा तो नीचे अपने आप रुक जाएगा। अगर नहीं रूकेगा तो निश्चित रूप से उसके लिए कठोरता भी की जायेगी। (इस समय मेजें थपथपाई गई) कल ही मुझे अम्बाला से एक जानकारी मिली की म्युनिसिपल कारपोरेशन के एक ट्रक में कबाड़ के साथ फ्रैश पाईप्स, सबमर्सीबल मोटरें आदि डालकर ले जाया जा रहा था। जानकारी मिलते ही तुरन्त इस बारे में वहां के डी.सी. को बताया गया। डी.सी. ने कहा कि मैं अपने तहसीलदार को भेजता हूँ। संयोग से उस दिन कमिश्नर भी छुट्टी पर थे। तहसीलदार और अन्य आफिसर्ज वहां पर गये और मौके पर जाकर छापा मारा गया और बात सही निकली और यह भी पता लगा कि केवल एक ट्रक ही नहीं पहले भी दो तीन ट्रक इस तरह के निकले हैं। इस संबंध में सैनिटेशन इंस्पेक्टर तथा ठेकेदार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमें जहां से भी जानकारियां मिले उन पर कार्यवाही करनी होंगी। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जानकारी जरूर देनी चाहिए और इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकेगा। मैं हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर सम्मिट की भी बात कर रहा था। इस सम्मिट में 13 केन्द्रीय मंत्रियों ने भाग लिया और अपने-अपने विभागों से संबंधित अनेक घोषणायें भी की। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, श्री वैंकेया नायडू जी ने घोषणा की कि हरियाणा प्रदेश के 18 शहरों को अमृत स्कीम के तहत धन मिलेगा, केन्द्रीय रेलवे मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने हरियाणा में रेल कोच फैक्ट्री लगाने की घोषणा की। यह कोच फैक्ट्री 120 एकड़ में स्थापित होगी। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार और रेलवे विभाग के साथ 50-50 रेशो के आधार पर एक एम.ओ.यू. साईन किया जायेगा। इस एम.ओ.यू. के आधार पर जो रेलवे स्टेशन बनाये जायेंगे उन रेलवे स्टेशनों पर रेलवे विभाग की बेहतर योजनाओं की झलक भी दिखाई देगी और हरियाणा सरकार के बेहतर योगदान व सोच की भी झलक साक्षात देखने को मिलेगी। इसी तरह से पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने पानीपत रिफाइनरी का विस्तार करके डाउनस्ट्रीम उद्योग लगाने की बात कही, केन्द्रीय मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह जी ने कहा कि न्यूक्लियर पॉवर प्लांट की स्थापना में 21,000 करोड़ रूपये का निवेश होगा, केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी ने हरियाणा में डिफैंस के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम स्थापित करने की बात कही। केन्द्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्रा जी ने देशभर में 15 टूल रूम स्थापित करने की श्रेणी में हरियाणा प्रदेश में भी एक टूल रूम स्थापित करने के लिए स्थान की डिमांड की है। अध्यक्ष महोदय, माननीय केन्द्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की झड़ी लगा दी है। हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल में 9 राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है (इस समय मेजें थपथपाई गई)। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या केवल मात्र 6 हुआ करती थी। इन 9 राष्ट्रीय राजमार्गो के बनने से अगले 2-3 वर्ष में प्रदेश में सड़कों की कोई कमी नहीं रहेगी। माननीय केन्द्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि जितने भी

नेशनल हाईवेज तथा स्टेट हाईवेज हैं उनके जितने भी अंडर ब्रिजेज और ओवर ब्रिजेज बनाने बाकी हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दीजिए हम उन्हें अपने पैसे से जल्द से जल्द बना देंगे। अत: स्टेट हाईवेज तथा नेशनल हाईवेज पर जहां कहीं किसी भी सड़क या फाटक पर अंडर ब्रिजेज या ओवर ब्रिजेज की आवश्यकता होगी वहां पर इनका निर्माण जल्द से जल्द करवाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्ज सम्मिट में 12 देशों ने भाग लिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कुछ अन्य बातों के साथ-साथ विशेषरूप से मैनुफैक्चरिंग के उपर प्रश्न चिन्ह लगाया था। जो हमारी एम.ओ.यू. की ब्रेक अप की टेबल है उसमें मैनुफक्चरिंग के छह अलग-अलग सैक्टर्ज हैं, इन सभी छह सैक्टर्ज को मैनुफैक्चरिंग कहा जाता है। यह जो 1.43 टोटल एम.ओ.यूज. की वैल्यू है यह तो small other manufacturing जिसका कोई बड़ा सैक्टर नहीं था, के लिए है। मैनुफैक्चरिंग के तहत Aerospace & Defence में 2 एम.ओ.यूज. साईन हुए, Agro, Food Processing & Allied Industries में 48 एम.ओ.यूज. साईन हुए, Pharmaceutical & Chemical Industry में 8 एम.ओ.यूज. साईन हुए, Auto, Auto Components & Light Engineering में 13 एम.ओ.यू. साईन हुए तथा Textile/ Apparel/ Knitting/ Embroidery में 15 एम.ओ.यूज. साईन हुए। इस प्रकार 10 प्रतिशत हिस्सा मैनुफैक्चरिंग के अधीन कवर होता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक एन.सी.आर. के बाहर का एरिया का सवाल है। एन.सी.आर. के बाहर 8 जिलो में (पंचकूला, यमुनानगर, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, और हिसार) एक लाख अट्ठाईस हजार करोड़ रूपये के एम.ओ.यूज. साईंन हुए थे। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये सारे एम.ओ.यूज. रीयल स्टेट या गुडगांव क्षेत्र के आस-पास के हुए हैं। ऐसे एरिया जो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दंगे की चपेट में थे, जहां पर कानून व्यवस्था के बारे में एक प्रश्नचिन्ह भी लगा हुआ था, उन तीन जिलों रोहतक, सोनीपत और झज्जर में भी बड़ी संख्या में एम.ओ.यूज. मंजूर हुए हैं। रीयल इस्टेट में चार लाख करोड़ रूपये की बजाय मात्र 1 लाख 6 हजार करोड़ रूपये के एम.ओ.यूज. मंजूर हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, एक विषय और उठाया है कि जिसका अपना मकान नहीं है उससे भी एम.ओ.यू. साईंन किया हुआ है। हमारा कहना है कि जब एम.ओ.यू. उसने मंजूर किया है और एम.ओ.यूज. के आधार पर यदि वह उसको रीयल इस्टेट में मैच्योर कर सकता है तो हमें क्या दिक्कत है। उसका लक्ष्य 45 हजार करोड़ रूपये का है। वह भी एम.ओ.यू. साईन अपनी किसी कम्पनी से करता होगा। वह डी.एल.एफ. के फ्लैट में रहता है या कहीं और रहता है, किसी के साथ उसका झगड़ा है या नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि उसने हमारे साथ एम.ओ.यू. साईंन किया है, वह मैच्योर होगा तो आगे जायेगा नहीं मैच्योर होगा तो वह अपने घर बैठेगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को एक बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था के संदर्भ को छोड़कर जिसको कहना चाहिए कि आरक्षण के दौरान कुछ उपद्रव हुए हैं, मैं यह नहीं कहता कि आरक्षण वाले सब लोगों ने ऐसा किया होगा लेकिन आरक्षण को आड़ बनाकर कुछ लोगों ने उपद्रव किए हैं और उन उपद्रवियों के कुछ कारण हो सकते हैं। बिहाइन्ड दि सीन उनकी कुछ मंशा हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, गत दिनों आरक्षण की आड़ लेकर कुछ लोगों ने उपद्रव व अराजकता फैलाकर सरकार को अपदस्थ करने की कुचेष्ठा की, ऐसे लोगों को यह जान लेना चाहिए कि वे इसमें कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हम प्रदेश की अढ़ाई करोड़ जनता द्वारा पूर्ण बहुमत के साथ चुनी गई सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता जिस पार्टी की सरकार चाहेगी उसी पार्टी की सरकार बनेगी।

[श्री मनोहर लाल]

(इस समय मेजें थपथपाई गई।) ऐसी मंशा के बारे में मैं बिल्कुल भी चिन्तित नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई परवाह है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में हुई घटनाओं से मुझे व्यक्तिगत रूप से आहत और पीड़ा पहुँची है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय भी इसी प्रकार का वातावरण बनाया गया था। मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री है यह बात सही है लेकिन आखिर एक व्यक्ति भी है। ऐसे मुद्दे सुनकर पीड़ा होती है कि वह 'पाकिस्तानी' है। मैं कहता हूँ कि आदमी को सोच समझकर बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जिस समय देश का विभाजन होकर दो टुकड़ों में बंट रहा था, जिस क्षेत्र में इस समाज के लोग थे, उनके मन में देश भक्ति की भावना थी, एक आस्था के प्रति उनका लगाव था। आस्था और देश भक्ति के कारण उन्होंने अपने घर-बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, खेती-बाड़ी छोड़ी, व्यापार छोड़ा और केवल तीन कपड़ों में वहां से चल दिए कि हमारा वतन तो भारतवर्ष है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) ऐसी टिप्पणियां सुनने पर व्यक्तिगत रूप से एक गंभीर चोट लगती है। इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करने वाले लोगों को मैं शातिर और शैतान कहूँगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों में ऐसी बातें फैलाकर भेदभाव पैदा करने जैसा घिनौना काम हम नहीं होने देंगे। यह प्रदेश अढ़ाई करोड़ लोगों का यानी की 60 लाख परिवारों का है। किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक जाति का नहीं है। हम सब हरियाणा के लोग एक हैं। कोई इसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको नहीं तोड़ने देंगे चाहे वह किसी भी प्रकार का भी प्रयत्न कर लें। हमने एक नारा भी दिया हुआ है कि 'हरियाणा एक, हरियाणवी एक'। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) इस हिसाब से हमें विचार करके आगे चलना चाहिए। यदि किसी को कोई गलतफहमी है तो वह अपने मन से निकाल दें। माननीय सदस्यों, हम एक बार नहीं सौ बार कहेंगे कि हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। अध्यक्ष महोदय व माननीय सभासदों, मैं जाट आरक्षण आंदोलन की चर्चा करना चाहूंगा। इस आंदोलन में आगजनी और लूटपाट जैसे अपराध हुए हैं। आरक्षण के संदर्भ में जिन लोगों ने आंदोलन आरम्भ किया था उन्होंने सरकार के सामने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब आंदोलन हमारे हाथ में नहीं रहा है। अब यह आंदोलन शरारती तत्वों के हाथों में आ गया है जिसे सिर्फ सरकार ही नियंत्रित कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि हम आंदोलनकारियों की तैयारी का सही अंदाजा नहीं लगा पाए हों लेकिन हमने इसे बेहतरीन ढंग से निपटाया है। इस आंदोलन को रोकने के लिए हमने आर्मी, पैरामिलिट्री फोसिर्ज और प्रदेश की सभी फोर्सिज को डिप्यूट किया। इसके साथ ही हमने मधुबन, सुनारिया और भौंडसी की रिजर्व फोर्सिज को तनावगस्त और संवेदनशील एरियाज में भेजा। उसके बाद तीन दिन के अंदर हम आंदोलन को नियंत्रित करने में कामयाब हो पाए। हमारी मंशा यह थी कि प्रदेश की जनता का जान-माल का नुक्सान न हो लेकिन जब उपद्रवी उग्र हो जाए तो उस समय पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सिज और आर्मी को अपनी और प्रदेशवासियों की जान-माल की रक्षा के लिए स्वयं निर्णय लेने होते हैं। हमें बड़ा दु:ख और खेद है कि इसी जद्दोजहद में तीस लोगों की जान चली गई लेकिन अगर हमने सूझ-बूझ और सही ढंग से आंदोलन को नहीं संभाला होता तो इससे भी अधिक जानें जा सकती थी। आंदोलन के दौरान लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गये थे। इससे जिस तरह का भयानक वातावरण झज्जर, रोहतक, मुरथल, सोनीपत, महम, कलानौर और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में बना उससे प्रदेश में भारी तनाव पैदा हो गया। इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हमें कई स्थानों पर बल प्रयोग करना पड़ा और गोली चलानी पड़ी। इस कार्रवाई में कुछ दोषी मारे गए और उनके साथ कुछ निर्दोष लोगों को

भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हरियाणा का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस दु:खद घटना से दुखी न हुआ हो। हमें हर दुखद घटना से बाहर निकलकर संभलना होता है। विश्व में ऐसी अनेक बड़ी-बड़ी घटनाएं होती रही हैं। यह शासन-प्रशासन का काम होता है कि वह इन दुखद घटनाओं से जनता को संभलने में मदद करे। वह काम हमने किया है। इस आंदोलन के समाप्त होने पर हमने आर्मी की कार्रवाई में जो निर्दोष लोग मारे गए थे उनके लिए 10-10 लाख रूपये मुआवजा राशि और एक-एक नौकरी की घोषणा की है। इसके साथ ही जिन लोगों का माली नुक्सान हुआ था हमने उनका असेसमैंट कराकर मुआवजा देना शुरू कर दिया है। हमने यह मुआवजा छोटे दुकानदारों से देना शुरू किया है। हमने जिन लोगों को 10 हजार रूपये मुआवजा राशि देनी थी सर्वप्रथम उनको यह मुआवजा राशि वितरित की उसके बाद 50 हजार रूपये फिर एक लाख रूपये आज की डेट में जिसके 20 लाख रूपये थे वह हम उन्हें दे चुके हैं। इस समय मेरे पास 17 तारीख तक की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार हमने 2191 लोगों का क्लेम प्राप्त हुआ है जिसमें 1789 प्रोपर्टीज डैमेज हुई थी। हम 17 तारीख तक 32 करोड़ रूपये मुआवजा राशि दे चुके हैं। आज 18 तारीख है इसलिए आज और भी राशि वितरित की गई होगी क्योंकि मुआवजा देने की योजना इससे ज्यादा ही बनी है। जिन लोगों ने बीमा करवाया था हमने उन बीमा कम्पनीज के रीजनल डायरैक्टर्स से बात करके उनको 15 दिन के अंदर-अंदर मुआवजा देने के लिए कह दिया था। इसके साथ ही हमने इन निर्दोष लोगों के बिजली के चार महीने के बिल माफ कर दिए हैं। जिन लोगों के पुराने लोन थे हमने उनका तीन महीने का इंट्रस्ट भी माफ कर दिया है। अब हम एक वैट की स्कीम भी लाने वाले हैं और यह एक प्रशासनिक काम है। हमने इन लोगों के एक साल के हाउस टैक्स भी माफ किए हैं। इस प्रकार से जितनी भी सहायता उनको हम दे सकते हैं हमने दी हैं। जिसका घर और कारोबार खत्म हो गया वह तुरंत अपना कारोबार नहीं बना सकता। जो रोज कमाने खाने वाला है अगर उसको ऐसी सहायता मिल जाए और वह 3 महीने में दोबारा अपने कारोबार को एस्टैब्लिश कर सके, ऐसे प्रबंध हमने किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे बढ़ने के लिए हम सबको मिलकर इस वातावरण को ठीक करना चाहिए इसलिए इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि-

एक दरख्त मोहब्बत का ऐसा लगाया जाए,
जिसका हमसाये के घर में भी साया जाए।

मित्रों, ऐसा काम हमको करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कुछ और विषय प्रश्नकाल के समय में भी और कुछ अन्य समय में भी इस चर्चा के दौरान आए । बिजली विभाग की ओर से पिछले डेढ़ साल के अंदर जो प्रयत्न किए गए उनमें दो तीन चीजों में हमें सफलता मिली है। गेहूं की बिजाई के समय पिछले साल कठिनाई आई क्योंकि बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक नही था, हम बिजली देना चाहते थे तो भी बिजली पहुंच नहीं पाती थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ऐग्रीकल्चर सैक्टर में किसान को गेहूं की बिजाई के समय पूरी बिजली जितनी चाहिए थी उतनी बिजली मिली है और कहीं से इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई। हमने बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है। 155 सब स्टेशंज मजबूत करवाए गए हैं तथा आगे भी इस क्षेत्र में कोई कठिनाई न आए ऐसा हम ध्यान रखेंगे। शहरों के बिजली के लौसिज के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा। अलग अलग क्षेत्रों से जो आंकड़े मिले हैं उनमें बिजली के लोसिज 4 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक कम हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने "म्हारा गांव जगमग गांव" स्कीम चलाई है। इस

[श्री मनोहर लाल]

स्कीम के तहत 1000 गांव यानि 1/6 of the Haryana State ऐसे हो गए हैं जहां हमने 12 घंटे की बजाय 15 घंटे बिजली देना शुरू कर दिया है। इस स्कीम के तहत 500 फीडर्ज इस वर्ष नए जोड़ दिए जाएंगे जिसके अंदर लगभग 3000 गांव आ जाएंगें जहां 12 घंटे की बजाय 15 घंटे बिजली दी जाएगी। इन गांवों में जो लोग अपने मीटर घर से बाहर लगा लेंगे तो वहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा और तारें भी बदल दी जाएंगी और वहां 15 घंटे की बजाय 18 घंटे बिजली दी जाएगी। इसके साथ यदि वे लोग पूरा बिल देना शुरू कर देते हैं तो उनको 18 की बजाय 21 घंटे बिजली देना शुरू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में यदि पूरी बिलिंग, लाइटिंग, मीटर तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर होता है तो हम 24 घंटे तक बिजली देने की तरफ भी जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो विरोध स्वर आता है तो उनके इस स्वर को मिटाने के लिए उनमें कम्पीटिशन पैदा करने से ये चीजें शायद ठीक हो सकती हैं तथा रूरल डॉमैस्टिक में हम 24 घंटे तक बिजली दे पाएंगे। अध्यक्ष महोदय, हम एक और स्कीम ला रहे हैं। पावर सैक्टर को ठीक करने के लिए केन्द्र सरकार ने "उदय" नाम की एक स्कीम पास की है। अभी तक जो बिजली का घाटा है वह इस वर्ष अनुमानित साढ़े 34 हजार करोड़ रूपये हो जाने वाला है। इस साढ़े 34 हजार करोड़ में से 75 प्रतिशत, जिसमें से 50 प्रतिशत इस वर्ष और 25 प्रतिशत अगले वर्ष यानि टोटल 75 परसैंट कर्जा स्टेट गवर्नमैंट ऑन कर लेगी यानि वह स्टेट गवर्नमैंट का होगा न कि पावर डिपार्टमैंट का। यह लोन स्टेट गवर्नमैंट के ऑन करने से 4 परसैंट इंट्रस्ट की बचत होगी क्योंकि बिजली विभाग को 12 से साढ़े 12 परसैंट रेट ऑफ इं ट्रस्ट पर लोन मिलता है। सरकार यदि लोन लेती है तो उसको 8 से साढ़े 8 परसैंट इंट्रस्ट पर लोन मिलता है और इस प्रकार सरकार द्वारा यह लोन ऑन करने पर 4 परसैंट की बचत होगी। बाकी का 25 परसैंट अभी पावर डिपार्टमैंट के पास रहेगा। आगे भी पावर डिपार्टमैंट घाटे में न चले इसके लिए बहुत सी स्कीमें चलाई गई हैं ताकि जो घाटा प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, एक विषय पिछले सत्र में भी आया था और उस पर कालिंग अटैंशन मोशन आया था। वह विषय था धान की प्रोक्योरमैंट का। 1509 धान प्रोक्योर किया गया था। धान की प्रोक्योरमैंट पर विषय था कि चूंकि केन्द्र सरकार से बातचीत करने के बाद उनसे अनुमति ली गई थी और कहा गया था कि 1509 धान को भी इसमें ले लिया जाए क्योंकि किसान की फसल का मंडी में कम दाम पर खरीद हो रही थी। केन्द्र सरकार से अनुमति लेने के बाद इस धान को A ग्रेड में शामिल करवाकर 1450 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रिक्योरमैंट की गई।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो हाऊस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाऊस का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसमें जो नमी होती है उस नमी के कारण किसानों और आड़तियों में इस बार नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से समझौता चला आ रहा है। हमारे में से भी कई लोग आड़ती होंगे या उनके संपर्क में रहते होंगे। चाहे किसी भी दल के लोग हैं। हम से से कई लोग किसान भी हैं और सबको मालूम है कि किसान जीरी को सुखाकर नहीं लाता उसमें कुछ नमी रहती है। इसी वजह से आड़ती और किसान आपसी समझौते में कुछ कटौती करते हैं। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होता। सरकार 1450 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जीरी की खरीद करती है और इतने पैसे ही पे करती है। उसके बदले में 100 किलो जीरी पर 67 किलो चावल वापिस लेती है। सरकार 1450 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदती है और यदि नमी के कारण बाद में वजन घटता है तो उसकी भरपाई मिलर अपने आप करता है। सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है उसका यह एक निश्चित रेशो है। उसी निश्चित रेशो के हिसाब से ही चावल वापिस लिया जाता है। विषय आया था कि 1450 रूपये प्रति क्विंटल जीरी खरीदी गई बासमती जो जीरी थी इसको कम भाव में ले लिया गया। इसका तो रेट ज्यादा था। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस समय सदन में जिस प्रकार का वातावरण था उसको लेकर हमने फीजिकल वैरीफिकेशन करवाई। फीजिकल वैरीफिकेशन के बाद जो 1,60,000 मिट्रिक टन 1509 बासमती खरीदा था उसको अलग करवाया। अलग करवाकर हमने कहा कि यदि इसका रेट ज्यादा है तो इसे बाजार में बेचना चाहिए और इससे जो लाभ होगा उस पर विचार बाद में करेंगे कि किसान को देना है या सरकार को अपने पास रखना है। उस 1,57,000 मीट्रिक टन धान के सरकार ने टैण्डर आक्शन के लिए निकाले। 1450 रूपये प्रति क्विंटल में खर्चा मिलाकर 1614 रूपये प्रति क्विंटल 1509 बासमती पड़ी थी। वैसे तो खर्चा मिलाकर इसकी खरीद 1700 रूपये प्रति क्विंटल पड़ती है। सरकार ने टैण्डर में उसका रिजर्व प्राईस 1614 रूपये ही रखा था लेकिन उस 1614 रूपये प्रति क्विंटल पर भी खरीदने वाला ओपन मार्केट में कोई नहीं मिला। क्योंकि खर्चे सहित मण्डियों में आज भी 1509 बासमती 1550 रूपये प्रति क्विंटल में मिल रहा है। जब 1550 रूपये प्रति क्विंटल मण्डी में 1509 बासमती मिलती है तो 1614 रूपये में कौन खरीदेगा जिसमें हमारा घाटा भी हो रहा है। 1614 रूपये प्रति क्विंटल के रेट में वह बिकेगा नहीं। अगर उसको घाटे में बेचना है तो आज भी 1550 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचा जा सकता है। क्योंकि मार्केट का रेट 1550 रूपये प्रति क्विंटल है यह मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बता रहा हूं। हमारे पास जीरी है अगर उसका मिलर से चावल बनवाकर लेना है तो सभी को मालूम है कि 1509 बासमती के चावल का क्या रेट है। मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से आहवान करता हूं यदि कोई 1614 रूपये प्रति क्विंटल में उस जीरी का खरीददार है तो सरकार देने के लिए तैयार है। उसके बाद खरीददार चाहे चावल बनवाये और उस चावल को वह महंगा बेचे या सस्ता बेचे। यदि सरकार उसको घाटे में नहीं बेचना चाहती है तो वह धान मिलर के पास पहुंचा हुआ है उसको मिलर से लेकर एफ.सी.आई. को दिया जा सकता है। मैंने जानकर सदन में यह विषय इसलिए रखा क्योंकि यदि सदन की बिना जानकारी के सरकार कोई ऐसा कार्य करती है तो कल को यह इशू फिर उठेगा। कहने वाले और हिसाब लगाने वाले हमारे एक पूर्व वित्तमंत्री हैं जो हिसाब लगाते हैं कि इतने

[श्री मनोहर लाल]

रूपये किलो का रेट था और इतने हजार करोड़ रूपये का घोटाला हुआ है। वे हिसाब लगाते रहते हैं। इसलिए उस हिसाब को आज मैं सबके सामने रख रहा हूं। यदि किसी की 1614 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 1509 बासमती को खरीदने की ऑफर हो तो हमारे मंत्री जी को एक-दो दिन में दे दें। सरकार इस रेट पर देने के लिए तैयार है। अन्यथा उन मिलर्ज को यह जीरी देकर जो 67 प्रतिशत के हिसाब से चावल लेने की शर्त तय हुई है उसके हिसाब से चावल उनसे लिया जा सकता है। अगले वर्ष क्या होगा इस पर उसी समय विचार किया जायेगा। मैंने यह विषय यहां पर इसलिए रखा है कि अगर सदन में किसी माननीय साथी को इस विषय के बारे में अपने विचार रखने हों तो वह रख सकता है नहीं तो फिर इसको वहीं मिलर्ज़ को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपना रिप्लाई कंटीन्यू करें क्योंकि इस विषय पर कोई भी मैम्बर अपने विचार नहीं रखना चाहता।

श्री मनोहर लाल : अब मैं अंतिम दो बातें यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि सभी जानते हैं हमारी सरकार ने पंचायत के चुनाव करवाये। इसके ऊपर भी सभी जगह बहुत हो-हल्ला हुआ। कई प्रकार की आलोचनायें भी जिन्हें हमें सुनना पड़ा। पता नहीं क्या-क्या कहा गया कि यह हो जायेगा और वह हो जायेगा। यहां तक भी कहा गया कि हरियाणा में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आगे नहीं आयेगा और इससे इतने-इतने लोगों का चुनाव लड़ने का अधिकार छिन जायेगा। यह विषय इन सारे के सारे विवादों से निपटते हुए पहले माननीय हाई कोर्ट और बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिसकस हुआ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अंत में यह विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर 45 दिन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के इस फैसले पर अपनी मोहर लगाई और कहा कि हरियाणा सरकार का यह प्रस्ताव पूरी तरह से ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि इससे और आगे जाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा में ही नहीं अपितु देश के सभी राज्यों को भी इस एक्ट को लागू करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि नये पंचायत एक्ट के अंतर्गत चुनाव हुए और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि ये चुनाव अब तक के सबसे ज्यादा सक्सैसफुल चुनाव साबित हुए। इन चुनावों में एवर-हाईयेस्ट नम्बर में निर्विरोध प्रत्याशी चुने गये। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इन चुनावों में अच्छे पढ़े-लिखे लोगों का चुनाव हुआ। बहुत से नौजवानों का चुनाव हुआ, बहुत सी महिलाओं का चुनाव हुआ और बहुत सी लड़कियों का भी चुनाव हुआ। बहुत से ऐसे लोग भी चुनाव जीतकर आये हैं जिन्होंने अलग-अलग विषयों में डिग्री प्राप्त की हुई है। जिला परिषद् में, पंचायत समिति में और पंच व सरपंच बनने में इस प्रकार के लोग आगे आये हैं। इस प्रकार से कुला-मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ है जो कि आने वाले समय में एतिहासिक साबित होगा। इसके बहुत से लाभ आने वाले समय में परिलक्षित होंगे और आने वाले समय में बड़े क्रांतिकारी परिणाम सामने आयेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता से इस बात को कह रहा हूं कि इसका भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलने के कारण से अभी-अभी जो जिला परिषद्ों और पंचायत समितियों के चुनाव हो रहे हैं। अभी तक नौ जिला परिषद्ों के चुनाव परिणाम आये हैं और ये 9 के 9 ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आये हैं। कहीं-कहीं पर वाईस

चेयरमैन निर्दलीय या दूसरे दल का बना है लेकिन चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के ही बने हैं। इसी प्रकार से 66 पंचायत समितियों में से 64 पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आये हैं। ये भले ही निर्दलीय लड़े हों लेकिन आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाईन की है। भारतीय जनता पार्टी ज्वाईन करने के बाद वे हमारे लोगों के सम्पर्क में आये हैं। इनमें से कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं और कुछ नये भी हैं। जिन लोगों ने हमारे इस आह्वान के प्रति अपनी सकारात्मक दृष्टि दिखाई वे इससे प्रभावित हुए। वही आज हमारे पास आ रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है और मेरे लिए खुशी देने वाला समाचार है। इसी प्रकार से यहा पर आर.ओ.बीज़. और आर.यू.बीज़. का विषय कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया। इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि आर.ओ.बीज़. और आर.यू.बीज़. का कुछ आंकड़ा अभी मेरे पास आया है उसके मुताबिक मैं यह बताना चाहूंगा कि 01 नवम्बर, 1966 से 01 नवम्बर, 2014 तक केवल 67 आर.ओ.बीज़. और आर.यू.बीज़. का निर्माण हरियाणा प्रदेश में हुआ है इसके विपरीत पिछले केवल मात्र 16 महीनों में 15 आर.ओ.बीज़. और आर.यू.बीज़. का निर्माण हमारी सरकार द्वारा करवाया गया है। इसी प्रकार से 20 आर.ओ.बीज़. और आर.यू.बीज़. के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। ऐसे ही आने वाले वर्ष के लिए 39 आर.ओ.बीज़. और आर.यू.बीज़. के निर्माण का नया कार्य आरम्भ करवाया जाना प्रस्तावित है जिसके ऊपर 1400 करोड़ रूपये की लागत आने की सम्भावना है। इस प्रकार से 01 नवम्बर, 1966 से 01 नवम्बर, 2014 तक 48 वर्षों में केवल 67 आर.ओ.बीज़. और आर.यू.बीज़. का निर्माण हरियाणा प्रदेश में हुआ जबकि केवल दो सालों में 74 आर.ओ.बीज़. और आर.यू.बीज़. का निर्माण कार्य हरियाणा प्रदेश में कम्पलीट हो जायेगा। माननीय विधायक मित्रगण, हमारी सरकार के समय में हरियाणा में विकास और काम की जो गति है वह इन सब बातों से हमें पता चलती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि भले ही हम लोग अलग-अलग दलों से सम्बन्ध रखते होंगे। इसीलिए हम एक-दूसरे की रचनात्मक आलोचना कर सकते हैं। हम एक-दूसरे के विरोध में भी खड़े हो सकते हैं लेकिन मैं यह बात विशेष रूप से ज़ोर देकर कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के समुचित और सर्वांगीण विकास के मामले में हम सभी को एक साथ मिलकर मज़बूती के साथ आगे बढ़ना है। इसके साथ ही मैं एक शेयर आप सभी के लिए अर्ज़ करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि :-

गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर,
सुबह ज़रूर आयेगी, सुबह का इंतज़ार कर।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है-

"कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाये :-

"कि इस सत्र में इक्ट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 14 मार्च, 2016 को 02.00 बजे मध्याह्न-पश्चात्' सदन में देने की कृपा की है।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

वर्ष 2015-2016 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : मैं वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : अब श्री मूल चंद शर्मा, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति वर्ष 2015-16 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson, Estimates Committee (Shri Mool Chand Sharma) : Speaker Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates 2015-16 (Second Installment).

वर्ष 2015-2016 के अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2015-16 के अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्ज (संख्या 2 से 4, 8, 17, 19 एवं 20, 22, 27, 33, 36, 40 तथा 45) एक साथ पढ़ी तथा पेश की समझी जायें। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 3,36,25,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद् के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 17,94,13,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 3-सामान्य प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 17,66,57,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 4-राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 257,63,35,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 8-भवन तथा सड़कें के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 17-रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 150,41,68,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 19-अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 1,65,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 20-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,65,74,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 27-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 11,56,00,000 से अधिक न हो, मांग सं. 33-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 112,33,00,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 36-गृह के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4106,90,03,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1297,50,00,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 40-उर्जा तथा विधुत के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 12141,35,59,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 45-राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(कोई सदस्य बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ)

श्री अध्यक्ष : अब डिमांड्स मतदान के लिए रखी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है:- मांग संख्या 2 से 4

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 3,36,25,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

[श्री अध्यक्ष]

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 17,94,13,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 3-सामान्य प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 17,66,57,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 4-राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 8

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :- कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 257,63,35,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 8-भवन तथा सड़कें के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 17

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :- कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 17-रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 19

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :- कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 150,41,68,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 19-अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 20

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :- कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 1,65,00,00,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 20-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 22

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :- कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,65,74,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 22-भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 27

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :- कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 27-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 33

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :- कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 11,56,00,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 33-सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 36

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :- कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 112,33,00,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 36-गृह के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 40

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :- कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1106,90,03,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1297,50,00,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 40-उर्जा तथा विधुत के संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 45

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है :- कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 12141,35,59,000 रुपये से अधिक न हो, मांग सं. 45-राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां के

संबंध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब यह सदन सोमवार 21 मार्च, 2016, दोपहर 02:00 बजे तक स्थगित किया जाता है।

*14:41 बजे (तत्पश्चात सदन की बैठक सोमवार 21 मार्च, 2016 दोपहर 02:00 बजे तक * स्थगित हुई।)

54352—H.V.S.—H.G.P.,Chd.

© 2016

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and printed by the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh.